सूर्योदय 5:28 सूर्यास्त 7:27

आज का तापमान

शिमला	17.2 न्यू	26.0 अधि
धर्मशाला	18.8 न्यू	31.0 अधि

बाजार

सेंसेक्स	77,054
निफ्टी	24,052
सोना 1,42,000	चांदी 2,19,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | बुधवार, 15 जुलाई 2026 | 31 आषाढ़, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 81, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई जमानत की गुहार

एजेंसी, नई दिल्ली। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आसाराम ने मेडिकल आधार पर जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनकी याचिका पर 17 जुलाई को सुनवाई होगी। कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार करते हुए मामले को सूचीबद्ध कर दिया है। आसाराम के वकील डीएस नायडू ने बताया कि 8 जुलाई को उन्हें आंतरिक रक्तस्राव के बाद एम्स जोधपुर में भर्ती कराया गया था। उन्होंने अदालत को बताया कि आसाराम की हालत गंभीर है और उन्हें रक्त चढ़ाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केवल सुनवाई की तारीख तय की है। जमानत देने या याचिका के गुण-दोष पर फैसला सुनवाई के बाद होगा।

जून में थोक महंगाई बढ़कर 9.87 फीसदी पर पहुंची

एजेंसी, नई दिल्ली। खाद्य व गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते जून में थोक महंगाई दर बढ़कर 9.87 फीसदी हो गई है। मई में यह दर 9.68 फीसदी थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई में खनिज तेल, खाद्य वस्तुओं, मूल धातुओं और रासायनिक उत्पादों की कीमतों का असर रहा। आंकड़ों के मुताबिक जून में खाद्य वस्तुओं की थोक महंगाई बढ़कर 5.49 फीसदी रही, जबकि मई में यह 3.60 फीसदी थी। ईंधन एवं बिजली श्रेणी में महंगाई 27.41 फीसदी दर्ज की गई। विनिर्मित उत्पादों की थोक महंगाई जून में 7.48 फीसदी पर स्थिर रही। वहीं, खुदरा महंगाई भी जून में बढ़कर 4.38 फीसदी पर पहुंच गई है।

जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े पांच संदिग्ध हिरासत में

एजेंसी, अहमदाबाद। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से कथित संबंधों की जांच के तहत पाटन जिले के सिद्धपुर शहर से पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सभी संदिग्धों को पूछताछ के लिए अहमदाबाद लाया गया है। एटीएस अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई खुफिया सूचना के आधार पर की गई। इससे पहले गुजरात और मध्य प्रदेश एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आठ संदिग्धों को पकड़ा गया था। उसी जांच को आगे बढ़ाते हुए सिद्धपुर में यह कार्रवाई की गई। जांच एजेंसियां हिरासत में लिए गए लोगों के आतंकी नेटवर्क से संबंध, गतिविधियों और संभावित भूमिका की जांच कर रही हैं। अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की जानकारी साझा की जाएगी।

हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

एजेंसी, श्रीनगर। पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच के सिलसिले में एक विशेष एनआईए अदालत ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 8 जुलाई को पारित किया। इससे दो दिन पहले ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में सईद के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। सईद को भारत और अमेरिका दोनों ने वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रखा है। उसे 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड भी माना जाता है।

धार भोजशाला के पास हर शुक्रवार होगी नमाज

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- मुस्लिम पक्ष को अलग जगह दें, एएसआई परिसर से छेड़छाड़ न करें

एजेंसी, धार। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को धार भोजशाला मंदिर के पास नमाज के लिए कोई खुला स्थान देने को कहा है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज के लिए यह जगह दी जाए।

अदालत ने यह भी कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बिना कोर्ट की मंजूरी परिसर में किसी भी तरह का बदलाव न करे। सुप्रीम कोर्ट एमपी हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें परिसर को मंदिर करार दिया गया है। सुनवाई के बाद भोजशाला संयोजक गोपाल शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार भोजशाला में नियमित पूजा-अर्चना जारी रहेगी। वहीं, तय जगह पर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को लेकर मुस्लिम पक्षों की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। इन याचिकाओं में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर माना गया था और परिसर में नमाज अदा करने पर रोक लगा दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। यानी पहले जैसी व्यवस्था बहाल नहीं होगी, जिसके तहत शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय को नमाज और निर्धारित दिनों में हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों से जवाब मांगा है। अब इस विवाद पर आगे की सुनवाई बाद में होगी।

दिव्यांगों पर टिप्पणी- कॉमेडियन समय रैना पर 3 लाख रुपए जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्टैंड-अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया और आशीष चंचलानी पर 3 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। अदालत ने दिव्यांगों पर विवादित टिप्पणी के केस में यह आदेश दिया है। इसकी सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जॉयमाल्या बागची और वी मोहन की बेंच ने की। बेंच ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद रैना ने अपने शो पर किसी दिव्यांग को नहीं बुलाया। अदालत क्योर एसएमए इंडिया फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रैना के शो पर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के खर्च पर असंवेदनशील टिप्पणी करने और दिव्यांगों का मजाक उड़ाने का आरोप है। संस्था की ओर से वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि रैना ने अपने किसी भी शो में शामिल होने के लिए उनसे या किसी अन्य दिव्यांगजन से कभी संपर्क नहीं किया। इसके बाद अदालत ने जुर्माना लगाया।

शाहरुख खान को राहत, 'मन्नत' के रेनोवेशन का रास्ता साफ

उच्चतम न्यायालय ने सुपरस्टार शाहरुख खान के मुंबई के बांद्रा में स्थित बंगले 'मन्नत' के रेनोवेशन के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने शाहरुख खान के बंगले के रेनोवेशन का रास्ता साफ कर दिया। सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता व मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दाउंडकर की मंशा पर संदेह जताया। याचिकाकर्ता का कहना था कि मन्नत में दो और मंजिलें जोड़ने के लिए पर्यावरण से जुड़ी जरूरी मंजूरी नहीं ली गई है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भी इस पहलू को अनदेखा किया। ये अनदेखी इसलिए की गई, क्योंकि शाहरुख खान बड़े फिल्म स्टार हैं। उनके लिए अलग कानून नहीं हो सकता। याचिकाकर्ता ने एनजीटी की पुणे स्थित पश्चिमी जोन के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि कोर्ट किसी के फिल्म स्टार होने से प्रभावित नहीं है।

नई तीन भाषा नीति पर केंद्र और सीबीएसई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की नई तीन भाषा नीति को चुनौती देने वाली दो नई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 18 जून को फ्रेंड्स ऑफ पीपल फॉर एक्टिव डेमोक्रेसी नामक एनजीओ की ऐसी ही याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी किया था। 27 मई को छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और सीबीएसई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में कहा गया है कि सीबीएसई की नई तीन भाषा नीति में नौवीं कक्षा से दो और भाषाओं को पढ़ना अनिवार्य बनाया गया है। इन तीन भाषाओं में दो भारतीय भाषाओं का अध्ययन जरुरी है। याचिका में कहा गया है कि अचानक कक्षा नौ के छात्रों को दो अतिरिक्त भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करना उनकी दसवीं बोर्ड की तैयारी प्रभावित कर सकता है।

भारत बोला- होर्मुज में जहाजों को निशाना बनाना बंद हो, ईरानी दूत को तलब किया

- ईरानी हमले में 1 भारतीय की मौत, 10 हुए घायल
- भारत से जुड़े 11 जहाज फारस की खाड़ी में फंसे

एजेंसी, वॉशिंगटन। भारत ने होर्मुज स्ट्रेट में मंगलवार सुबह दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास के उप प्रमुख (डिप्टी चीफ ऑफ मिशन) को तलब कर भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराया। मंत्रालय ने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर इस तरह के हमले तुरंत बंद होने चाहिए।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, हमले का शिकार बने दोनों जहाजों पर कुल 30 भारतीय नाविक सवार थे। इनमें एक भारतीय की मौत हो गई, जबकि 10 घायल हुए हैं। भारत ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। भारत ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव चिंता का विषय है। उसने सभी पक्षों से हिंसा रोकने, बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और व्यापार हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

ईरान की संसद ने अमेरिका के साथ बातचीत का खुलकर विरोध करने वाले दो नेताओं को उनके पदों से हटा दिया है।

महमूद नबावियन को सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रथम उपाध्यक्ष, जबकि इब्राहिम रेजाई को प्रवक्ता पद से हटाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति ईरान की संसद की एक स्थायी संसदीय समिति है। यह देश की सुरक्षा, रक्षा, विदेश नीति, सीमा सुरक्षा और परमाणु कार्यक्रम जैसे अहम मुद्दों पर काम करती है और इनकी समीक्षा करती है। ईरान में जंग शुरू होने के बाद पहली बार संसद का सत्र मंगलवार को शुरू हुआ, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। होर्मुज स्ट्रेट में जारी तनाव के बीच भारत से जुड़े 11 जहाज और 148 भारतीय नाविक फिलहाल फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। ये सभी जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं।

सीएम रेखा ने किया कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप के मैस्कॉट का अनावरण

27 जुलाई से दिल्ली में खेलों का महाकुंभ

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक मैस्कॉट 'मयूर' का अनावरण किया। राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित यह शुभंकर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऊर्जा और विविधता का प्रतीक है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 'मयूर' आत्मविश्वास, उत्कृष्टता, दृढ़ संकल्प और खेल भावना का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में मोर गर्व, ऊर्जा और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, जो इस अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन की भावना को दर्शाता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन 27 जुलाई से 2 अगस्त तक दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया जाएगा। प्रतियोगिता में 25 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह आयोजन दिल्लीवासियों के लिए गर्व का अवसर है। इसके माध्यम से पूरी दुनिया दिल्ली की खेल भावना, बेहतर आयोजन क्षमता और अतिथि सत्कार की परंपरा से परिचित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार राजधानी में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद सहित टेबल टेनिस फेडरेशन के पदाधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 सफलतापूर्वक आयोजित होगी और भारत की खेल प्रतिभा को वैश्विक मंच पर नई पहचान मिलेगी।

चारा घोटाला: लालू यादव को 'सुप्रीम' राहत, जमानत रद्द करने से इनकार

एजेंसी, पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख व पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने फिलहाल उनकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने की सीबीआई की मांग भी स्वीकार नहीं की, जिसमें लालू को जमानत दी थी। वर्तमान स्थिति में हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सीबीआई ने जमानत रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने तर्क दिया कि सजा निलंबित करने का आदेश उचित आधार पर नहीं दिया गया।

हरियाणा में 20 करोड़ के राज्य अनुसंधान कोष को मंजूरी

शोध का लाभ किसानों, उद्योगों और समाज तक पहुंचना चाहिए: सीएम सैनी

एजेंसी, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिविल सचिवालय में हरियाणा विजन-2047 को लेकर उच्चतर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने हरियाणा के नवाचार-आधारित परिवर्तन को गति देने के लिए 20 करोड़ रुपए के 'हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष' को मंजूरी दी।

इसके तहत प्रदेश के 27 उच्च शिक्षा संस्थानों की 90 अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपना वादा निभाते हुए प्रदेश में 20 किलोमीटर की परिधि में छात्राओं के लिए कॉलेज की स्थापना की है, जिससे छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में सुविधा हो रही है। सैनी ने कहा कि 'हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष' विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें राज्य की जमीनी समस्याओं के समाधान केंद्रों में बदलेगा। ये सभी 90 परियोजनाएं कृषि, भूजल संरक्षण, जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ग्रामीण विकास, औद्योगिक नवाचार व समावेशी शिक्षा जैसे हरियाणा के विशिष्ट विषयों पर केंद्रित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसंधान केवल प्रकाशनों और प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका सीधा लाभ हमारे किसानों, उद्योगों और स्थानीय समुदायों को मिलना चाहिए। अकादमिक ज्ञान जब व्यावहारिक तकनीकों, पेटेंटों, स्टार्टअप्स और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं में बदलेगा, तभी हरियाणा के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।

मुख्यमंत्री धामी ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण व हरित उत्तराखंड का दिया संदेश

एजेंसी, पौड़ी गढ़वाल। हरेला पर्व के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विकासखंड स्थित मालाग्राम पहुंचकर पौधरोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित उत्तराखंड का संदेश दिया।

इस दौरान उन्होंने 'श्री धन्वंतरि धाम हर्बल वर्ल्ड हिमालय' का विस्तृत भ्रमण कर वहां संरक्षित दुर्लभ औषधीय वनस्पतियों, अनुसंधान गतिविधियों तथा आयुर्वेद आधारित नवाचारों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने परिसर स्थित ध्यान कुटी का भी निरीक्षण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भ्रमण के दौरान उत्तराखंड की समृद्ध जैव विविधता, हिमालयी औषधीय वनस्पतियों और पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान के संरक्षण एवं संवर्धन पर विशेष फोकस किया। उन्होंने कहा कि राज्य की यह प्राकृतिक धरोहर पूरे विश्व के लिए अमूल्य है और इसका संरक्षण और वैज्ञानिक शोध वर्तमान समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में किए जा रहे प्रयास पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा देने के साथ-साथ औषधीय पौधों के संवर्धन, आयुर्वेद आधारित अनुसंधान, हर्बल पर्यटन तथा स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार और आजीविका के नए अवसर भी सृजित करेंगे।

पंजाब में निवेश का यह सही समय : सीएम मान

मोहाली को बनाएंगे सिलिकॉन वैली; इसी माह आएगी एक और स्टील कंपनी

एजेंसी, चंडीगढ़। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली में कहा कि राज्य में निवेश करने का यह उपयुक्त समय है। सरकार ने निवेशकों के लिए समयबद्ध सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जिससे सभी आवश्यक मंजूरियां तय समय में मिलती हैं। उन्होंने दावा किया कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के मामले में पंजाब देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

सीएम ने कहा कि मोहाली देश की सिलिकॉन वैली बनने की ओर बढ़ रहा है। मोहाली अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से पांच मिनट के दायरे में उद्योगों के लिए जरूरी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अलग विभाग बनाया है। उन्होंने दावा किया कि अब तक पंजाब में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिससे 5 लाख रोजगार मिला हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के पास 6 एयरपोर्ट हैं, जिनमें 2 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट शामिल हैं। रेलवे कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि पंजाब में संसाधनों और कुशल लोगों की कोई कमी नहीं है, अब सिर्फ उनके निवेश का इंतजार है। मान ने कहा कि सरकार का काम उद्योगों को सुविधाएं देना और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है। उन्होंने कहा कि व्यापारी और उद्योगपति सरकार के लिए चुनावी फंड का जरिया नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा हैं। मुख्यमंत्री ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि सरकार बनने के बाद कई उद्योगपति उनसे मिलने आए। एक उद्योगपति ने कहा कि वह करोड़ों रुपए का निवेश करना चाहता है, लेकिन सरकार का सहयोग चाहिए, जब उन्होंने पूछा कि किस तरह का सहयोग चाहिए तो उद्योगपति ने हाथ जोड़कर कहा, 'बस हमें तंग मत करना।' सीएम ने कहा कि इससे पता चलता है कि पहले उद्योगों के साथ कैसा व्यवहार होता था।

टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब का टेक्सटाइल सेक्टर आज भी देश के प्रमुख उद्योगों में शामिल है। लुधियाना देश के करीब 90 फीसदी होजरी और गारमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र है, जहां बड़े ब्रांड से लेकर एमएसएमई तक काम कर रहे हैं। इसके अलावा जालंधर और अमृतसर भी प्रमुख औद्योगिक शहर हैं। इसी वजह से पंजाब ने इस क्षेत्र में पार्टनर स्टेट बनने का फैसला लिया है।

- उद्योगपति बोला, निवेश करेंगे, बस तंग मत करना

तीन करोड़ से ज्यादा की नहीं हुई चोरी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए जा रहे आंकड़े : गोविंद गिरी

- राम मंदिर दान विवाद के बीच स्वामी ने इस्तीफे की खबरों को बताया झूठा

एजेंसी, अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने अपने इस्तीफे की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने ट्रस्ट के खजांची के इस्तीफे की खबरों को पूरी तरह से आधारहीन व झूठा करार देते हुए स्पष्ट किया कि वे स्वयं अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि संघर्ष के इस दौर में ट्रस्ट के साथ मजबूती से खड़ा होना बेहद जरूरी है।

स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद के इस्तीफा देने की खबरों को खारिज करते हुए कहा, खजांची के इस्तीफा देने की खबरें फैलाई गई हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं कोषाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दूंगा, जो खबरें आ रही हैं वो झूठी हैं। इस मुश्किल वक्त में ट्रस्ट के साथ खड़ा होना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि वह एसआईटी की जांच से संतुष्ट हैं।

गोविंद गिरी महाराज ने भारतीय स्टेट बैंक पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसबीआई बैंक को अपने इंस्पेक्टर खुद रखने चाहिए थे और उन्हें अनुशासन का पालन करना चाहिए था। उन्होंने मीडिया में आ रहे गबन के आंकड़ों को बहुत ज्यादा बताते हुए अपना अनुमान जताया कि ये रकम करीब 3 करोड़ रुपए होगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल अकाउंट वेरिफिकेशन का काम ठीक से चल रहा है।

समीक्षा प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जल्द होगा किशाऊ एमओयू हस्ताक्षरित, सीएम ने की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता

हिमाचल को सालाना मिलेंगे 600 करोड़ : सीएम सुक्खू

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की साझा 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ बहुउद्देशीय जलविद्युत परियोजना को लेकर जल्द ही केंद्र सरकार और साझेदार राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।

यह एमओयू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हस्ताक्षरित किया जा सकता है। इससे पहले केंद्र सरकार ने एमओयू का मसौदा सभी साझेदार राज्यों को भेज दिया है और उन पर सुझाव मांगे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इसी मसौदे की समीक्षा के लिए उन्होंने शिमला में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अधिकारियों के साथ एमओयू के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की गई और जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को आगे बढ़ाने के पक्ष में है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और यहां के लोगों के अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुई बैठक में परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर सहमति बनी है। इस व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश को परियोजना में कोई पूंजी निवेश नहीं करना पड़ेगा व राज्य को हर वर्ष करीब 600 करोड़ रुपए की आय होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले के मसौदा समझौते को स्वीकार नहीं किया था और हिमाचल की ओर से रखी गई शर्तों को सभी पक्षों से मंजूरी दिलाई गई। इससे राज्य के दीर्घकालिक हित सुरक्षित हुए हैं और परियोजना के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है।

राज्य के अधिकारों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता

सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ने हमेशा प्रदेश के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि किशाऊ परियोजना पर बनी सहमति हिमाचल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे राज्य को लंबे समय तक लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की परियोजनाओं से हिमाचल के 13,066 मिलियन यूनिट बिजली के लंबे समय से लंबित बकाये को हासिल करने के प्रयास भी तेज कर रही है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बावजूद करीब 15 वर्षों से यह मामला लंबित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने किशाऊ परियोजना में राज्य के वित्तीय योगदान को लेकर आठ वर्ष से चले आ रहे गतिरोध को भी समाप्त किया है। उन्होंने बताया कि पिछली भाजपा सरकार ने इस परियोजना में हिमाचल की हिस्सेदारी के रूप में करीब 800 करोड़ रुपए देने पर सहमति जताई थी। मौजूदा सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया और बातचीत के जरिए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की, जिसके तहत हिमाचल को परियोजना में कोई पूंजी निवेश नहीं करना होगा और राज्य अपने सभी वैध लाभ भी प्राप्त करेगा।

अनुराग ने की सीएम योगी से मुलाकात उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल को सराहा

अनिल कुमार, हमीरपुर। सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में शिष्टाचार भेंट की।

इस दौरान उन्होंने विकास, सुशासन और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को उत्तर प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के रूप में प्रभावी ढंग से लागू किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज डबल इंजन सरकार के सफल मॉडल के रूप में उभर रहा है, जहां बेहतर कानून व्यवस्था, निवेश को बढ़ावा और जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विकास को गति मिली है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13.30 लाख करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 30.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसी अवधि में प्रति व्यक्ति आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राज्य में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और निवेश के अनुकूल माहौल के कारण उद्योगों का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने बताया कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के बाद बड़ी संख्या में निवेश परियोजनाओं पर कार्य शुरू हुआ है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सड़क और परिवहन क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने तेजी से प्रगति की है। राज्य में कई एक्सप्रेसवे संचालित हैं और नए प्रोजेक्टों पर काम जारी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने जन आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदलने का कार्य किया है।

युवाओं को कौशल विकास से सामाजिक सेवा तक जोड़ेगा माय भारत अभियान

अभियान को बढ़ावा देने के लिए जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित, 15 अगस्त तक करें पंजीकरण

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मेरा युवा भारत अभियान को जिला स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से माय भारत जिला समन्वय समिति की बैठक उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में अभियान की गतिविधियों, युवाओं के पंजीकरण और उन्हें उपलब्ध अवसरों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर उपायुक्त ने माय भारत पंजीकरण अभियान का शुभारंभ भी किया। उपायुक्त ने बताया कि 15 अगस्त, 2026 तक युवा माई भारत के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर इस अभियान से जुड़ सकते हैं। अभियान के माध्यम से युवा नृत्य प्रतियोगिता, रील एवं लघु फिल्म प्रतियोगिता, मौलिक संगीत प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक और स्लैम पोएट्री जैसी प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट और यंग भारत यंग लीडर डायलॉग-2026 जैसे कार्यक्रमों में भी प्रतिभागिता का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि माय भारत अभियान युवाओं को नेतृत्व क्षमता विकसित करने, टीम भावना बढ़ाने और सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए प्रेरित करता है।

इसके माध्यम से 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, नशा मुक्ति, स्वास्थ्य जागरूकता, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छता, आपदा प्रबंधन और अन्य सामाजिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। डीसी ने कहा कि माय भारत अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने वाले ओशिन शर्मा, दिव्यांशी, कनिष्क और तरुण शर्मा को अनुभव प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया। बैठक में बताया गया कि जिला स्तर पर अभियान के संचालन और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के लिए माई भारत जिला समन्वय समिति का गठन किया गया है। समिति युवाओं को सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों और स्वयंसेवी संगठनों के साथ जोड़कर जनहित के कार्यों में भागीदारी के अवसर उपलब्ध करवाएगी।

उपायुक्त ने कहा कि माय भारत अभियान का उद्देश्य युवाओं में सेवा भावना, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, नवाचार और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को विकसित करना है। बैठक में अतिरिक्त जिलाधीश सचिन शर्मा, जिला रोजगार अधिकारी अनीता, जिला भाषा अधिकारी सरोजना नरवाल, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा लेखराज भारद्वाज, उप निदेशक माई भारत शिमला विपिन कुमार, जिला एनएसएस समन्वयक पूनम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

पांच प्रमुख मंदिर ट्रस्टों की वेबसाइट इसी माह होंगी लॉन्च

शिमला। जिला के पांच प्रमुख मंदिर ट्रस्टों की वेबसाइट विकसित करने को लेकर डीसी अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वेबसाइट निर्माण की प्रगति, ऑनलाइन सेवाओं व श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध करवाई जाने वाली डिजिटल सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। डीसी ने कहा कि मंदिर ट्रस्टों की वेबसाइटें श्रद्धालुओं को पारदर्शी व सरल सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होंगी। इन वेबसाइटों पर मंदिरों का इतिहास, धार्मिक महत्व, पूजा-अर्चना का समय, प्रमुख उत्सवों की जानकारी, ऑनलाइन दान, आरती एवं विशेष पूजन की बुकिंग सहित अन्य आवश्यक जानकारियां उपलब्ध होंगी। उन्होंने निर्देश दिए कि वेबसाइट का डिजाइन उपयोगकर्ता के अनुकूल हो तथा सभी जानकारियां हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध करवाई जाएं। साइबर सुरक्षा, नियमित अपडेट और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखने को कहा गया। उपायुक्त ने मंदिर ट्रस्टों में रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन की प्रक्रिया इसी सप्ताह पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वेबसाइट निर्माण का कार्य एक सप्ताह में पूरा कर इसी माह इनकी लॉन्चिंग की जाएगी। बैठक में मंदिर ट्रस्टों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, जबकि एसडीएम शिमला ग्रामीण मंजीत शर्मा सहित अन्य अधिकारी और तकनीकी एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

खाद्य सुरक्षा पर सख्ती, 800 पंजीकरण व 65 लाइसेंस जारी

शिमला। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की 10वीं बैठक उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में खाद्य सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों, लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रक्रिया और विभागीय प्रगति की समीक्षा की गई। डीसी ने बताया कि जिले में अब तक खाद्य व्यवसाय संचालकों के 800 पंजीकरण व 65 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में 172 पंजीकरण हुए हैं, जिनमें से 67 लाइसेंस जारी किए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को सभी पात्र खाद्य प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में लाने के निर्देश दिए। बैठक में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने, खाद्य नमूनों की जांच व खाद्य व्यवसायियों को सुरक्षा मानकों के पालन के लिए प्रेरित करने पर चर्चा हुई। डीसी ने स्कूलों में 'ईट राइट स्कूल' अभियान के तहत निरीक्षण बढ़ाने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि शिमला के शोघी क्षेत्र में फूड टेस्टिंग लैब स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहां खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मिलावट की वैज्ञानिक जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। बैठक में अधिकारियों को होटल, रेस्तरां, ढाबों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

किसानों, व्यापारियों व आम जनता को राहत देने के लिए युद्धस्तर पर हो सड़क की मरम्मत: कर्ण नंदा

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने नगर निगम शिमला के आयुक्त सचिन कंवल से उनके कार्यालय में भेंट कर लोअर बाजार सब्जी मंडी को जाने वाले भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्ग की शीघ्र मरम्मत एवं वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा।

कर्ण नंदा ने आयुक्त को बताया कि हाल ही में हुई भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण कार्ट रोड से लोअर बाजार सब्जी मंडी को जोड़ने वाला मार्ग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके चलते किसानों, आढ़तियों, व्यापारियों तथा आम उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सब्जियों एवं अन्य कृषि उत्पादों को सीधे मंडी तक नहीं पहुंचाया जा पा रहा है, जिससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है और इसका प्रभाव आम जनता तक बढ़ती सब्जियों की कीमतों के रूप में पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में यदि इस सड़क की शीघ्र मरम्मत नहीं की गई तो राजधानी शिमला की प्रमुख सब्जी मंडी में आपूर्ति प्रभावित होगी, जिससे आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा।

उन्होंने आग्रह किया कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। ज्ञापन में भाजपा की ओर से मांग की गई कि क्षतिग्रस्त सड़क की युद्धस्तर पर तत्काल मरम्मत करवाई जाए, सड़क पूरी तरह बहाल होने तक किसानों और व्यापारियों के लिए सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराया जाए, कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाए तथा नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन के समन्वय से कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए।

शोघी में स्मार्ट एमएसएमई पर जागरूकता व क्षमता निर्माण सत्र आयोजित

जेम पोर्टल, एआई व आधुनिक तकनीकों की दी जानकारी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। बिजनेस प्रमोशन सेंटर, शोघी में स्मार्ट एमएसएमई कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता व क्षमता निर्माण सत्र का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को डिजिटल रूपांतरण, इंडस्ट्री 4.0 तकनीकों तथा आधुनिक तकनीकी समाधानों के प्रति जागरूक करना और उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था।

कार्यक्रम में स्थानीय एमएसएमई इकाइयों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने, तकनीकी नवाचार, आधुनिकीकरण और नई तकनीकों के उपयोग के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। उद्यमियों को व्यवसाय विकास और तकनीकी उन्नयन के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सहायता तंत्रों की जानकारी भी प्रदान की गई। तकनीकी सत्र में रैम्प परियोजना समन्वयक कोविद शर्मा ने इंडस्ट्री 4.0, स्मार्ट विनिर्माण, स्वचालन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और डिजिटल परिवर्तन जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों को अपनाकर एमएसएमई इकाइयां अपनी उत्पादकता, कार्यकुशलता और बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को बढ़ा सकती हैं। जिला उद्योग केंद्र, शिमला के अभिलक्ष लौ ने प्रतिभागियों को सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जेम पोर्टल एमएसएमई इकाइयों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है और इसके माध्यम से उद्यमी अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। कार्यक्रम में विभिन्न एमएसएमई इकाइयों से जुड़े 30 से अधिक उद्यमियों, उद्योगपतियों व प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने डिजिटल तकनीक, जेम पोर्टल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और एमएसएमई विकास से जुड़ी सरकारी पहलों में विशेष रुचि दिखाई। उन्होंने विशेषज्ञों से संवाद कर अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान भी प्राप्त किया।

कार्यक्रम का समापन संवादात्मक चर्चा सत्र के साथ हुआ, जिसमें विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर दिए। आयोजकों ने सभी उद्यमियों व अतिथियों का सफल आयोजन में सहयोग एवं सक्रिय सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया।

पुलिस अभिरक्षा से फरार आरोपी काबू

बिलासपुर। पुलिस की विशेष टीम ने पुलिस अभिरक्षा से फरार चल रहे आरोपी अजय कुमार को हरियाणा के झज्जर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी अजय कुमार पुत्र प्रेम सिंह, निवासी गांव एवं डाकघर गोयला ताला, तहसील एवं थाना बादली, जिला झज्जर (हरियाणा) का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सदर बिलासपुर में फरार होने का मामला दर्ज किया गया था। आरोपी को न्यायालय में पेशी के लिए हरियाणा ले जाया गया था, जहां से वापसी के दौरान वह पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था।

निविदा आमंत्रण नोटिस

ग्राम पंचायत घाट, विकास खण्ड बालीचौकी वित वर्ष 2026-27 में विकास कार्यों के निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत को आवश्यक सामग्री की आपुर्ति हेतू इच्छुक आपुर्तिकर्ताओं से निविदाएं आमंत्रित करती है। इच्छुक आवेदनकर्ता ग्राम पंचायत घाट से टेंडर फार्म प्राप्त कर सकते हैं। फार्म जमा करवाने की अंतिम तिथि 24 जुलाई, 2026 शाम 4:00 बजे तक है। निविदाएं 25 जुलाई, 2026 को प्रातः 11:00 बजे ग्राम पंचायत कार्यलय में खोली जाएगीं। निविदा में भाग लेने के लिए धरोहर राशि व टेंडर फार्म फीस व विभाग द्वारा जारी विभिन्न शपथ पत्र जारी दिए जाने अनिवार्य होगें। ग्राम पंचायत द्वारा जारी व हस्ताक्षरित टेंडर फार्म पर दी गई निविदाएं ही मान्य होगीं। विस्तृत शर्ते टेंडर फार्म के साथ संलग्न हैं।

प्रधान, ग्राम पंचायत घाट
विकास खण्ड बालीचौकी, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ।

निविदा आमंत्रण नोटिस

ग्राम पंचायत थाचाधार, विकास खण्ड बालीचौकी वित वर्ष 2026-27 में विकास कार्यों के निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत को आवश्यक सामग्री की आपुर्ति हेतू इच्छुक आपुर्तिकर्ताओं से निविदाएं आमंत्रित करती है। इच्छुक आवेदनकर्ता ग्राम पंचायत थाचाधार से टेंडर फार्म प्राप्त कर सकते हैं। फार्म जमा करवाने की अंतिम तिथि 25 जुलाई, 2026 शाम 4:00 बजे तक है। निविदाएं 26 जुलाई, 2026 को प्रातः 11:00 बजे ग्राम पंचायत कार्यलय में खोली जाएगीं। निविदा में भाग लेने के लिए धरोहर राशि व टेंडर फार्म फीस व विभाग द्वारा जारी विभिन्न शपथ पत्र जारी दिए जाने अनिवार्य होगें। ग्राम पंचायत द्वारा जारी व हस्ताक्षरित टेंडर फार्म पर दी गई निविदाएं ही मान्य होगीं। विस्तृत शर्ते टेंडर फार्म के साथ संलग्न हैं।

प्रधान, ग्राम पंचायत थाचाधार,
विकास खण्ड बालीचौकी, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ।

कार्यालय ग्राम पंचायत टिक्कर
विकास खंड गोपालपुर, तहसील सरकाघाट, जिला मंडी (हि.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

ग्राम पंचायत टिक्कर की मासिक बैठक में सर्व सम्मति से प्रस्ताव रखा गया है कि पंचायत के विकास कार्यों के लिए Sand Crusher, Aggrigate, Boulder, Pukki Eat (Bricks), Samgri Dhulan (Cement), JCB, Shattering, Shattering Slab, Sand Khadd, Agg. Khadd, Sand Plant, Cut Stone, JCB Breaker, Sign Board के लिए वर्ष 2026-27 के लिए निविदाएं आमंत्रित की जानी है। इच्छुक सप्लायरों द्वारा निविदाएं पंचायत कार्यालय में 16/07/2026 सांय 5:00 बजे तक जमा करवानी होगी। सभी निविदाएं आगामी पंचायत बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष खोली जाएंगी। अतः प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित व पास है। **नियम व शर्तेः–** (1) निविदा देने वाले के पास अपना जीएसटी नं. होना चाहिए। (2) सामग्री गाड़ी में जहाँ तक जा सकती है पहुंचानी होगी। (3) पंचायत के सप्लाई आदेश पर ही सामग्री दी जायेगी। (4) यदि सामग्री में सही गुणवता नहीं पाई जाती है या समय पर पर सप्लाई नहीं दी जाती जिसके कार जिसके कारण यदि कार्य में बाधा पैदा होती या पैदा होती है तो आपूर्तिकर्ता को पंचायत द्वारा एक माह का नोटिस देने पर किसी भी समय निविदा रददं की जा सकती है (5) निविदा स्वीकृत या रदद करने का अधिकार निविदा कमेटी को होगा (6) यदि निविदा किसी व्यक्ति या फर्म की स्वीकृत होती है तो उस व्यक्ति या फर्म को निविदा 20000/- रूपये धरोहर राशि के रूप में पंचायत में जमा करवाने होगें। (7) निविदा खुलने वाली तिथि को जिस भी व्यक्ति या फर्म ने निविदा हेतू अपना आवेदन पंचायत को किया है निविदा खुलते समय उपस्थित होना अनिवार्य है। (8) निविदा में मांगी गई प्रत्येक सामग्री वस्तु का मूल्य व जीएसटी प्रत्येक सामग्री में निर्धारित दर से अलग बिल में दर्शाना होगा। (9) निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकर्ता को सप्लाई की गई सामग्री (वस्तु) के साथ एम-फार्म जमा करवाना अनिवार्य है। (10) निविदा स्वीकृत होने पर व्यक्ति या फर्म को अपने दस्तावेज जैसे- जीएसटी न0, आधार कार्ड, बैंक पास बुक की फोटो कापी जमा करवानी होगी।

पंचायत /सचिव
ग्राम पंचायत टिक्कर विकास खंड गोपालपुर, जिला

कार्यालय ग्राम पंचायत घेच कोहबाग
विकास खंड टूटू, जिला शिमला (हि.प्र.)

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत घेच कोहबाग वित्त वर्ष 2026-27 में करवाए जाने वाले समस्त कार्यों हेतु निम्न निर्माण सामग्री की निविदाएं/कोटेशन अमंत्रित करती है। (1) Sand Darla (CFT), (2) Sand Dhulla (CFT), (3) Sand Crusher (CFT), (4) Aggregate 10 MM(CFT), (5) Aggregate 20 MM(CFT), (6) Aggregate 40 MM(CFT), (7)Bricks (Per Tile), (8) Stone(CFT), (9) Cement Carriage(Per Bag), (10) Mi&ture(Per Hour), (11) JCB Backhoe Loader (Per Hour), (12) JCB Rock Breaker (Per Hour), (13) Signboard(3*2), (14) Shuttering(Per Day). **कोटेशन / निविदा संबंधित शर्ते व नियमः–** कोटेशन/निविदा लिफाफा बंद होनी चाहिए तथा प्रधान ग्राम पंचायत घेच कोहबाग के नाम देय हो, कोटेशन/निविदा लिफाफा के बाहर फर्म/एजेंसी/सप्लाईर/आवेदक का नाम तथा फ़ोन न. स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए । फर्म/एजेंसी/सप्लाईर/आवेदक कर्ता के पास जीएसटी नंबर होना आवश्यक है और उनके नाम से GST नंबर एवं बिल वाउचर पर GST नंबर होना अनिवार्य होगा तथा वाहन व मशीन संबंधित कागजात, व्यक्ति/फर्म का बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर, तथा वोटर आईडी कार्ड नंबर, GST न. की कॉपी कुटेशन के साथ लगाना अनिवार्य होगा। फर्म/एजेंसी/सप्लाईर/आवेदककर्ता द्वारा कोट की गई दरों के साथ GST (Included or Excluded) स्पष्ट शब्दों लिखना अनिवार्य होगा। कोटेशन दिनांक 23 जुलाई, 2026 दोपहर 4:00 बजे तक कार्यालय ग्राम पंचायत घेच कोहबाग में पहुंच जानी चाहिए । जिन्हें 24 जुलाई, 2026 को सुबह 11:00 बजे पंचायत द्वारा गठित कमेटी के सम्मुख खोला जायेगा। सभी प्रकार की निर्माण सामग्री जैसे (रेता, रोड़ी, पत्थर, गटका, ईट इत्यादि) के लिए एम फॉर्म आवश्यक होंगे वेंडर को साथ ही लिख कर भी देना होगा कि इस एम फॉर्म का प्रयोग सिर्फ इसी बिल (बिल नंबर तथा तिथि सहित) के साथ किया गया है। निविदा में भाग लेने हेतु सभी वेंडरों को धरोहर राशी 5000/- रु. ग्राम पंचायत घेच कोहबाग को जमा करवाना होगा। ग्राम पंचायत घेच कोहबाग किसी भी कुटेशन / निविदा से सम्बंधित शर्तो व नियमों में किसी भी प्रकार का सशोंधन करने के लिए अधिकृत होगी।

प्रधान
ग्राम पंचायत घेच कोहबाग, विकास खंड टूटू, जिला शिमला हि. प्र.

कार्यालय ग्राम पंचायत घाड़
विकास खंड पालमपुर, तह. पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

निविदा सूचना

यह कि बैठक में प्रस्तात रखा गया कि ग्राम पंचायत घाड़ वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न मदों से किए जाने वाले विकास कार्यों हेतु सामग्री क्रय करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की जानी हैं। सामग्री का विवरण निम्न प्रकार से है। 1. क्रैशर रेत-प्रति घन फुट, 2. क्रैशर बजरी-प्रति घन फुट, 3. क्रैशर गटका-प्रति घन फुट, 4. बोल्डर-प्रति घन फुट, 5. फाडा पत्थर-प्रति घन फुट, 6. ईंट अब्बल- प्रति ईंट, 7. ईंट दोम- प्रति ईंट, 8. कट स्टोन-प्रति पथ्थर, 9. जेसीबी खुदाई कार्य-प्रति घंटा, 10. शटरिंग लकड़ी-प्रति वर्ग फुट, 11. शटरिंग लोहा-प्रति वर्ग फुट, 12. साईन बोर्ड सीमेंट लिखाई-प्रति वर्ग फुट, 13. दीवार पेंटिंग साईन बोर्ड-प्रति दीवार, 14. सीमेंट ढुलाई सरकारी सिद्धपुर से घाड़ सीमेंट स्टोर तक-प्रति बैग, 15. टाईल आईएसआई/पेवर टाईल व सीमेंट बैग लेवर लोडिंग व अनलोडिंग -प्रति बैग। स्टोर से कार्यस्थल तक। इच्छुक सप्लायर /फर्म दिनांक 21.07.26 तक शाम 5.00 बजे तक कार्यालय ग्राम पंचायत घाड़ में पंचायत प्रधान/सचिव के पास कुटेशन सीलबंद लिफाफे में पंजीकृत पत्र या स्वयं जमा करवाएं। सप्लायार/फर्म के पास अपना जीएसटी नं. होना चाहिए। रेट जीएसटी व FOR सहित होने चाहिए। सामग्री की मात्रा व गुणवत्ता सही होनी चाहिए। सप्लायर को सामग्री के साथ एम फार्म देने होंगे साथ में शपथ पत्र देना होगा। फर्म सप्लायर की दायगी एमबी (तकनीकी मूल्यांकन) होने पर ही की जाएगी। किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में ग्राम पंचायत घाड़ का निर्णय अंतिम होगा। सप्लायर के द्वारा समय पर ही सामग्री सप्लाई की आपूर्ती ना करने पर बिना नोटिस के कुटेशन को रद्द करके फर्म/सप्लायर को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। कुटेशन के साथ रू.25000/- अग्रिम राशि /एफडी पंचायत में जमा करवानी होगी। कुटेशन दिनांक 25.07.2026 को पंचायत बैठक में प्रातः 11.00 बजे कमेटी के समक्ष खोली जाएंगी। प्रस्ताव सर्वसहमती से पास हुआ।

प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत घाड़
विकास खंड पालमपुर, तह. पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

कार्यालय ग्राम पंचायत बठमाना जाबरी
विकास खण्ड टुटूहिरानगर उप-तहसील धामी जिला शिमला, हि.प्र.

निविदा सूचना

विषय :– ग्राम पंचायत बठमाना जाबरी में वर्ष 2026-2027 के लिए रेता, रोडी, पत्थर, ईट, सीमेंट, केरिज मानरेगा व सामान्य वोर्ड और जे.सी.बी. की निवेदाताए आमंत्रित करें बारे।

आज पंचायत बैठक में उपरोक्त विषय पर अध्यक्ष अनुमती उपरांत चर्चा ग्राम पंचायत बठमाना जाबरी के लिए वर्ष 2026-2027 के लिए रेता, रोडी, पत्थर, ईट, सीमेंट, केरिज और जे.सी.बी. बठमाना जाबरी में निविदाएं दिनांक 23 जुलाई, 2026 तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदाएं 25 जुलाई 2026 को पंचायत कमेटी के सामने खोली जाएंगी। निवेदिताओं के मालिक स्वयं ग्राम पंचायत में आना अनिवार्य होगा, शर्ते निम्न प्रकार से है।

1. निविदाएं करने वाले के पास जी.एस.टी. नंबर आवश्यक होना चाहिए और बिल जी.एस.टी. के साथ होना अनिवार्य है तभी निवेदिताए मान्य होगी अन्यथा निवेदिताएं रद्द की जाएगी।
2. निवेदिताए सील बंद लिफाफे पंजीकृत डाक द्वारा या सीधे पंचायत में भी जमा हो सकती है।
3. सामग्री की दरे एक वर्ष के लिए मान्य है
4. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता उचित व अनिवार्य है गुणवत्ता सही न होने की स्थिति में निवेदिताए को रद्द करने का अधिकार पंचायत के पास होगा।
5. रेता धुला, केशर, दाडला रोडी पत्थर निवेदिताएं के पास बिल के साथ एम फार्म होना चाहिए विबल प्रति गाडी लिया जाएगा।
6. पांच हजार रुपए की धरोहर राशि एफ.डी.आर. प्रधान ग्राम पंचायत बठमाना जाबरी को निवेदिताए के साथ एक वर्ष के लिए जमा होगी और धरोहर राशि एफ.डी.आर. एक वर्ष के बाद वापिस कर दी जाएगी और सामग्री का भुगतान न करने पर धरोहर राशि वापिस नहीं होगी।

अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की उपरोक्त लिखित ग्राम पंचायत बठमाना जाबरी उपरोक्त प्रस्ताव सम्मति से पारित किया गया है।

पंचायत प्रधान कुमारी ज्योति शर्मा

कार्यालय ग्राम पंचायत थाटा
(विकास खण्ड बालीचौकी जिला मंडी हिमाचल प्रदेश)

निविदा आमंत्रण सूचना

ग्राम पंचायत थाटा विकास खण्ड बालीचौकी जिला मंडी हिमाचल प्रदेश द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यकता अनुसार अधिकृत विक्रेताओं से मोहरबंद (sealed) निविदाएं/कोटेशन आमंत्रित की जाती है। ये निविदाएं दिनांक 26.7.2026 तक ग्राम पंचायत थाटा के कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। इस तिथि तक प्राप्त निविदाओं को कार्यालय ग्राम पंचायत थाटा में दिनांक 27.7.2026 को प्रातः 11:00 बजे पदाधिकारी की गणपूर्ति व निविदाओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष (यदि उपस्थित हो) खोली जाएगी। प्रशासकीय कारणो से इस तिथि को बदलाव करने का अधिकार ग्राम पंचायत थाटा के पास सुरक्षित रहेगा। इस दशा में सूचना समाचार पत्रों में प्रदर्शित नहीं की जाएगी। सूचना ग्राम पंचायत के सूचनापट्ट पर ही प्रदर्शित की जाएगी। ग्राम पंचायत को इस अवधि हेतु निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता रहेगीः- **सामग्री का विवरण–** 1. रेत क्रशर/WATER BORNE-प्रति फुट 2. बजरी क्रशर- 3. सोलिंग/बोल्डर पत्थर-प्रति चैटा (6*6) फीट 4. पत्थर (कट स्टोन) / लोकल पत्थर-प्रति चैटा (6*8) फीट/CUB MET 5. ईट मिट्टी के भठे की-प्रति 1000 6. JCB Machine Excavator द्वारा मिट्टी व ब्रेकर-प्रति घन मीटर (हाई/सॉफ्ट रॉक) प्रति घंटा 7. सामग्री ढूलान (सीमेंट बालीचौकी से (पंचायत क्षेत्र जहाँ तक सड़कें)-प्रति किलोमीटर / प्रति फेरा / प्रति बैग 8. शटरिंग लोहा व लकड़ी-प्रति फुट 9. लकड़ी लोहा व एलुमिनियम फिटिंग व डोर विन्डो-आइटम बार प्रति फुट 10. प्लाई बोर्ड शीटें OTHER फैंसी सीलिंग/पैलोंग PVC फटे SHEETS-आइटम बार साइज़ बार 11. लेबर रेट पेलिंग PVC वुडन-प्रति स्क्वायर फीट 12. हार्डवेयर सरिया एंगल चैनल साइज़ वार, कंटीली लोहे की तारें टाइल पेंट रेलिंग लोहा पाइप विभिन्न साइज़ सैनिटरी फिटिंग व लेबर रेट-आइटम बार व् प्रति किलो/प्रति क्विंटल प्रति पॉइंट 13. कलर कोटिड रूफ शीट्स/प्लेन रूफ शीट आदि व सीलिंग शीट्स आदि-प्रति शीट साइज़ बार 14. RCC कलवर्ट PIPE-साइज़ बार 15. FURNITURE ITEMS (सभी प्रकार की फर्नीचर वस्तुएं)-प्रति आइटम पूर्ण विवरण सहित 16. वेल्डिंग वर्क्स-प्रति किलो/ प्रति क्विंटल 17. मिक्सर मशीन-प्रति दिन प्रति घंटा 18. पेंटर/दिवार लेखन-प्रति दिन / स्क्वायर फीट 19. साइन बोर्ड/दीवार लेखन/पेंटिंग-साइज़ वार/अन्य 20. पंचवटी पार्क हेतु बेंच इत्यादि-आइटम वार 21. स्वछता प्रबंधन हेतु विभिन्न आइटम (प्लास्टिक कचरा संग्रहण शेड आदि)- आइटम बार व् साइज़ बार 22. ढलान घोड़े खचर द्वारा रेट बजरी सीमेंट ईट पत्थर-दुरी अनुसार 23. अन्य सामग्री जो पंचायत के कार्य में प्रयुक्त होनी है उपर दर्शाई हो-आइटम वार। **शर्ते–** निविदादाता (आपूर्ति कर्ता) के पास अपना पंजीकरण, TIN NO/CST/GST NO. होना आवश्यक है और रेत/बजरी व पत्थर आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग M/X FORM तथा गाड़ी की RC ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करना होगा व PWD लैब से प्रमाणिकता का प्रमाण पत्र भी संलगन करना होगा और साथ में GST Return Copy व MX FORM उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा निविदा पर दरें स्पष्ट अंकित होनी चाहिए। निविदादाता को धरोहर राशी निविदा पारित होने के 2 दिन के भीतर जमा करनी होगी जिसे कमेटी द्वारा पारित किया जायेगा। OVERWRITING होने की दशा में निविदा रद्द की जाएगी। सामग्री की आपूर्ति HPPWD की SPECIFICATION के अनुरूप होगी किसी भी निविदा को बिना कारण बताये सवीकृत/असवीकृत/रद्द करने, सामान दर रहने की स्थिति में, एक या एक से अधिक निविदाताओं के लिए आपूर्ति आदेश निर्गत करने, सामग्री की गुणवता का चयन तथा निविदाएँ किसी भी समय रद्द करने का पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित रहेगा। सामग्री खरींद की अंतिम मूल्य/निर्णय विभाग की JUSTIFICATION व अनुमोदित निविदाओं के साथ NEGOTITION अनुसार ही किया जायेगा।

प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत थाटा (विकास खण्ड बालीचौकी जिला मंडी हिमाचल प्रदेश)

कार्यालय ग्राम पंचायत खलवाहण
(विकास खण्ड बालीचौकी जिला मंडी हिमाचल प्रदेश)

निविदा आमंत्रण सूचना

ग्राम पंचायत खलवाहण विकास खण्ड बालीचौकी जिला मंडी हिमाचल प्रदेश द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यकता अनुसार अधिकृत विक्रेताओं से मोहरबंद (sealed) निविदाएं/कोटेशन आमंत्रित की जाती है। ये निविदाएं दिनांक 24.7.2026 तक ग्राम पंचायत खलवाहण के कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। इस तिथि तक प्राप्त निविदाओं को कार्यालय ग्राम पंचायत खलवाहण में दिनांक 25.7.2026 को प्रातः 11:00 बजे पदाधिकारी की गणपूर्ति व निविदाओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष (यदि उपस्थित हो) खोली जाएगी। प्रशासकीय कारणो से इस तिथि को बदलाव करने का अधिकार ग्राम पंचायत खलवाहण के पास सुरक्षित रहेगा। इस दशा में सूचना समाचार पत्रों में प्रदर्शित नहीं की जाएगी। सूचना ग्राम पंचायत के सूचनापट्ट पर ही प्रदर्शित की जाएगी। ग्राम पंचायत को इस अवधि हेतु निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता रहेगीः- **सामग्री का विवरण–** 1. रेत क्रशर/WATER BORNE-प्रति फुट 2. बजरी क्रशर- 3. सोलिंग/बोल्डर पत्थर-प्रति चैटा (6*6) फीट 4. पत्थर (कट स्टोन) / लोकल पत्थर-प्रति चैटा (6*8) फीट/CUB MET 5. ईट मिट्टी के भठे की-प्रति 1000 6. JCB Machine Excavator द्वारा मिट्टी व ब्रेकर-प्रति घन मीटर (हाई/सॉफ्ट रॉक) प्रति घंटा 7. सामग्री ढूलान (सीमेंट बालीचौकी से (पंचायत क्षेत्र जहाँ तक सड़कें)-प्रति किलोमीटर / प्रति फेरा / प्रति बैग 8. शटरिंग लोहा व लकड़ी-प्रति फुट 9. लकड़ी लोहा व एलुमिनियम फिटिंग व डोर विन्डो-आइटम बार प्रति फुट 10. प्लाई बोर्ड शीटें OTHER फैंसी सीलिंग/पैलोंग PVC फटे SHEETS-आइटम बार साइज़ बार 11. लेबर रेट पेलिंग PVC वुडन-प्रति स्क्वायर फीट 12. हार्डवेयर सरिया एंगल चैनल साइज़ वार, कंटीली लोहे की तारें टाइल पेंट रेलिंग लोहा पाइप विभिन्न साइज़ सैनिटरी फिटिंग व लेबर रेट-आइटम बार व् प्रति किलो/प्रति क्विंटल प्रति पॉइंट 13. कलर कोटिड रूफ शीट्स/प्लेन रूफ शीट आदि व सीलिंग शीट्स आदि-प्रति शीट साइज़ बार 14. RCC कलवर्ट PIPE-साइज़ बार 15. FURNITURE ITEMS (सभी प्रकार की फर्नीचर वस्तुएं)-प्रति आइटम पूर्ण विवरण सहित 16. वेल्डिंग वर्क्स-प्रति किलो/ प्रति क्विंटल 17. मिक्सर मशीन-प्रति दिन प्रति घंटा 18. पेंटर/दिवार लेखन-प्रति दिन / स्क्वायर फीट 19. साइन बोर्ड/दीवार लेखन/पेंटिंग-साइज़ वार/अन्य 20. पंचवटी पार्क हेतु बेंच इत्यादि-आइटम वार 21. स्वछता प्रबंधन हेतु विभिन्न आइटम (प्लास्टिक कचरा संग्रहण शेड आदि)- आइटम बार व् साइज़ बार 22. ढलान घोड़े खचर द्वारा रेट बजरी सीमेंट ईट पत्थर-दुरी अनुसार 23. अन्य सामग्री जो पंचायत के कार्य में प्रयुक्त होनी है उपर दर्शाई हो-आइटम वार। **शर्ते–** निविदादाता (आपूर्ति कर्ता) के पास अपना पंजीकरण, TIN NO/CST/GST NO. होना आवश्यक है और रेट/बजरी व पत्थर आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग M/X FORM तथा गाड़ी की RC ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करना होगा व PWD लैब से प्रमाणिकता का प्रमाण पत्र भी संलगन करना होगा और साथ में GST Return Copy व MX FORM उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा निविदा पर दरें स्पष्ट अंकित होनी चाहिए। निविदादाता को धरोहर राशी निविदा पारित होने के 2 दिन के भीतर जमा करनी होगी जिसे कमेटी द्वारा पारित किया जायेगा। OVERWRITING होने की दशा में निविदा रद्द की जाएगी। सामग्री की आपूर्ति HPPWD की SPECIFICATION के अनुरूप होगी किसी भी निविदा को बिना कारण बताये सवीकृत/असवीकृत/रद्द करने, सामान दर रहने की स्थिति में, एक या एक से अधिक निविदादाताओं के लिए आपूर्ति आदेश निर्गत करने, सामग्री की गुणवता का चयन तथा निविदाएँ किसी भी समय रद्द करने का पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित रहेगा। सामग्री खरींद की अंतिम मूल्य/निर्णय विभाग की JUSTIFICATION व अनुमोदित निविदाओं के साथ NEGOTITION अनुसार ही किया जायेगा।

प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत खलवाहण विकास खण्ड बालीचौकी जिल मण्डी (हि0प्र0)

कार्यालय ग्राम पंचायत खौली
विकास खंड बालीचौकी, जिला मंडी (हि.प्र.)

निविदा सूचना

आज की बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि वर्ष 26-27' के लिये विभिन्न प्रकार की सामग्री की कुटेशन आमंत्रित करने की आवश्यकता है। इस प्रस्ताब पर चर्चा हुई। चर्चा उपरान्त प्रस्ताव सर्वसमिति से पारित किया गया कि निम्न प्रकार की सामग्री की कुटेशन आमत्रित की जाती है; रेत (क्रशर), रेत (खड्डु), बजरी, सीमेंट ढलवान बालीचौकी गोदाम से पंचायत के स्टोर तक, इंट, लोकल स्टोन, सरिया, पेवर, sign बोर्ड (कंक्रीट), क्रेट वायर, लकड़ी के दरवाजे व खिड़की, लोहे के दरवाजे व खिड़की, ग्रील एंगल, ERW पाइप्स, बेंच, डस्टबिन, जीप कैरिज, GI शीट, शटरिंग, कार्यालय फर्नीचर, टाइलस बाथरूम व किचन बाली, रंग पेंट, JCB कटिंग कुबिक मीटर/प्रति घंटा, वाटर कूलर वाटर टैंक्स (स्टील) आदि । अन्य कुटेशन आवश्कयता अनुसार आमत्रित की जाएगी। **नियम व शर्ते –** 1. निविदाता के पास अपनी गाड़ी व GST नंबर का होना अति आवश्यक है। जिसकी स्वयं हस्ताक्षरित कॉपी कुटेशन के साथ लगायें। 2. आपूर्ति करता की खनन विभाग से M-FORM बिल के साथ जमा करना होगा। 3. CIB नरेगा गाइड अनुसार बनाने होंगे व कार्य स्थल में लगाने होंगे। 4. धरोहर राशि के रूप में 100000 रूपए का चेक कुटेशन के साथ लगायें। 5. कार्य में कोताही बरतने पर या समय पर वांछित सामग्री न पहुँचाने पर धरोहर राशि जब्त की जाएगी 6. सामग्री की गुणवता अच्छी होनी चाहिय। गुणवता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। 7. अगर समय सीमा के भीतर सामग्री नही पहुंचाई जाति है तो बिना पूर्व सुचना के कुटेशन रद्द की जाएगी। तथा अगले वेंडर को सप्लाई ऑर्डर दिया जायेगा। 8. सविकृत निविदाता को पंचायत के साथ अनुबंध करना होगा। 9. कुटेशन बंद लिफाफे में डाक द्वारा दिनांक 24.07.26 को सायं 5 बजे तक पंचायत कार्यालय में पहुंचनी चाहिए । जो 25.07.26. को पंचायत पदाधिकारियो के समक्ष खोली जाएगी । निर्धारित अबधि के बाद कुटेशन मान्य नही होगी। 10. अन्य कुटेशन आवयश्कता अनुसार आमंत्रित की जाएगी।

प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत खौली
विकास खंड बालीचौकी , जिला मंडी (हि.प्र.)

कार्यालय ग्राम पंचायत जफरकोट
विकास खंड बालीचौकी , जिला मंडी (हि.प्र.)

निविदा सूचना

आज की बैठक में वर्ष 206-27 के लिए निविदा आमन्त्रण वारे प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव पर बैठक में विचार-विमर्श किया गया तथा विचार-विमर्श के वाद सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि वर्ष 2026-27 के लिए निविदा आमंत्रित करनी उचित है। सभी इच्छुक निविदादाता/सेवा प्रदाता को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026-27 निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। सभी से निवेदन है कि दिनांक 24/07/2026 शाम 4 बजे तक निविदाएं सील बंद लिफाफे में ग्राम पंचायत जुफरकोट में पहुंच जानी चाहिए । इस तिथि व समय के बाद किसी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा । सभी अपने आवेदन पंजीकृत डाक माध्यम से भेजें। हाथ दस्ती आवेदन प्राप्त नहीं होंगे। दिनांक 25/07/2026 को निविदादाओं को ग्राम पंचायत द्वारा अधिकृत समिति द्वारा खोला जाएगा। सामग्री का पूर्ण विवरण इस प्रकार से है :-1.रेत (Water Borne)- m² में 2. रेत (क्रशर)-m² में 3. बजरी (krusher)-m² में 4. लोकल पत्थर transportation-m² में 5. इंटें (मिटटी के भठे की)-दर प्रति ईंट 6. सीमेंट ढुलान बालीचौकी से-दर प्रति बैग 7. JCB Cutting और Stone breaking-m³ में 8. sign Board- 2x3sq ft, 3x4sq ft 9. Steel साइज़ वार-प्रति किलो ग्राम 10. GI SHEET छत बाली-प्रति शीट 11. शटरिंग किराया- sq feet 12. ग्रिल लोहा-प्रति किलोग्राम 13. रेत बजरी सीमेंट खच्चर ढलवान-प्रति फुट/प्रति बैग/प्रति मीटर। **शर्तेः–**1. निविधादाताओं के पास अपनी गाड़ी होनी अनिवार्य है जिसकी RC आवेदन पत्र के साथ सलंग्र करनी आवश्यक है। 2. निविदादाता का अपना पंजीयन पैन संख्य GST नम्बर होना चाहिए । 3. GST या CGST निविदा के साथ व सामग्री के साथ मूल्य सहित स्पष्ट रूप से दर्शायें । 4. बिल वाउचर के साथ रूफॉर्म लगवाना आवश्यक है । 5. अनुमोदित निविदादाता को धरोहर राशि के तौर पर 5000 रूपये पंचायत कार्यालय में जमा करने होंगे । 6. सामग्री की गुणवता से कोई समझोता नहीं होगा । आवेदन को रद्द करने का अधिकार पंचायत के पास सुरक्षित है। 7. अगर सामग्री की आपूर्ति समय पर नहीं की जाती है टो विना पूर्व सुचना के उसका अनुबंध रद्द किया जायेगा।

प्रधान / सचिव ग्राम पंचायत जफरकोट
विकास खंड बालीचौकी , जिला मंडी (हि.प्र.)

उत्तराखंड की नई खेल नीति में जनता की भागीदारी तय

खेल मंत्री रेखा आर्या की पहल, नई खेल नीति में खिलाड़ियों के विकास पर रहेगा जोर

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की नई खेल नीति तैयार करने की प्रक्रिया को और व्यापक बनाते हुए इसमें आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। खेल विभाग ने प्रदेशवासियों से 30 जुलाई 2026 तक सुझाव आमंत्रित किए हैं। सरकार का उद्देश्य ऐसी खेल नीति तैयार करना है जो राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, खिलाड़ियों की जरूरतों और भविष्य की खेल संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाए। इस पहल के माध्यम से सरकार खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल विशेषज्ञों, खेल संघों, अभिभावकों, शिक्षकों और आम नागरिकों को नीति निर्माण प्रक्रिया से जोड़ना चाहती है।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि नई खेल नीति केवल सरकारी स्तर पर तैयार किया जाने वाला दस्तावेज नहीं होगी बल्कि इसमें प्रदेश के लोगों की राय और अनुभवों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनता से प्राप्त उपयोगी सुझावों का विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किया जाएगा और जो सुझाव प्रदेश के खेल विकास के लिए बेहतर होंगे उन्हें नई नीति में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही उत्कृष्ट सुझाव देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा।

खेल मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ऐसी खेल नीति बनाना है जिससे उत्तराखंड के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं और अवसर मिल सकें। प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है लेकिन कई बार संसाधनों और उचित मार्गदर्शन के अभाव में खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाते।

नई खेल नीति के माध्यम से इन चुनौतियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों और दूरदराज के इलाकों में छिपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाया जाए और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर मिले।

उत्तराखंड में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों की अलग-अलग परिस्थितियां हैं। ऐसे में राज्य की खेल नीति को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप तैयार करना आवश्यक है।

उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम, नई खेल नीति के लिए प्रदेशवासियों से मांगे गए सुझाव

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों, खेल मैदानों और सुविधाओं का विस्तार करना नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में मौजूद खेल संसाधनों को और बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जा सकता है। जनता से मिलने वाले सुझावों से सरकार को जमीनी स्तर की समस्याओं और संभावनाओं को समझने में मदद मिलेगी।

खेल नीति में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, खेल उपकरणों की उपलब्धता, प्रशिक्षकों की भूमिका, खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन, खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसर जैसे विषयों को शामिल किए जाने की संभावना है। इसके अलावा महिला खिलाड़ियों, दिव्यांग खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधानों पर भी विचार किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि नई नीति खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास का आधार बने।

खेल विभाग ने सुझाव भेजने के

◆खेल विभाग ने खोला सुझावों का रास्ता

लिए ऑनलाइन माध्यम, ईमेल और डाक की सुविधा उपलब्ध कराई है। इससे प्रदेश के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोग अपनी राय सरकार तक पहुंचा सकते हैं। खिलाड़ी अपने अनुभवों के आधार पर सुझाव दे सकते हैं जबकि प्रशिक्षक और खेल विशेषज्ञ तकनीकी सुधारों को लेकर अपनी राय साझा कर सकते हैं। अभिभावक और शिक्षक भी युवा खिलाड़ियों के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं। सरकार का मानना है कि खेल केवल प्रतियोगिता का माध्यम नहीं बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास, अनुशासन और स्वास्थ्य से भी जुड़ा विषय है।

नाबार्ड ने बांटी 5,061 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता

उत्तराखंड में नाबार्ड बना ग्रामीण परिवर्तन का मजबूत भागीदार

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित उत्तराखंड क्षेत्रीय कार्यालय में विशेष समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत रहे। समारोह में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रतिनिधि, ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों के अधिकारी, कृषक उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमीनी स्तर पर ऋण प्रवाह बढ़ाने के विषय पर पैनल चर्चा आयोजित की गई। इसमें कृषि ऋण, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों तक बेहतर वित्तीय सुविधाएं पहुंचाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर नाबार्ड की 45 वर्षों की विकास यात्रा और उत्तराखंड क्षेत्रीय कार्यालय की वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों की जानकारी भी दी गई।

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने नाबार्ड को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संस्था ने पिछले 45 वर्षों में कृषि, ग्रामीण विकास और जनजातीय क्षेत्रों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड ने दूरस्थ क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन, आधारभूत संरचना विकास और सामुदायिक विकास के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है।

उन्होंने कृषक उत्पादक संगठनों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने, सामूहिक विपणन को मजबूत करने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने में नाबार्ड की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि नाबार्ड के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ है और सहकारी बैंकों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया है।

नाबार्ड स्थापना दिवस समारोह में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित करते अधिकारी।

नाबार्ड ने बदली ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक पंकज यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 उत्तराखंड क्षेत्रीय कार्यालय के लिए उपलब्धियों से भरा रहा। इस दौरान राज्य में 5,061 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 4,179 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त दिया गया, जबकि ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत 743 करोड़ रुपये की स्वीकृति और 754 करोड़ रुपये का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि नाबार्ड वित्तीय सहायता देने वाली संस्था है।

देहरादून में अनुसूचित जाति के 465 युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर

कौशल विकास और स्वरोजगार से जुड़ेंगे 465 एससी युवा

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। देहरादून में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 124.94 लाख रुपये की जिला कार्ययोजना को जिलाधिकारी आशीष चौहान ने मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना को अब अंतिम स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा गया है। योजना के क्रियान्वयन से जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के 465 युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास का लाभ मिलेगा।

'ग्रांट-इन-एड' घटक के तहत तैयार की गई कार्ययोजना का मुख्य उद्देश्य जिले के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अंतर्गत 175 बेरोजगार अनुसूचित जाति के युवक-युवतियों को अपना व्यवसाय शुरू करने या स्वरोजगार अपनाने के लिए 87.55 लाख रुपये की अनुदान (सब्सिडी) सहायता प्रदान की जाएगी। स्वरोजगार के साथ-साथ 290 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आज के बाजार की मांग के अनुरूप रोजगारपरक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह ट्रेनिंग प्रतिष्ठित और अधिकृत स्वैच्छिक संस्थाओं के जरिए दिलवाई जाएगी ताकि युवाओं को आसानी से रोजगार मिल सके।

इस संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि शासन से हरी झंडी मिलते ही लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता और तय मानकों के आधार पर किया जाए, ताकि योजना का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक समय पर पहुंच सके।

युवाओं के लिए 125 लाख रुपए की योजना मंजूर

जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि विभाग इस कार्ययोजना को केंद्र सरकार के समक्ष अंतिम मंजूरी के लिए भेज रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वहां से स्वीकृति मिलते ही पात्र युवाओं के चयन, उनकी ट्रेनिंग और स्वरोजगार के लिए अनुदान बांटने का काम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा।

विभाग का पूरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ा जाए।

भवाली पोक्सो केस में आज फिर होगी सुनवाई

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। भवाली के चर्चित यौन शोषण प्रकरण में एक नया घटनाक्रम सामने आया है। मामले में पहली शिकायतकर्ता युवती को मंगलवार को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) के अवकाश पर होने के कारण पुलिस की रिमांड अर्जी पर सुनवाई प्रभारी न्यायाधीश ने की और एक दिन की रिमांड मंजूर कर दी। मामले में अब बुधवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत में आगे की सुनवाई होगी।

पुलिस के अनुसार व्यापारी नेता नरेश पांडे प्रकरण में दूसरी युवती की शिकायत के आधार पर पहली शिकायतकर्ता युवती के विरुद्ध भी पॉक्सो अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है। विवेचना के दौरान आवश्यक पूछताछ और साक्ष्य संकलन के लिए पुलिस ने रिमांड का अनुरोध किया था, जिसे प्रभारी न्यायाधीश ने एक दिन के लिए स्वीकार कर लिया। बताया गया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एक दिन के अवकाश पर होने के कारण रिमांड की कार्यवाही प्रभारी न्यायाधीश के समक्ष हुई। अब आज विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) के न्यायालय में पुलिस आवश्यकतानुसार आगे की रिमांड बढ़ाने का अनुरोध कर सकती है।

उत्तराखंड में बढ़े मतदान केंद्र, अब 12,543 केंद्रों पर होगा मतदान

हरिद्वार देहरादून और ऊधमसिंह नगर में सबसे ज्यादा मतदाता दर्ज

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के पहले चरण के बाद चुनाव आयोग ने मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने देहरादून में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान प्राप्त फॉर्म की जांच में करीब 19 लाख मतदाताओं के विवरण में कुछ विसंगतियां सामने आई हैं। ऐसे मतदाताओं को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी किए जाएंगे।

अधिकारियों के अनुसार नोटिस जारी होने के बाद मतदाताओं को अपनी जानकारी स्पष्ट करने और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। मतदाता सूची से जुड़ी आपत्तियों और दावों का निपटारा 11 सितंबर तक किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सुनवाई की प्रक्रिया न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित की जाएगी ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

प्रेस वार्ता में अधिकारियों ने योजनाओं और आगामी कार्यक्रमों की दी जानकारी।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 71 लाख 33 हजार 785 मतदाता शामिल हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 37 लाख 23 हजार है जबकि महिला मतदाताओं की संख्या करीब 34 लाख 23 हजार है। मतदाता सूची में पुरुष मतदाताओं की हिस्सेदारी लगभग 52 प्रतिशत और महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 47 प्रतिशत है।

जिलेवार आंकड़ों के अनुसार हरिद्वार में सबसे अधिक 12 लाख 45 हजार मतदाता दर्ज हैं। इसके बाद देहरादून में करीब 11 लाख 90 हजार और ऊधमसिंह नगर में लगभग 11 लाख 55 हजार मतदाता शामिल हैं। वहीं पर्वतीय जिलों में रुद्रप्रयाग में करीब 1 लाख 80 हजार, चंपावत में 1 लाख 88 हजार और बागेश्वर में 2 लाख से अधिक मतदाता दर्ज किए गए हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि मतदाता सूची को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए मतदान केंद्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में पहले 11,733 मतदान केंद्र थे, जिनकी संख्या बढ़ाकर 12,543 कर दी गई है।

रानीखेत सोमनाथ मैदान में होगी सेना भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। भारतीय सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा ने भर्ती वर्ष 2027 के तहत आयोजित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का परिणाम जारी होने की जानकारी दी है। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम जांच लें।

भर्ती कार्यालय ने बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों के केंद्रीय श्रेणी के अभ्यर्थियों तथा जोनल श्रेणी के सिपाही फार्मा और नर्सिंग असिस्टेंट पदों के उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड के अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिलों के अग्निवीर श्रेणी के अभ्यर्थी भी इसमें शामिल होंगे।

शारीरिक दक्षता परीक्षा 27 जुलाई से 9 अगस्त तक रानीखेत के सोमनाथ मैदान में आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना जरूरी दस्तावेजों के किसी भी अभ्यर्थी को भर्ती रैली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ तीन प्रतियां और हाल की 20 पासपोर्ट साइज फोटो लाने के निर्देश दिए गए हैं। आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और पुलिस सत्यापन जैसे दस्तावेज अनिवार्य होंगे। सेना ने चेतावनी दी है कि नकली दस्तावेज प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

भारतीय सशस्त्र बलों की मजबूती पर दोनो ने साझा किए विचार

राज्यपाल गुरमीत सिंह से मिले सीडीएस जनरल राजा सुब्रमणि, राष्ट्रीय सुरक्षा पर हुई चर्चा

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) से मंगलवार को नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा तैयारियों और वर्तमान रणनीतिक परिस्थितियों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सीडीएस जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि को नया दायित्व संभालने पर बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि जनरल राजा सुब्रमणि का लंबा सैन्य अनुभव, कुशल नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शी सोच भारतीय सशस्त्र बलों को नई दिशा प्रदान करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में देश की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा सेना की गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

बैठक के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा हालात और बदलती वैश्विक परिस्थितियों पर भी विचार-विमर्श किया गया। दोनों अधिकारियों ने देश की रक्षा क्षमता को मजबूत करने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियों की आवश्यकता पर चर्चा की।

रुद्रप्रयाग पुलिस की साप्ताहिक परेड संपन्न

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। रुद्रप्रयाग में पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य, शारीरिक क्षमता और मानसिक सजगता को बनाए रखने के उद्देश्य से रिजर्व पुलिस लाइन रतूड़ा में साप्ताहिक मंगलवार परेड का आयोजन किया गया। परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक विकास पुण्डीर ने किया। इस दौरान पुलिस जवानों से दौड़ लगवाई गई और प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में पीटी व विभिन्न शारीरिक अभ्यास कराए गए। परेड के बाद पुलिस उपाधीक्षक ने पुलिस लाइन परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि नियमित शारीरिक प्रशिक्षण से पुलिस बल की फिटनेस, अनुशासन और कार्यक्षमता मजबूत होती है, जिससे जवान बेहतर तरीके से जनसेवा कर सकते हैं।

भारत-यूके व्यापार समझौते से खुलेंगे नए अवसर, युवाओं को मिलेगा बड़ा लाभ

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू होने के साथ ही भारतीय व्यापार जगत के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से छोटे व्यवसायों, किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, युवाओं और श्रम आधारित उद्योगों को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने इसे भारत का सबसे व्यापक मुक्त व्यापार समझौता बताते हुए कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी।

इस समझौते के तहत ब्रिटेन को किए जाने वाले भारत के लगभग सभी निर्यात पर सीमा शुल्क में राहत मिलेगी। इससे भारतीय निर्माताओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा और उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। सरकार का मानना है कि यह समझौता भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को गति देने में सहायक होगा।

रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, वस्त्र, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य श्रम आधारित क्षेत्रों को इस समझौते से विशेष फायदा मिलने की उम्मीद है। बेहतर बाजार पहुंच के कारण इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सेवा क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों को आईटी, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग और परामर्श जैसे क्षेत्रों में लाभ मिलने की संभावना है।

डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिपुर कला सीवर परियोजना में गुणवत्ता पर दिया जोर

सीवर परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश, डॉ. अग्रवाल ने कसा शिकंजा

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। ऋषिकेश विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश स्थित कैंप कार्यालय में हरिपुर कला क्षेत्र में चल रही सीवर लाइन परियोजना के कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी, परियोजना से जुड़े इंजीनियर, कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और समय सीमा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

डॉ. अग्रवाल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही और गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीवर लाइन परियोजना सीधे तौर पर जनता की सुविधाओं से जुड़ी हुई है, इसलिए इसमें पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सितंबर माह तक परियोजना का कार्य हर हाल में पूरा किया जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को जल्द राहत मिल सके।

जनहित के कार्यों को गति देने के लिए तैयार हो रही नई योजना।

उन्होंने हरिपुर कला की गली नंबर 5 में पुरानी सीवर लाइन को बदलने के निर्देश भी दिए। साथ ही पूर्व में क्षेत्र भ्रमण के दौरान दिए गए सड़क निर्माण और अन्य कार्यों को जल्द पूरा करने को कहा। बैठक में परियोजना निदेशक मीनाक्षी मित्तल ने बताया कि हरिपुर कला क्षेत्र में सीवर लाइन परियोजना के तहत सड़क निर्माण का करीब 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और बाकी कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

पौधरोपण हरेला पर्व से पहले मुख्यमंत्री धामी ने किया सघन पौधरोपण अभियान का शुभारंभ

सीएम धामी ने मालाग्राम में किया पौधरोपण, हरित उत्तराखंड का दिया संदेश

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। हरेला पर्व के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर स्थित मालाग्राम पहुंचकर सघन पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने स्वयं पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण और हरित उत्तराखंड के निर्माण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण सभी की जिम्मेदारी है और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर श्री धन्वंतरि धाम हर्बल वर्ल्ड हिमालय का भ्रमण भी किया। उन्होंने परिसर में संरक्षित दुर्लभ औषधीय वनस्पतियों, अनुसंधान कार्यों और आयुर्वेद आधारित नवाचारों की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने परिसर में स्थित ध्यान कुटी का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की समृद्ध जैव विविधता और हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली औषधीय वनस्पतियों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा केवल राज्य की नहीं बल्कि पूरे विश्व की अमूल्य धरोहर है। इसका संरक्षण, संवर्धन और वैज्ञानिक अध्ययन वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि औषधीय पौधों के संरक्षण और आयुर्वेद आधारित शोध को बढ़ावा देने से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि हर्बल पर्यटन और आयुर्वेदिक अनुसंधान के क्षेत्र में उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों को विकसित करने से स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

धरती मां के श्रृंगार के लिए लगाया गया हरियाली का पौधा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता बचाने और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पौधरोपण अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संकल्प है। उन्होंने प्रदेशवासियों से भी अपील की कि वे अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें।

हरेला पर्व उत्तराखंड की संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व के माध्यम से हर वर्ष लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला जैसे पर्व हमें पर्यावरण के महत्व को समझने और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं।

मोदी देंगे ट्राइसिटी को दो बड़ी सड़क परियोजनाओं की सौगात

जीरकपुर-पंचकूला बाइपास और आईटी सिटी-कुराली एक्सप्रेसवे से ट्राइसिटी में जाम घटेगा, यात्रा होगी तेज और सुगम

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

ट्राइसिटी में वर्षों से लोगों के लिए बड़ी परेशानी बने ट्रैफिक जाम से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को चंडीगढ़ दौरे के दौरान 3,500 करोड़ रुपये से अधिक की दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें 1,983 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले जीरकपुर-पंचकूला बाइपास का शिलान्यास तथा 1,525.30 करोड़ रुपये की लागत से तैयार आईटी सिटी-कुराली एक्सप्रेसवे का उद्घाटन शामिल है। इन दोनों परियोजनाओं के शुरू होने से ट्राइसिटी की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। साथ ही उद्योग, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलेगी।

जीरकपुर-पंचकूला बाइपास लंबे समय से क्षेत्र की प्रमुख जरूरत माना जा रहा था। लगभग 19.2 किलोमीटर लंबा यह छह लेन का बाइपास राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर जीरकपुर-पटियाला जंक्शन से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर जीरकपुर-परवाणू जंक्शन तक जाएगा। इस परियोजना में लगभग 6.195 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड सेक्शन, कई फ्लाईओवर, अंडरपास और रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिससे यातायात बिना किसी बाधा के सुचारु रूप से चल सकेगा।

वर्तमान में दिल्ली, अंबाला, पंचकूला, बद्दी, परवाणू और शिमला की ओर जाने वाले हजारों वाहन प्रतिदिन जीरकपुर शहर से होकर गुजरते हैं। इसके कारण शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों पर सुबह से देर शाम तक लंबा जाम लगा रहता है। बाइपास बनने के बाद बाहरी राज्यों की ओर जाने वाले वाहनों को शहर के भीतर प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। इससे स्थानीय लोगों को जाम से राहत मिलेगी और शहर के भीतर यातायात अधिक व्यवस्थित होगा।

प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान आईटी सिटी-कुराली एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन किया जाएगा। लगभग 1,525.30 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह छह लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आधुनिक तकनीक के अनुरूप विकसित किया गया है। इस मार्ग पर किसी भी प्रकार का ट्रैफिक सिग्नल नहीं होगा, जिससे वाहन लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुरक्षित और निर्बाध सफर कर सकेंगे।

इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से मोहाली, न्यू चंडीगढ़ और कुराली के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। रोजाना आने-जाने वाले कर्मचारियों, विद्यार्थियों, उद्योगपतियों और व्यापारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही आईटी सेक्टर, औद्योगिक इकाइयों और रियल एस्टेट परियोजनाओं को भी बेहतर सड़क संपर्क मिलने से विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी।

दोनों परियोजनाएं प्रस्तावित 244 किलोमीटर लंबे ट्राइसिटी रिंग रोड नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इस नेटवर्क का उद्देश्य ट्राइसिटी क्षेत्र में बढ़ते वाहनों के दबाव को कम करना और विभिन्न शहरों के बीच तेज, सुरक्षित तथा सुगम यातायात उपलब्ध कराना है। परियोजनाओं के पूरा होने के बाद शहर के भीतर गैर-स्थानीय और भारी वाहनों की आवाजाही कम होगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने और यातायात व्यवस्था बेहतर होने की संभावना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन परियोजनाओं से ईंधन की बचत होगी, यात्रा का समय घटेगा और प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी। माल परिवहन तेज होने से उद्योगों की लागत कम होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

डेरा समर्थकों को हाई कोर्ट से राहत हरियाणा सरकार की अपील खारिज

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के समर्थकों को बड़ी राहत देते हुए अगस्त 2017 की हिंसा और आगजनी से जुड़े एक मामले में ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह असफल रहा। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

यह मामला 25 अगस्त 2017 का है, जब साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को दोषी ठहराए जाने के बाद हरियाणा के कई जिलों में व्यापक हिंसा और आगजनी हुई थी। आरोप था कि कैथल जिले के कलायत स्थित उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) कार्यालय पर डेरा समर्थकों की भीड़ ने हमला किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने लाठी-डंडों और पेट्रोल बमों के साथ कार्यालय में तोड़फोड़ की और भवन को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ देशद्रोह, आगजनी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 2019 में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के आधार पर आरोपित धर्मपाल, जसबीर, शिव कुमार और बलबीर को बरी कर दिया था। इसके खिलाफ हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अपील दायर की थी और ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

न्यूज ब्रीफ

टूटे बेंचों से परेशान ढकोली पार्क के लोग

भारतेन्दु संवाददाता, जीरकपुर। ढकोली के कृष्णा एनक्लेव कॉलोनी स्थित म्युनिसिपल पार्क में टूटे बेंच लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। पार्क में सुबह-शाम सैर करने आने वाले बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है। कई बेंचों की लकड़ियां और लोहे के हिस्से टूट चुके हैं, जबकि कुछ बेंच इतने खराब हो चुके हैं कि उन पर बैठना जोखिम भरा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पार्क की नियमित देखभाल नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि बुजुर्गों को चोट लगने के डर से खड़े रहना पड़ता है और बच्चों को भी टूटे बेंचों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। लोगों ने प्रशासन से जल्द बेंचों की मरम्मत करवाने और पार्क की सुविधाएं बेहतर करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो लोग पार्क आना कम कर देंगे।

700 ग्राम चरस मामले में आरोपी को चार साल की सजा

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। विशेष एनडीपीएस अदालत ने हिमाचल प्रदेश निवासी सुनील ठाकुर को 700 ग्राम चरस रखने के मामले में दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला वर्ष 2019 का है, जब एसटीएफ फेज-4 मोहाली को सूचना मिली थी कि सुनील ठाकुर चरस लेकर ढकोली बस स्टैंड पहुंच रहा है। पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया और तलाशी के दौरान उसके बैग से 700 ग्राम चरस बरामद की। जांच में फोरेंसिक रिपोर्ट ने भी बरामद पदार्थ को चरस बताया। अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस के निर्देशों और साक्ष्य की पूरी प्रक्रिया विश्वसनीय रही।

ऑनलाइन सट्टेबाजी ठगी में दो लोगों पर केस

भारतेन्दु संवाददाता, जीरकपुर। पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के नाम पर लोगों से ठगी करने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान हरियाणा के यमुनानगर निवासी देव वर्मा और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी अनुज के रूप में हुई है। दोनों आरोपी वर्तमान में जीरकपुर के साउथ सिटी में रह रहे थे। पुलिस के अनुसार, गश्त के दौरान कोहिनूर ढाबे के पास सूचना मिली थी कि साउथ सिटी स्थित एक फ्लैट में रहने वाले दोनों व्यक्ति लोगों को क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टा लगाने का लालच देकर ठगी करते हैं। आरोप है कि आरोपी अधिक मुनाफे का झांसा देकर लोगों से पैसे अपने खातों में ट्रांसफर करवाते थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ जुआ अधिनियम की धाराओं और भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपों की पुष्टि के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है।

गोल्डी बराड़ के नाम पर तीन करोड़ रंगदारी

भारतेन्दु संवाददाता, खरड़। लांडरां के ट्रांसपोर्टर रविंदर सिंह को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम पर तीन करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और परिवार सहित जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। पीड़ित के अनुसार, उन्हें विदेशी नंबरों से लगातार व्हाट्सएप कॉल, वॉयस मैसेज और धमकी भरे संदेश भेजे जा रहे हैं। सदर खरड़ थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस विदेशी नंबरों की तकनीकी जांच और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है। पीड़ित ने हाईकोर्ट में भी सुरक्षा की मांग की थी। अदालत ने अधिकारियों को मामले पर जल्द निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

विधानसभा चुनावों से पहले मोहाली नगर निगम ने 42 विकास कार्यों के टेंडर किए जारी

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली।

विधानसभा चुनावों से पहले विकास कार्यों में तेजी लाते हुए नगर निगम मोहाली ने शहर और आसपास के क्षेत्रों के लिए 42 विकास परियोजनाओं के टेंडर जारी किए हैं। इन कार्यों में ग्रीन बेल्टों का सौंदर्यीकरण, पार्कों का विकास, औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क और पेवर ब्लॉक निर्माण, रोड सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, फुटपाथ, नए ट्यूबवेल, नगर निगम भवन का नवीनीकरण और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं।

नगर निगम का मुख्य फोकस शहर की हरियाली बढ़ाने, पेयजल व्यवस्था मजबूत करने और आधारभूत सुविधाओं में सुधार पर है। फेज-2, फेज-4, सेक्टर-57 और सेक्टर-78 के पार्कों के विकास के साथ औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क सुधार कार्य भी किए जाएंगे। इसके अलावा संभालकी, कम्बाली, लखनौर, चपरचिरी, बल्लोमाजरा, बलियाली, बलोंगी, लांडरां, ग्रीन एन्क्लेव और रुड़का समेत कई गांवों में नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। निगम का दावा है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से शहर की यातायात, पेयजल और हरित क्षेत्र संबंधी सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा।

विकास कार्यों की होगी नियमित निगरानी

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार सभी विकास कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे कराने के लिए संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चरणबद्ध तरीके से कार्य शुरू होंगे और उनकी नियमित निगरानी की जाएगी। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी टीम समय-समय पर निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी, ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही या मानकों से समझौता न हो। अधिकारियों का कहना है कि शहर की लगातार बढ़ती आबादी और नए विकसित हो रहे रिहायशी क्षेत्रों को देखते हुए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार आवश्यक हो गया है। इसी उद्देश्य से पेयजल आपूर्ति मजबूत करने के लिए नए ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, जबकि ग्रीन बेल्ट और पार्कों के विकास से पर्यावरण संरक्षण के साथ नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक स्थल उपलब्ध होंगे। औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कें, पेवर ब्लॉक और रोड सेफ्टी से जुड़े कार्य पूरे होने से माल परिवहन सुगम होगा और उद्यमियों को भी राहत मिलेगी।

विवाह साबित नहीं फिर भी महिला को मिला संपत्ति का अधिकार

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहते हैं तो कानून उनके रिश्ते को विवाह मानने की धारणा बनाता है। केवल इस आधार पर किसी महिला के अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता कि उसका विधिवत विवाह साबित नहीं हुआ है। अदालत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यक्ति के नाम वसीयत कर सकता है।

हाईकोर्ट ने यह फैसला यमुनानगर जिले के गांव सांखेड़ा की 23 बीघा कृषि भूमि से जुड़े 34 वर्ष पुराने विवाद में सुनाया है। न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने सुरमुख सिंह और अन्य की दूसरी अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत और प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले को बरकरार रखा। मामले में अपीलकर्ताओं का दावा था कि विवादित जमीन उनके पिता विशन सिंह की पैतृक संपत्ति थी। उनका तर्क था कि विशन सिंह जाट समुदाय से संबंधित थे और सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार वह पैतृक संपत्ति कथित पत्नी देवो के नाम वसीयत नहीं कर सकते थे। उन्होंने यह भी कहा था कि देवो उनकी कानूनी पत्नी नहीं थीं, इसलिए उनके पक्ष में की गई वसीयत और सहमति डिक्री अवैध है।

हाईकोर्ट ने मामले के दस्तावेजों और गवाहों के बयानों की जांच के बाद पाया कि 15 मार्च 1976 को पंजीकृत वसीयत कानूनी प्रक्रिया के अनुसार साबित हुई थी। वसीयत के गवाहों के बयान विश्वसनीय थे और दस्तावेज का नोटरी प्रमाणीकरण भी मौजूद था। अदालत ने कहा कि वसीयत को चुनौती देने वालों के पास अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है।

पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि देवो लंबे समय तक विशन सिंह के साथ रहीं और उनकी देखभाल करती रहीं। विशन सिंह ने अपने जीवनकाल में कभी भी उनके संबंधों से इनकार नहीं किया।

स्कूलों और कोचिंग केंद्रों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर हाई कोर्ट सख्त

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब में स्कूलों और कोचिंग सेंटरों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) को 10 अगस्त तक स्कूलों एवं कोचिंग संस्थानों में उपलब्ध फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट तैयार कर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी। इस प्रक्रिया के तहत सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों का सुरक्षा ऑडिट तेज कर दिया गया है।

यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद शुरू की गई है। अदालत ने राज्य सरकार को सभी शैक्षणिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की समीक्षा कर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए थे। इसके बाद संबंधित विभागों ने जिला स्तर पर निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है। ऑडिट के दौरान यह परखा जा रहा है कि संस्थानों में आग जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सुरक्षा इंतजाम मौजूद हैं या नहीं।

हाल ही में लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना के बाद देशभर में शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने भी स्कूलों और कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानकों का गंभीरता से परीक्षण शुरू किया है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

निरीक्षण के दौरान संस्थानों में लगाए गए अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता और उनकी कार्यशीलता की जांच की जा रही है। इसके अलावा फायर अलार्म सिस्टम, हाइड्रेंट व्यवस्था, आपातकालीन निकास मार्ग, विद्युत वायरिंग, भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा तथा आग लगने की स्थिति में विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकालने की तैयारियों का भी आकलन किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा यह भी देखा जा रहा है कि सुरक्षा उपकरणों का समय-समय पर रखरखाव किया जा रहा है या नहीं।

पंजाब के लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला, मोहाली और बठिंडा जैसे बड़े शहरों में बड़ी संख्या में निजी स्कूल और कोचिंग संस्थान संचालित हैं। इन संस्थानों में प्रतिदिन हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन का मानना है कि सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। इसलिए सभी संस्थानों को निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार किसी भी स्कूल या शैक्षणिक संस्थान को मान्यता देने से पहले निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होता है।

बारिश के बाद बढ़ा वायरल बुखार, स्वास्थ्य चिंता गहराई

भारतेन्दु संवाददाता, जीरकपुर।

लगातार बारिश के बाद शहर में जलभराव और क्षतिग्रस्त सड़कों की समस्या अब लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डालने लगी है। सरकारी और निजी अस्पतालों में सर्दी, जुकाम, खांसी, वायरल बुखार तथा गले के संक्रमण से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मौसम में बदलाव और जगह-जगह जमा गंदे पानी के कारण संक्रमण फैलने की आशंका भी बढ़ गई है।

बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को साफ-सफाई बनाए रखने, उबला या स्वच्छ पानी पीने, संतुलित भोजन करने और बुखार या संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर

गड्ढों में जमा पानी बना बीमारी का कारण बढ़ा डेंगू का खतरा

बारिश के कारण शहर की कई मुख्य और आंतरिक सड़कें उखड़कर गहरे गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। इन गड्ढों में पानी भरने से मच्छरों और मक्खियों का प्रकोप बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय तक पानी जमा रहने से डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की है। ढकोली के एसएमओ डॉ. गगनदीप सिंह शेरगिल ने स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि सर्दी, बुखार और वायरल संक्रमण के मरीजों का बिना देरी उपचार सुनिश्चित किया जाए।

गहरे गड्ढों से बदहाल वीआईपी रोड रोजाना जाम और हादसों का खतरा

भारतेन्दु संवाददाता, जीरकपुर

शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में शामिल वीआईपी रोड की बदहाल स्थिति लोगों के लिए लगातार परेशानी का कारण बनी हुई है। सड़क पर जगह-जगह बने गहरे गड्ढों के कारण रोजाना हजारों वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया है। ऐसे में हर दिन इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को जाम, धीमी रफ्तार और दुर्घटना के खतरे के बीच सफर करना पड़ रहा है।

बारिश के मौसम में स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई दिखाई नहीं देती, जिससे विशेषकर दोपहिया वाहन चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं। कई बार वाहन गड्ढों में फंस जाते हैं, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग जाता है और लोगों का समय भी बर्बाद होता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क की खराब

हालत के कारण रोजाना दुर्घटना का खतरा बना रहता है।

वीआईपी रोड जीरकपुर की प्रमुख संपर्क सड़क है, जो चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली को जोड़ती है। प्रतिदिन हजारों निजी वाहन, स्कूल बसें, टैक्सियां और व्यावसायिक वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। इसके बावजूद सड़क की नियमित मरम्मत नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि कई स्थानों पर केवल औपचारिक पैचवर्क किया गया, जो कुछ दिनों बाद फिर उखड़ गया और समस्या पहले जैसी हो गई।

नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के कारण फिलहाल सड़क निर्माण और मरम्मत का कार्य पूरी तरह शुरू नहीं किया जा सकता। हालांकि संबंधित अधिकारियों को सड़क के खराब हिस्सों की पहचान कर आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए हैं। जीरकपुर नगर परिषद के एसडीओ विक्टर संधू ने बताया कि मौसम सामान्य होते ही सड़क की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम यातायात सुविधा मिल सके।

प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा तो कटेंगे पानी और सीवरेज कनेक्शन

व्यावसायिक संपत्तियों की होगी अटैचमेंट, आवासीय बकायेदारों के पानी और सीवरेज कनेक्शन काटने की तैयारी शुरू

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। लंबे समय से टैक्स जमा नहीं करने वाले आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति मालिकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। व्यावसायिक श्रेणी के डिफॉल्टरों की संपत्तियां अटैच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जबकि आवासीय श्रेणी के बकायेदारों के पानी और सीवरेज कनेक्शन काटने की तैयारी की जा रही है। निगम का कहना है कि अब टैक्स वसूली में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

नगर निगम ने पहले चरण में एक हजार से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके अलावा तीन हजार से अधिक अन्य बकायेदारों की सूची भी तैयार कर ली गई है। आने वाले दिनों में इन्हें भी नोटिस भेजे जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल निगम का काफी स्टाफ विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में व्यस्त है। यह कार्य पूरा होते ही

नोटिस जारी करने और वसूली अभियान को और तेज किया जाएगा।

निगम अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई पंजाब नगर निगम अधिनियम और प्रॉपर्टी टैक्स उपविधियों के तहत की जा रही है। टैक्स जमा करने की निर्धारित छूट अवधि समाप्त होने के बाद अब बकाया राशि पर 25 प्रतिशत जुर्माना और 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लगाया जा रहा है। ऐसे में जितनी देर होगी, बकायेदारों पर आर्थिक बोझ उतना ही बढ़ेगा।

इस वित्त वर्ष में नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स संग्रह के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। जून माह के अंत तक 76,344 करदाता अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा चुके हैं, जिससे निगम के खाते में लगभग 66 करोड़ रुपये की आय हुई है। इसके बावजूद निगम का मानना है कि अभी बड़ी संख्या में संपत्ति मालिकों ने टैक्स जमा नहीं कराया है, जिससे राजस्व का बड़ा हिस्सा बकाया बना हुआ है।

नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार शहर में लगभग 1.50 लाख प्रॉपर्टी टैक्सदाता हैं। इनमें करीब 1.20 लाख आवासीय और 30 हजार व्यावसायिक संपत्तियां शामिल हैं। इस हिसाब से अब तक लगभग आधे करदाताओं ने ही टैक्स जमा कराया है, जबकि शेष लोगों से वसूली की जानी बाकी है। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त डॉ. इंद्रजीत सिंह ने बताया कि टैक्स जमा नहीं करने वाले सभी डिफॉल्टरों को नियमानुसार नोटिस भेजे जा रहे हैं। यदि निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि जमा नहीं की गई तो व्यावसायिक संपत्तियों की अटैचमेंट और आवासीय संपत्तियों के पानी तथा सीवरेज कनेक्शन काटने जैसी कार्रवाई की जाएगी।

टैक्स बकायेदारों पर निगम सख्त

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार आगामी दिनों में वार्डवार विशेष वसूली अभियान भी चलाया जाएगा। इसके तहत सबसे पहले उन संपत्तियों को चिन्हित किया जाएगा, जिन पर लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। ऐसे मामलों में नोटिस की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि बार-बार सूचना देने के बावजूद टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे। निगम का मानना है कि प्रॉपर्टी टैक्स उसकी आय का प्रमुख स्रोत है। इसी राजस्व से शहर में सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था, सीवरेज नेटवर्क, पेयजल आपूर्ति, पार्कों के रखरखाव और अन्य विकास कार्यों पर खर्च किया जाता है। यदि बड़ी संख्या में करदाता समय पर टैक्स जमा नहीं करते हैं तो विकास परियोजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

गुरसिमरन मंड को विदेशी नंबरों से मिली परिवार समेत मारने की धमकी

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना

महानगर में एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय नंबरों से गैंगस्टरों के नाम पर धमकी मिलने का मामला सामने आया है। इस बार अंतरराष्ट्रीय एंटी-खालिस्तानी फ्रंट के प्रधान और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर गुरसिमरन सिंह मंड को निशाना बनाया गया है। अज्ञात लोगों ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर वाले नंबर से उनके मोबाइल पर धमकी भरे संदेश भेजे हैं। संदेशों में मंड और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सदर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गुरसिमरन सिंह मंड ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 2 जुलाई को जब वह लुधियाना में मौजूद थे, उस समय उनके मोबाइल नंबर पर एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप संदेश आया। जब उन्होंने नंबर की जानकारी जांची तो उस पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर लगी हुई थी। संदेश में उन्हें धमकी दी गई कि वह दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा।

शिकायतकर्ता के अनुसार, इसके बाद धमकी देने वालों ने लगातार अलग-अलग नंबरों से संदेश भेजना शुरू कर दिए। 3 जुलाई, 5 जुलाई और 13 जुलाई को भी उन्हें धमकी भरे संदेश मिले। आरोप है कि पुर्तगाल और सऊदी अरब के नंबरों के अलावा भारत के कुछ मोबाइल नंबरों से भी उन्हें कॉल और संदेश भेजे गए। लगातार मिल रही धमकियों से मंड और उनका परिवार दहशत में है।

मंड पहले से ही खालिस्तान समर्थक गतिविधियों और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। इसी कारण उन्हें पहले से पुलिस सुरक्षा मिली हुई है। धमकी की सूचना मिलने के बाद पुलिस विभाग में भी हलचल बढ़ गई। अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 के तहत आपराधिक धमकी और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धाराओं के तहत भी जांच की जा रही है। पुलिस की साइबर टीम धमकी देने वाले नंबरों की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इन नंबरों का इस्तेमाल कहां से और किसके द्वारा किया गया।

डिजिटल जांच हुई तेज

पुलिस अब धमकी भेजने वाले खातों और नंबरों की डिजिटल गतिविधियों की जांच कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि आरोपियों तक पहुंचने के लिए तकनीकी साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं।

पीएम मोदी के जालंधर दौरे से पहले चप्पे-चप्पे पर कड़ी सुरक्षा

भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई को प्रस्तावित जालंधर दौरे को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। उनके आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट, जालंधर ग्रामीण पुलिस और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहां से कार्यक्रम स्थल तक जाने वाले पूरे मार्ग की सुरक्षा को लेकर विशेष योजना तैयार की गई है। आदमपुर एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी जालंधर ग्रामीण पुलिस को सौंपी गई है।

◆जालंधर में हाई अलर्ट

जालंधर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह विर्क खुद सुरक्षा तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। वह लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं, शहर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह संभाल रहे हैं। उनके नेतृत्व में शहर के प्रमुख चौकों, संवेदनशील स्थानों, रेलवे स्टेशन, होटल, बस अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

पुलिस की ओर से जिले में लगातार गश्त की जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर नाके लगाए जा रहे हैं और आने-जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय है। उपायुक्त के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

आशु की पोस्ट से पंजाब कांग्रेस में हलचल

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना

पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी के बीच चन्नी को समर्थन

पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व और संगठन को लेकर चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता भारत भूषण आशु की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पार्टी के भीतर नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया है। आशु ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तस्वीर साझा करते हुए पंजाबी में संदेश लिखा, 'सारा पंजाब चन्नी नाल' यानी 'सारा पंजाब चन्नी के साथ'।

आशु की इस पोस्ट में चरणजीत सिंह चन्नी की बड़ी तस्वीर के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे चन्नी के समर्थन में एक बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस पोस्ट के जरिए चन्नी को पार्टी के भीतर व्यापक समर्थन मिलने का संकेत देने की कोशिश की गई है।

यह पोस्ट ऐसे समय सामने आई है, जब पंजाब कांग्रेस में संगठन को लेकर नेताओं के बीच मतभेद और गुटबाजी की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। पार्टी में नेतृत्व की भूमिका और भविष्य की रणनीति को लेकर अलग-अलग नेताओं के रुख सामने आते रहे हैं। भारत भूषण आशु और चरणजीत सिंह चन्नी की नजदीकियां पहले से ही राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय रही हैं। आशु को चन्नी गुट के प्रमुख नेताओं में गिना जाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह पोस्ट चन्नी खेमे की ताकत दिखाने और पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश हो सकती है।

हालांकि, कांग्रेस की ओर से अभी तक इस पोस्ट को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। लेकिन आशु की इस पोस्ट ने पंजाब कांग्रेस के अंदर चल रही सियासी गतिविधियों को फिर से चर्चा में ला दिया है। अब नजर इस बात पर है कि पार्टी हाईकमान इस राजनीतिक संकेत को किस तरह देखता है और आने वाले दिनों में पंजाब कांग्रेस की रणनीति क्या रहती है।

बेअदबी के आरोपित की तेजधार हथियार से हत्या

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में बेअदबी मामले के आरोपित मेवा सिंह की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। मंडी गोबिंदगढ़ के गांव लाडपुर तूरां में बीती रात हमलावरों ने तेजधार हथियारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हमले में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया और एक हाथ भी काट दिया गया।

प्रारंभिक जांच के अनुसार, मेवा सिंह कुछ समय पहले बेअदबी केस में जमानत पर जेल से बाहर आया था। मृतक की बेटी ने पुलिस को बताया कि रात के समय उसके पिता वाशरूम जाने के लिए कमरे से बाहर निकले थे। इसी दौरान उन्हें चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। परिवार के लोग बाहर आए तो देखा कि कुछ लोग मेवा सिंह पर हमला कर रहे थे।

बेटी के अनुसार, जब परिवार ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो हमलावरों ने उन पर भी हमला करने का प्रयास किया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। परिवार ने पुलिस को बताया कि उनकी किसी से कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। पुलिस के मुताबिक, मेवा सिंह के खिलाफ अक्टूबर 2020 में गांव तुर्रा स्थित गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच हाईकमान ने बुलाई बैठक

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब कांग्रेस में पिछले करीब दो सप्ताह से चल रहे अंदरूनी विवाद के बीच कांग्रेस हाईकमान की संभावित बैठक को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मुलाकात हो सकती है। इस बैठक में पंजाब कांग्रेस की मौजूदा स्थिति, संगठन में चल रही खींचतान और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है।

बताया जा रहा है कि राहुल गांधी विदेश दौरे से वापस लौट चुके हैं। ऐसे में उनकी खड़गे के साथ संभावित बैठक को पंजाब की राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी के भीतर उस समय से असंतोष बढ़ा हुआ है, जब राजा वड़िंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला लिया गया और नए पदाधिकारियों की सूची जारी की गई। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने संगठन में प्रतिनिधित्व को लेकर खुलकर नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद उन्होंने अपने समर्थक नेताओं के साथ कई बैठकें कीं और अपनी बात पार्टी हाईकमान तक पहुंचाने का प्रयास किया। चन्नी गुट की ओर से मांग की जा रही है कि संगठन में सभी वर्गों और नेताओं को संतुलित प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि पार्टी के अंदर एकजुटता बनी रहे।

इस बीच पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल भी चंडीगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी के विभिन्न नेताओं और गुटों के साथ बैठकें कर स्थिति को समझने की कोशिश की। बघेल ने दोनों पक्षों की राय सुनी और आपसी मतभेदों को खत्म करने का प्रयास किया। हालांकि, इन बैठकों के बाद भी पार्टी के अंदर चल रही खींचतान पूरी तरह समाप्त होती नजर नहीं आ रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पंजाब कांग्रेस में चल रहे विवाद का असर आगामी राजनीतिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। पार्टी नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन में संतुलन बनाए रखना और सभी नेताओं को साथ लेकर चलना है।

अब सभी की निगाहें दिल्ली पर टिकी हुई हैं। यदि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बैठक होती है तो इसमें पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी, संगठनात्मक बदलाव और आगे की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हो सकती है। साथ ही यह भी तय किया जा सकता है कि पार्टी में एकता बनाए रखने के लिए हाईकमान की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे। हालांकि, कांग्रेस हाईकमान की ओर से अभी तक इस संभावित बैठक या पंजाब से जुड़े किसी फैसले को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

तलवंडी साबो में जर्जर छत गिरने से मां-बेटे की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, बठिंडा

बठिंडा जिले के ऐतिहासिक नगर तलवंडी साबो में सोमवार देर रात एक दर्दनाक हादसे में जर्जर कमरे की छत गिरने से मां और बेटे की मौत हो गई, जबकि परिवार की दो बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों घायल बेटियों का इलाज एम्स बठिंडा में चल रहा है।

जानकारी के अनुसार, तलवंडी साबो निवासी धर्म सिंह उर्फ काला का परिवार रात करीब 11 बजे घर के एक कमरे में सो रहा था। अचानक कमरे की पुरानी छत भरभराकर गिर गई, जिससे परिवार के सभी सदस्य मलबे के नीचे दब गए। हादसे में धर्म सिंह की पत्नी वीरपाल कौर (40) और 14 वर्षीय बेटे अर्शदीप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के समय धर्म सिंह कमरे के बाहर सो रहे थे, जिससे उनकी जान बच गई। छत गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए दोनों बेटियों को एम्स बठिंडा रेफर किया गया।

स्थानीय लोगों के अनुसार, परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और मेहनत-मजदूरी कर जीवनयापन करता है। हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। नगर परिषद अध्यक्ष कुलवीर कौर सरां समेत कई जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर परिवार के प्रति संवेदना जताई। पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में जर्जर छत गिरने को हादसे का कारण माना जा रहा है।

न्यूज ब्रीफ

पानी संकट खत्म, श्रेय की राजनीति तेज

भारतेन्दु संवाददाता, बरनाला। शहीद भगत सिंह पार्क में लंबे समय से बंद पड़े ट्यूबवेल के दोबारा शुरू होने से वार्ड नंबर 29 और 41 के लोगों को पेयजल संकट से राहत मिली है। हालांकि इसके साथ ही भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं में इस कार्य का श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। नेताओं ने सोशल मीडिया पर इसे अपने प्रयासों की सफलता बताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सबसे बड़ी बात पानी की समस्या का समाधान होना है। उन्होंने नेताओं से राजनीतिक श्रेय की बजाय शहर की अन्य समस्याओं पर ध्यान देने की अपील की है।

गदाईपुर नहर में गंदा पानी छोड़ने का आरोप

भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर। कालिया कॉलोनी के पीछे स्थित गदाईपुर नहर में गंदा पानी छोड़े जाने का मामला सामने आया है। वार्ड नंबर-1 के पार्षद आशू शर्मा ने नगर निगम प्रशासन से मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है। पार्षद का आरोप है कि कुछ अज्ञात लोग लगातार नहर में गंदा पानी डाल रहे हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है और आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने नगर निगम कमिश्नर और मेयर से जांच कर दोषियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लोगों से भी स्वच्छता बनाए रखने की अपील की।

फरीदकोट में हेरोइन सहित दो तस्कर गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदकोट। पुलिस के सीआईए स्टाफ ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो युवकों को 200 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान बठिंडा निवासी रजनीश उर्फ मोटी और लुधियाना निवासी गुरजंट सिंह उर्फ जंटा के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि गांव ढिलवां कलां के पास चेकिंग के दौरान दोनों बाइक सवार युवकों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे भागने लगे। तलाशी लेने पर उनके पास से हेरोइन बरामद हुई। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब उनके आपराधिक रिकॉर्ड और नशे के नेटवर्क की जांच कर रही है।

फिरोजपुर में खेतों से बरामद हुआ पुराना बम

भारतेन्दु संवाददाता, फिरोजपुर

पंजाब के फिरोजपुर जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के नजदीक हुसैनीवाला क्षेत्र में सोमवार सुबह खेतों से एक पुराना बम मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। गांव झुग्गे हजारा सिंह ढाणी के खेतों में काम कर रहे मजदूरों ने मिट्टी में दबे संदिग्ध वस्तु को देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी।

जानकारी के अनुसार, हुसैनीवाला बॉर्डर के पास स्थित खेतों में मजदूर रोजाना की तरह काम कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें जमीन में दबा हुआ एक पुराना बम दिखाई दिया। बम मिलने की सूचना मिलते ही भारतीय सेना और फिरोजपुर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं।

सेना की बम निरोधक टीम ने क्षेत्र को सुरक्षित किया और सावधानीपूर्वक बम को अपने कब्जे में लिया। टीम ने मौके पर आवश्यक सुरक्षा प्रबंध किए और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बम काफी पुराना बताया जा रहा है। हालांकि, यह कहां से आया और कितने समय से जमीन में दबा हुआ था, इसकी जांच की जा रही है। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो उसे छूने के बजाय तुरंत पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दें।

हुसैनीवाला क्षेत्र भारत-पाकिस्तान सीमा के करीब होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है। यहां पहले भी युद्ध या पुराने समय के सैन्य सामान मिलने के मामले सामने आते रहे हैं। फिलहाल सेना और पुलिस की टीमें पूरे मामले की जांच कर रही हैं और बम की स्थिति तथा उसके स्रोत के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

भारी बारिश के चलते रावी दरिया में बाढ़ का खतरा बढ़ा, सीमा क्षेत्र के गांवों में चिंता का माहौल

गुरदासपुर के गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा

भारतेन्दु संवाददाता, गुरदासपुर

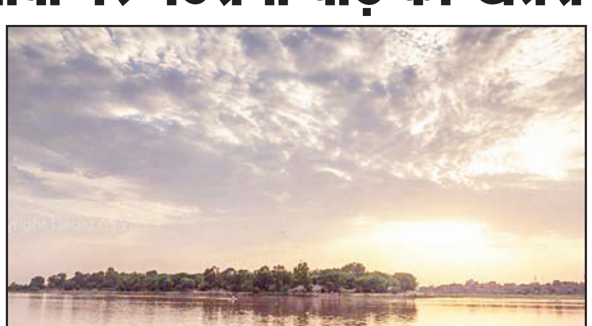

ग्रामीणों ने सुरक्षा प्रबंध बढ़ाने की मांग की

हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश तथा बादल फटने जैसी घटनाओं के कारण रावी दरिया में कभी भी बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। दरिया किनारे बसे गुरदासपुर जिले के कई गांवों के लोग हर साल बरसात के मौसम में डर के माहौल में रहने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ड्रेनेज विभाग की ओर से बाढ़ से निपटने के लिए पर्याप्त प्रबंध नहीं किए गए हैं।

रावी दरिया हिमाचल प्रदेश से रंजीत सागर डैम और शाहपुर कंडी डैम के रास्ते माधोपुर हेडवर्क्स से होते हुए पठानकोट और फिर गुरदासपुर जिले की सीमा में प्रवेश करता है। पठानकोट के जैनीपुर के पास इसमें जम्मू-कश्मीर से आने वाला उज्ज दरिया और शिंगारवां नाला भी मिल जाते हैं। इसके अलावा कई छोटे नाले भी रावी में गिरते हैं, जिससे पानी का बहाव काफी तेज हो जाता है।

गुरदासपुर क्षेत्र में पहुंचने के बाद रावी दरिया का पानी बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। मकोड़ा पत्तन के पास बाढ़ के समय पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि नाव चलाना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि विभाग की ओर से कुछ स्थानों पर सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, लेकिन तेज बहाव के सामने कई बार यह नाकाफी साबित होते हैं।

400 करोड़ के प्रस्तावित डैम का काम अटका

भारत सरकार ने रावी दरिया के पानी को नियंत्रित करने के लिए रंजीत सागर डैम और शाहपुर कंडी डैम बनाए हैं। इसके बावजूद जैनीपुर के पास लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित एक अन्य डैम योजना वर्षों से लंबित है। इस डैम का उद्देश्य रावी के पानी को नियंत्रित करना और दरिया पार बसे गांवों के लिए रास्ता उपलब्ध करवाना था। सभी मंजूरियां मिलने के बावजूद इसका निर्माण शुरू नहीं हो पाया है।

धुस्सी बांध भी नहीं रोक पाता बाढ़

रावी दरिया के किनारे बनाया गया धुस्सी बांध भी कई बार बाढ़ के दबाव को सहन नहीं कर पाता। ग्रामीणों और किसानों द्वारा बनाए गए रास्तों के कारण बांध को नुकसान पहुंचता है, जिससे बाढ़ के दौरान पानी निकलने का खतरा बढ़ जाता है।

एक्टिवा चोरी करते युवक को लोगों ने पकड़ा

भारतेन्दु संवाददाता, कपूरथला। शहर की पुरानी सब्जी मंडी में सोमवार रात एक्टिवा चोरी करने का प्रयास कर रहे एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने पहले आरोपी की पिटाई की और बाद में उसे सिटी थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, मंसूरवाल दोना बाईपास निवासी महेंद्र कुमार रात के समय पुरानी सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आए थे। उन्होंने अपनी एक्टिवा मंडी में खड़ी की और पास की दुकान पर सामान लेने चले गए। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटे तो उनकी एक्टिवा वहां नहीं मिली।

महेंद्र कुमार ने तुरंत आसपास एक्टिवा की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने उन्हें जानकारी दी कि एक युवक उनकी एक्टिवा लेकर लक्कड़ बाजार चौक की ओर जा रहा है। इसके बाद महेंद्र ने स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी का पीछा किया और लक्कड़ बाजार चौक पर उसे पकड़ लिया। आरोपी के पकड़े जाने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

कपूरथला में महिला ने बच्चों संग निगला जहर

भारतेन्दु संवाददाता, कपूरथला

पंजाब के कपूरथला जिले के गांव मल्लू कादराबाद में घरेलू कलह के बाद एक महिला ने अपने तीन बच्चों के साथ जहरीली दवा निगल ली। इस घटना में एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि महिला और उसके दो बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, गांव मल्लू कादराबाद निवासी लवकुश कुमार ने पुलिस को बताया कि वह रात करीब 11 बजे ड्यूटी से काम करके घर लौटे थे। घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी संतोष देवी की तबीयत खराब थी और उन्हें उल्टियां हो रही थीं। महिला के पास कीटनाशक की एक बोतल पड़ी हुई थी। वहीं, तीनों बच्चे अर्द्ध-बेहोशी की हालत में मिले।

लवकुश ने तुरंत बिना देरी किए सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। 108 एम्बुलेंस की मदद से महिला और बच्चों को कपूरथला के सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर करणप्रीत सिंह और उनकी टीम ने सभी का उपचार शुरू किया।

अस्पताल में इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं, महिला संतोष देवी और उसके दो बच्चों की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अमृतसर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, तीनों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना सदर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जेलकांड — फिरोजपुर जेल प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने मामला किया दर्ज

जेल से वीडियो वायरल, हवालाती पर केस दर्ज

भारतेन्दु संवाददाता, फिरोजपुर

केंद्रीय जेल फिरोजपुर में बंद एक हवालाती द्वारा जेल परिसर के अंदर से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपलोड करने का मामला सामने आया है। जेल प्रशासन की शिकायत के आधार पर थाना सिटी फिरोजपुर पुलिस ने संबंधित हवालाती के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, जेल के सहायक सुपरिंटेंडेंट बलविंदर सिंह ने शिकायत में बताया कि कपूरथला जिले के रहने वाले हवालाती गुरिंदर सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह ने जेल के अंदर से एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी। वीडियो सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने हवालाती की तलाशी ली, लेकिन तलाशी के दौरान उसके पास से कोई मोबाइल फोन या अन्य संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। इसके बाद जेल अधिकारियों ने हवालाती से वीडियो के संबंध में पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि कुछ दिन पहले उसने यह वीडियो जेल की जदीद चक्कियों में बंदी के दौरान बनाई थी। इसके बाद जेल प्रशासन ने उसकी निशानदेही पर बैरक नंबर 11 के बाहर बनी भट्टियों की तलाशी ली।

तलाशी के दौरान वहां से एक ओप्पो कंपनी का स्क्रीन मोबाइल फोन बरामद किया गया। मोबाइल में एयरटेल कंपनी की सिम भी लगी हुई थी। जेल प्रशासन ने बरामद मोबाइल को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया।

थाना सिटी फिरोजपुर के सब इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह ने बताया कि जेल अधिकारियों की शिकायत के आधार पर हवालाती गुरिंदर सिंह के खिलाफ पंजाब प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस एक्ट 2026 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि मोबाइल फोन जेल के अंदर कैसे पहुंचा और इसका इस्तेमाल किन गतिविधियों के लिए किया गया। जेल प्रशासन भी मामले की आंतरिक जांच कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जेल परिसर में प्रतिबंधित वस्तुओं की रोकथाम के लिए लगातार तलाशी अभियान चलाए जाते हैं। आने वाले समय में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जाएगा।

ट्रेड डील और लैंड पूलिंग का विरोध तेज

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

भारत-अमेरिका ट्रेड डील और पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग नीति के विरोध में मंगलवार को पंजाब के विभिन्न किसान संगठनों ने राज्यभर में प्रदर्शन किया। किसानों ने कई जिलों में टोल प्लाजा पर धरना देते हुए उन्हें वाहन चालकों के लिए टोल फ्री कर दिया। इस दौरान किसानों ने केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

किसान संगठनों के आह्वान पर पटियाला, मोहाली, लुधियाना, जालंधर समेत कई जिलों में सुबह से ही किसान टोल प्लाजा के पास एकत्र होने लगे। किसानों ने टोल बैरियर हटाकर वाहन चालकों को बिना शुल्क के गुजरने दिया। प्रदर्शन के कारण कई टोल प्लाजा पर किसानों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही।

गैर-राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक और भारतीय किसान यूनियन (एकता सिद्धूपुर) के अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पहले ही ऐलान किया था कि 14 जुलाई को पंजाब के सभी टोल प्लाजा को जनता के लिए फ्री किया जाएगा। इसी घोषणा के तहत राज्यभर में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। किसानों ने लुधियाना जिले के लाडोवाल टोल प्लाजा पर भी प्रदर्शन किया, जो पंजाब के सबसे महंगे टोल प्लाजा में शामिल है। यहां बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। टोल फ्री होने से वाहन चालकों को कुछ समय के लिए शुल्क से राहत मिली।

किसान नेताओं का कहना है कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका ट्रेड डील से कृषि क्षेत्र और छोटे किसानों के हित प्रभावित हो सकते हैं। उनका आरोप है कि विदेशी व्यापार समझौतों से किसानों को नुकसान होने की आशंका है। इसके अलावा किसानों ने पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग नीति का भी विरोध किया।

जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आरोप लगाया कि लैंड पूलिंग नीति के जरिए पंजाब की उपजाऊ कृषि भूमि को बड़े कॉर्पोरेट घरानों को सौंपने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान इस नीति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे और इसके खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे। किसान संगठनों ने कहा कि सरकार को किसानों की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए नीतियों पर दोबारा विचार करना चाहिए।

जीवन की सबसे अनमोल पूंजी हैं अच्छे लोग जो हर कठिन राह को आसान बना देते हैं

जिंदगी एक ऐसी यात्रा है, जिसमें हर मोड़ पर हमें अलग-अलग तरह के लोग मिलते हैं। कोई कुछ समय के लिए साथ चलता है, तो कोई पूरी उम्र के लिए यादों में बस जाता है। इस यात्रा में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, तो वह हैं अच्छे लोग।

अच्छे लोग हमारी जिंदगी को सिर्फ आसान ही नहीं बनाते, बल्कि उसे अर्थ भी देते हैं। वे हमें इंसान बने रहना सिखाते हैं, खासकर उस समय में जब दुनिया स्वार्थ और दिखावे से भरी होती जा रही है।

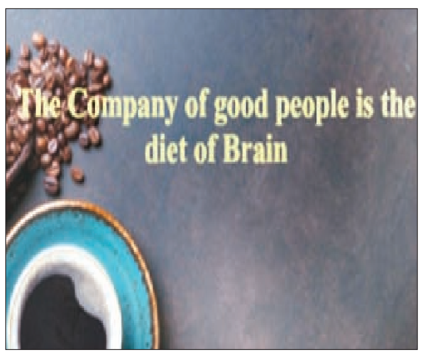

अच्छे लोग वह होते हैं जो बिना किसी मतलब के हमारी परवाह करते हैं। वे हमारे चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को भी समझ लेते हैं। अच्छे लोग न तो हर बात में हामी भरते हैं और न ही हमारी हर गलती को सही ठहराते हैं, बल्कि वे हमें सच्चाई दिखाते हैं और सही रास्ते पर चलने की हिम्मत देते हैं। उनकी अच्छाई शब्दों में नहीं, बल्कि उनके व्यवहार में दिखाई देती है। जिंदगी में अच्छे समय में तो बहुत से लोग साथ होते हैं, लेकिन बुरा समय ही अच्छे लोगों की असली पहचान कराता है। जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं, जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, तब जो लोग बिना सवाल किए हमारे साथ खड़े रहते हैं, वही सच्चे और अच्छे लोग होते हैं। उस समय उनका एक वाक्य, एक सहारा या बस उनकी मौजूदगी ही हमें टूटने से बचा लेती है।

सुभाष चंद काशव
गांव जौवा, डाकघर गैहरा (चंबा)

अच्छे लोग हमारे व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित करते हैं। उनके साथ रहकर हमारी सोच सकारात्मक होती है। हम चीजों को समझदारी से देखना सीखते हैं। वे हमें यह एहसास दिलाते हैं कि सफलता सिर्फ आगे बढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि इंसान बने रहना भी उतना ही जरूरी है। अच्छे लोगों की संगत हमें विनम्र, धैर्यवान और संवेदनशील बनाती है। परिवार हमारे जीवन में अच्छे लोगों की पहली पहचान होता है। माता-पिता का निस्वार्थ प्रेम, भाई-बहनों का अपनापन और बड़ों का मार्गदर्शन हमें मजबूत बनाता है। परिवार ही हमें सिखाता है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, लेकिन जिंदगी के सफर में कई बार ऐसे लोग भी मिलते हैं, जो खून के रिश्ते न होते हुए भी परिवार से बढ़कर हो जाते हैं। ऐसे लोग हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सौगात होते हैं। दोस्तों की भूमिका भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारे सामने हमारी तारीफ से ज्यादा हमारी सच्चाई रखे। अच्छे दोस्त हमारी गलतियों पर हमें सच बोलते हैं, हमें गिरने से बचाते हैं और हमारी सफलता में दिल से खुश होते हैं। जिंदगी में अगर एक भी ऐसा दोस्त मिल जाए, तो इंसान खुद को बहुत भाग्यशाली समझ सकता है।

आज के समय में मानसिक तनाव, अकेलापन और अवसाद आम समस्याएं बनती जा रही हैं। ऐसे दौर में अच्छे लोगों की मौजूदगी किसी दवा से कम नहीं होती। जब हम उनके साथ खुलकर बात करते हैं, तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। अच्छे लोग हमें जज नहीं करते, बल्कि हमारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। वे हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हमारी भावनाएं मायने रखती हैं और हम अकेले नहीं हैं।

अच्छे लोग हमें सही और गलत के बीच अंतर करना भी सिखाते हैं। जब हम किसी दुविधा में फंसे होते हैं, तब वे अपने अनुभव और समझ से हमें सही दिशा दिखाते हैं। वे आदेश नहीं देते, बल्कि प्यार और समझदारी से सलाह देते हैं। एक अच्छा शिक्षक, गुरु या मार्गदर्शक हमारी सोच और पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। उनकी सीख हमें हर मोड़ पर मार्गदर्शन देती है।

अक्सर हम यह मान लेते हैं कि अच्छे लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे, इसलिए उनकी कद्र करना भूल जाते हैं, लेकिन समय और परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अच्छे लोगों को समय दें और उन्हें महत्व दें। साथ ही, केवल अच्छे लोगों की तलाश ही नहीं, बल्कि खुद अच्छा इंसान बनना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि अच्छाई से ही अच्छाई जन्म लेती है। सच यही है कि अच्छे लोग हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं।

आज के तेज़ी से बदलते समय में भौतिक उपलब्धियों को अक्सर सफलता का पैमाना माना जाता है, लेकिन वास्तविक सुख और संतोष का आधार अच्छे लोगों का साथ होता है। धन, पद और प्रतिष्ठा समय के साथ बदल सकते हैं, परंतु अच्छे लोगों द्वारा दिया गया विश्वास, स्नेह और सहयोग जीवनभर हमारे साथ रहता है। ऐसे लोग हमारे कठिन दिनों में आशा की किरण बनते हैं और अच्छे दिनों में हमारी खुशियों को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए और अपने व्यवहार से यह प्रयास करना चाहिए कि हम भी किसी के जीवन में एक अच्छे इंसान के रूप में याद किए जाएं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

सोशल मीडिया की ताकत जिम्मेदारी के साथ ही लोकतंत्र को मजबूत बना सकती है

आज का युग डिजिटल सूचना क्रांति का युग है। सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अभूतपूर्व विस्तार दिया है और आम नागरिक को अपनी बात रखने का सशक्त मंच प्रदान किया है।

यह जनसमस्याओं को उजागर करने, जनांदोलनों को गति देने और सामाजिक बदलाव लाने का प्रभावी माध्यम बना है, किंतु इसी शक्ति का एक गंभीर और चिंताजनक पक्ष भी सामने आया है- डिजिटल भीड़ का उन्माद। भावनाओं से प्रेरित यह भीड़ अक्सर तथ्यों, विवेक और संवैधानिक प्रक्रियाओं को दरकिनार कर देती है और सरकारों व संस्थाओं पर तात्कालिक निर्णय लेने का दबाव बनाती है। हिमाचल प्रदेश के हालिया घटनाक्रम इस खतरे को स्पष्ट करते हैं। आईजीएमसी शिमला में डॉक्टर-मरीज विवाद और धर्मशाला कॉलेज में छात्रा की मृत्यु से जुड़ा रैगिंग व यौन उत्पीड़न का मामला इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन मामलों में वायरल वीडियो और हैशटैग ने जांच पूरी होने से पहले ही सार्वजनिक ट्रायल की स्थिति पैदा कर दी। सोशल मीडिया पर बनी राय के दबाव में प्रशासन को शीघ्र निर्णय लेने पड़े, जबकि तथ्यात्मक जांच अभी जारी थी।

सोशल मीडिया मूलत: संवाद और सूचना साझा करने का माध्यम है, न कि न्यायालय। फिर भी आज अधूरी या संपादित वीडियो क्लिप, एकतरफा बयान और भावनात्मक अपीलों के आधार पर मिनटों में किसी व्यक्ति को अपराधी या पीड़ित घोषित कर दिया जाता है। यह न तो संवैधानिक है और न ही लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, परंतु यह स्वतंत्रता निरंकुश नहीं है। इसके साथ निष्पक्ष सुनवाई, प्राकृतिक न्याय और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन भी उतना ही आवश्यक है। जब सोशल मीडिया इन सीमाओं को लांघता है, तब वह लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय कमजोर करता है। संवैधानिक दृष्टिकोण स्पष्ट है-भीड़ नहीं, विधि सर्वोच्च है। भारतीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि दोष सिद्ध होने तक प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष माना जाएगा।

डिजिटल भीड़ जब जांच से पहले निर्णय सुनाती है, त्वरित दंड की मांग करती है और संस्थाओं को कठघरे में खड़ा करती है, तो वह सीधे संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देती है। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, भावनात्मक भीड़ के प्रति नहीं। सरकार का दायित्व है कि वह कानून, विवेक और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर निर्णय ले, न कि ट्रेंड और वायरल दबाव के आधार पर।

आईजीएमसी शिमला प्रकरण में जांच के बाद दोनों पक्षों की भूमिका सामने आई, फिर भी सोशल मीडिया दबाव में पहले निलंबन और सार्वजनिक निंदा हुई। इसी प्रकार धर्मशाला कॉलेज मामले में जांच जारी रहने के बावजूद डिजिटल मंचों पर फैसला पहले ही सुना दिया गया। इन घटनाओं से संस्थानों की साख को ठेस पहुंची, पेशेवरों का मनोबल गिरा और समाज में भय व अविश्वास का वातावरण बना। सोशल मीडिया पर लिखा गया हर शब्द मात्र कंटेंट नहीं होता। उसके पीछे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, किसी पेशेवर का करियर और किसी परिवार का भविष्य जुड़ा होता है।

डॉ. नितिका शर्मा
भोरंज, जिला हमीरपुर
हि.प्र. केंद्रीय विवि की पूर्व शोधार्थी

भावनाओं में बहकर साझा की गई एक पोस्ट किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए जिम्मेदार सोशल मीडिया उपयोग अनिवार्य है-सत्यापन करें, संयम रखें और संवेदनशील रहें। समाज को यह समझना होगा कि हर वायरल पोस्ट सत्य नहीं होती और न्याय का स्थान स्क्रीन नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्थाएं हैं। सोशल मीडिया न शत्रु है, न देवता। यह केवल एक औजार है।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

> **यह** सच है कि कवि सौंदर्य को देखता है। जो केवल बाहरी सौंदर्य को देखता है वह कवि है, पर जो मनुष्य के मन के सौंदर्य का वर्णन करता है वह महाकवि है।
>
> -रामनरेश त्रिपाठी

संपादकीय

अहिंसा ही सच्चा धर्म

मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता केवल उसकी बुद्धि या शक्ति नहीं बल्कि उसकी करुणा, संवेदनशीलता और विवेक है। मनुष्य को प्रकृति ने सोचने-समझने और सही-गलत का निर्णय करने की क्षमता दी है। इसी कारण वह अन्य जीवों की रक्षा करने और उनके प्रति दया का व्यवहार करने का उत्तरदायित्व भी निभाता है। पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक जीव चाहे वह मनुष्य हो, पशु, पक्षी, जलचर, कीट या वनस्पति हो, सभी प्रकृति की अमूल्य रचना हैं। प्रत्येक जीव का इस संसार में अपना महत्व है और सभी को जीने का समान अधिकार प्राप्त है। इसलिए किसी भी जीव को अनावश्यक हानि पहुँचाना न केवल अमानवीय है बल्कि प्रकृति के संतुलन के लिए भी हानिकारक है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही अहिंसा और दया को सर्वोच्च धर्म माना गया है। वेद, उपनिषद, पुराण तथा अनेक धार्मिक ग्रंथों में सभी जीवों के प्रति करुणा रखने का संदेश मिलता है। भगवान महावीर ने 'अहिंसा परमो धर्म:' का सिद्धांत दिया और बताया कि किसी भी जीव को पीड़ा पहुँचाना सबसे बड़ा पाप है। भगवान बुद्ध ने करुणा, प्रेम और मैत्री का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। महात्मा गांधी ने भी अहिंसा को केवल व्यक्तिगत जीवन का नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण का आधार माना। इन महान व्यक्तित्वों का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था।

प्रकृति का प्रत्येक जीव पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मधुमक्खियाँ परागण का कार्य करती हैं, पक्षी बीजों का प्रसार करते हैं, केंचुए मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं और अनेक छोटे-बड़े जीव खाद्य श्रृंखला को संतुलित रखते हैं। यदि किसी एक प्रजाति का अत्यधिक विनाश होता है तो उसका प्रभाव पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है। यही कारण है कि जैव विविधता का संरक्षण आज पूरी दुनिया की प्राथमिकता बन चुका है। यदि हम अपने स्वार्थ के कारण जीवों का विनाश करेंगे तो अंतत: उसका दुष्परिणाम मानव समाज को भी भुगतना पड़ेगा। आज के समय में पशुओं के साथ क्रूरता, अवैध शिकार, जंगलों की कटाई और प्रदूषण जैसी समस्याएँ लगातार बढ़ रही हैं। अनेक वन्य जीव विलुप्त होने की कगार पर पहुँच चुके हैं। प्लास्टिक कचरे के कारण समुद्री जीवों की मृत्यु हो रही है, रासायनिक प्रदूषण से पक्षियों और मछलियों की संख्या घट रही है तथा शहरीकरण के कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। यह स्थिति केवल जीव-जंतुओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए गंभीर चेतावनी है। यदि प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो जलवायु परिवर्तन, खाद्य संकट और नई बीमारियों जैसी समस्याएँ भी बढ़ सकती हैं।

किसी भी जीव को हानि न पहुँचाने का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे कार्य करें जिनसे किसी जीव को अनावश्यक कष्ट न हो। उदाहरण के लिए प्लास्टिक का कम उपयोग करना, जल स्रोतों को प्रदूषित न करना, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से बचना, पशुओं के साथ क्रूर व्यवहार न करना और पर्यावरण की रक्षा करना भी अहिंसा का ही एक रूप है। यदि हम अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, पक्षियों के लिए पानी रखें, घायल पशुओं की सहायता करें और वृक्षारोपण करें तो यह भी जीवों के प्रति हमारी करुणा का प्रमाण है। मानव और प्रकृति का संबंध सह-अस्तित्व पर आधारित है। मनुष्य चाहे कितना भी विकसित क्यों न हो जाए, वह प्रकृति से अलग होकर जीवित नहीं रह सकता। स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, उपजाऊ भूमि और संतुलित जलवायु सभी जीवों के संयुक्त अस्तित्व पर निर्भर करते हैं। इसलिए किसी भी जीव की रक्षा करना वास्तव में अपने भविष्य की रक्षा करना है। जब हम प्रकृति और जीवों का सम्मान करते हैं, तब हम अपने जीवन को भी सुरक्षित बनाते हैं।

बच्चों में बचपन से ही जीवों के प्रति प्रेम और संवेदनशीलता के संस्कार विकसित किए जाने चाहिए। परिवार और विद्यालय इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि बच्चों को पशु-पक्षियों से प्रेम करना, पेड़ लगाना, पर्यावरण की रक्षा करना और सभी जीवों के प्रति दया रखना सिखाया जाए तो वे बड़े होकर जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्य विकसित करना भी है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी पशु संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं। लोग घायल पशुओं की सहायता कर रहे हैं, पक्षियों के लिए दाना-पानी रखने की पहल कर रहे हैं और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए समाज को प्रेरित कर रहे हैं। ऐसी सकारात्मक पहलें समाज में करुणा और संवेदनशीलता का वातावरण बनाती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम केवल संदेश साझा करने तक सीमित न रहें बल्कि अपने जीवन में भी इन मूल्यों को अपनाएं।

धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में भी सभी जीवों के प्रति सम्मान का संदेश मिलता है। अनेक पर्वों और अवसरों पर पशु-पक्षियों को भोजन कराना, वृक्षों की पूजा करना और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। इन परंपराओं का मूल उद्देश्य मनुष्य को यह समझाना है कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा है। जब यह भावना हमारे भीतर विकसित होती है तब हम किसी भी जीव को हानि पहुँचाने से पहले कई बार सोचते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि करुणा केवल बड़े कार्यों में ही नहीं बल्कि छोटे-छोटे व्यवहारों में भी दिखाई देती है।

-शिवांश धाकड़

श्री गणेश के बारह दिव्य नामों में छिपा है सुख, समृद्धि, ज्ञान और सफलता का रहस्य

भगवान श्री गणेश को हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता माना गया है। किसी भी शुभ कार्य का आरंभ उनके स्मरण और पूजन से किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश विघ्नों का नाश करने वाले, बुद्धि और विवेक प्रदान करने वाले तथा सुख समृद्धि के दाता हैं। पुराणों में वर्णित है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री गणेश के विभिन्न नामों का स्मरण करता है उसके जीवन की अनेक कठिनाइयां दूर होने लगती हैं। विशेष रूप से भगवान गणेश के बारह पवित्र नामों का जाप अत्यंत फलदायी माना गया है। इन नामों में केवल भगवान के स्वरूप का वर्णन ही नहीं है बल्कि प्रत्येक नाम में एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति और संदेश भी छिपा हुआ है।

डॉ. तारा देवी सेन
वल्लभ कॉलेज, मंडी,
विभागाध्यक्ष वनस्पति शास्त्र

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश के बारह नामों का उल्लेख नारद पुराण तथा अन्य ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रात:काल स्नान के बाद इन बारह नामों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है उसके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और उसे कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। विद्यार्थियों के लिए यह जाप विशेष रूप से लाभकारी माना गया है क्योंकि भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान और स्मरण शक्ति का अधिष्ठाता देव माना गया है। भगवान गणेश के बारह पवित्र नाम इस प्रकार हैं। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। प्रत्येक नाम अपने भीतर एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ समेटे हुए है।

सुमुख का अर्थ है सुंदर और मंगलमय मुख वाला। यह नाम हमें सिखाता है कि मनुष्य को सदैव प्रसन्नचित्त और मधुर स्वभाव का होना चाहिए। सुंदर चेहरा नहीं बल्कि सुंदर विचार और मधुर व्यवहार ही व्यक्ति की वास्तविक पहचान होते हैं। इस नाम का स्मरण मन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास का संचार करता है।

एकदंत का अर्थ है एक दांत वाले भगवान। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश ने धर्म और ज्ञान की रक्षा के लिए अपना एक दांत त्याग दिया था। यह नाम त्याग, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक है।

कपिल का अर्थ है ताम्रवर्ण या दिव्य तेज से युक्त।

यह नाम भगवान के ज्ञान और आध्यात्मिक प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। कपिल नाम का स्मरण अज्ञान के अंधकार को दूर कर विवेक और ज्ञान का प्रकाश फैलाने की प्रेरणा देता है।

गजकर्णक का अर्थ है हाथी के समान बड़े कान वाले। बड़े कान इस बात का संकेत हैं कि मनुष्य को अधिक सुनना और कम बोलना चाहिए। भगवान गणेश सबकी प्रार्थनाएं सुनते हैं और उचित समय पर उनका समाधान करते हैं। यह नाम धैर्य और सजगता का संदेश देता है।

लंबोदर का अर्थ है विशाल उदर वाले भगवान। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान गणेश अपने विशाल उदर में संपूर्ण सृष्टि को धारण किए हुए हैं। यह नाम सहनशीलता, धैर्य और उदारता का प्रतीक है।

विकट का अर्थ है अत्यंत शक्तिशाली और कठिन परिस्थितियों पर विजय पाने वाला। यह नाम हमें जीवन की चुनौतियों से घबराने के बजाय साहस और धैर्य के साथ उनका सामना करने की प्रेरणा देता है। भगवान गणेश की कृपा से कठिन से कठिन मार्ग भी सरल हो सकता है।

विघ्ननाशक भगवान गणेश का सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक है। इसका अर्थ है सभी प्रकार के विघ्नों और बाधाओं का नाश करने वाला। यही कारण है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। यह नाम हमें विश्वास और सकारात्मक सोच बनाए रखने की प्रेरणा देता है।

विनायक का अर्थ है श्रेष्ठ नेता और मार्गदर्शक। भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि जीवन के सच्चे पथप्रदर्शक भी हैं। उनका यह नाम नेतृत्व क्षमता, निर्णय शक्ति और विवेकपूर्ण आचरण का प्रतीक है। जो व्यक्ति विनायक का स्मरण करता है उसमें सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है।

धूम्रकेतु नाम भगवान गणेश के तेजस्वी और प्रभावशाली स्वरूप का प्रतीक है। इसका अर्थ है ऐसा दिव्य प्रकाश जो अंधकार और नकारात्मकता को समाप्त कर देता है।

गणाध्यक्ष का अर्थ है समस्त गणों के स्वामी और अध्यक्ष। भगवान गणेश देवताओं के गणों का नेतृत्व करते हैं। यह नाम संगठन, अनुशासन और जिम्मेदारी का संदेश देता है। जीवन में सफलता के लिए नेतृत्व के साथ विनम्रता भी आवश्यक है।

भालचंद्र का अर्थ है मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले। चंद्रमा शांति, संतुलन और सौम्यता का प्रतीक है। यह नाम हमें क्रोध, अहंकार और अस्थिरता से दूर रहकर शांत और संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देता है।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

हॉलीवुड की दमदार अभिनेत्री हैं डायने क्रूगर

डायने क्रूगर

डायने क्रूगर का जन्म 15 जुलाई 1976 को जर्मनी के अल्गरमिसेन में हुआ था। उनका पूरा नाम डायने हीडक्रूगर है। बचपन से ही उन्हें कला और नृत्य में गहरी रुचि थी। उन्होंने बैले नृत्य का प्रशिक्षण लिया और पेशेवर बैले नृत्यांगना बनने का सपना देखा। हालांकि एक दुर्घटना के कारण उन्हें यह सपना छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और बहुत कम समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली। उनकी प्रतिभा और आकर्षक व्यक्तित्व ने उन्हें यूरोप के साथ-साथ अमेरिका के फैशन जगत में भी लोकप्रिय बना दिया।

मॉडलिंग में सफलता मिलने के बाद डायने ने अभिनय की ओर रुख किया। उन्होंने अभिनय का विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किया और कई फ्रांसीसी तथा जर्मन फिल्मों में काम किया। उनकी अभिनय क्षमता को सबसे बड़ी पहचान वर्ष 2004 में रिलीज हुई ऐतिहासिक फिल्म ट्रॉय से मिली। इस फिल्म में उन्होंने स्पार्टा की रानी हेलेन का किरदार निभाया। उनकी प्रभावशाली अदाकारी और सशक्त स्क्रीन उपस्थिति ने दर्शकों और समीक्षकों का ध्यान आकर्षित किया। इस फिल्म के बाद उन्हें हॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्रियों में गिना जाने लगा।

कविता

निकला था कुछ सपने खरीदने

डॉ. अशोक प्यारे लाल चौबे

मैं तकलीफ बेचकर
सुकून खरीदना चाहता हूं।
न कोई घर न महल खरीदना चाहता हूं
अपने देश में अमन खरीदना चाहता हूं।
कोई मेरी तकलीफों का मोल दे दे
मैं प्यार मोहब्बत का उपहार बांटना चाहता हूं।
खुशियां चाहते हो देखना रात झोपड़ी में गुजारो।
महलों की दीवार में दु:ख के ईंट नजर आते हैं।

भारत की आर्थिक ताकत को नई उड़ान देगा सीईटीए

भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता यानी सीईटीए 15 जुलाई से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते को भारत के सबसे महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक माना जा रहा है। इसके लागू होने के साथ ही ब्रिटेन को होने वाले भारत के लगभग सभी निर्यात उत्पादों पर सीमा शुल्क समाप्त हो जाएगा। इससे भारतीय व्यापारियों, किसानों, छोटे और मध्यम उद्योगों, मछुआरों, महिला उद्यमियों और युवाओं के लिए वैश्विक बाजार में नए अवसर खुलेंगे।

इस समझौते का उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार को बढ़ावा देना और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना है। सीईटीए के तहत लगभग 99 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त किया जाएगा, जिसमें व्यापार के लगभग पूरे मूल्य को शामिल किया गया है। इससे भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा और भारतीय कंपनियां अधिक आसानी से अपने उत्पाद वहां पहुंचा सकेंगी।

पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री

भारत सरकार का मानना है कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वैश्विक बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलने से भारतीय उद्योगों को विस्तार का मौका मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ ही देश के छोटे व्यापारियों और स्थानीय उत्पादकों को भी अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

व्यापार जगत में इस समझौते को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्यातकों को उम्मीद है कि ब्रिटेन को होने वाला उनका निर्यात आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ेगा। अनुमान है कि अगले तीन वर्षों में रत्न और आभूषण निर्यात में बड़ी वृद्धि हो सकती है। इसी तरह इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यातकों को भी ब्रिटेन के बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है।

भारत के श्रम आधारित उद्योगों जैसे कपड़ा, चमड़ा, जूते, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, वाहन कलपुर्जे और जैविक रसायन क्षेत्र को इस समझौते से विशेष लाभ मिलने की संभावना है। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। ब्रिटेन के बाजार में बेहतर पहुंच मिलने से इन उद्योगों का उत्पादन बढ़ सकता है जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

सीईटीए का एक महत्वपूर्ण पहलू युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसरों से जुड़ा है। यह समझौता विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लागू हुआ है। भारत सरकार का कहना है कि कौशल भारत मिशन के माध्यम से तैयार हो रहे युवा अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए अधिक सक्षम होंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय युवाओं के लिए आईटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वित्तीय सेवाओं, इंजीनियरिंग और पेशेवर सेवाओं जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होंगे।

ब्रिटेन ने सेवा क्षेत्र में भारत के लिए अपनी महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं व्यक्त की हैं। इससे भारतीय सेवा प्रदाताओं को कई प्रमुख क्षेत्रों में बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी। सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवा, परामर्श और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों और पेशेवरों के लिए संभावनाएं बढ़ेंगी।

सीईटीए में दोहरी सामाजिक सुरक्षा योगदान व्यवस्था भी शामिल है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोहरी सामाजिक सुरक्षा राशि जमा करने से छूट मिलेगी। इससे हजारों भारतीय पेशेवरों और कई कंपनियों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। यह व्यवस्था दोनों देशों के बीच पेशेवर संबंधों को और मजबूत करेगी।

कृषि क्षेत्र के लिए भी यह समझौता काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्रिटेन का बड़ा बाजार भारतीय किसानों और कृषि उत्पादकों के लिए नए अवसर लेकर आएगा। चाय, कॉफी, मसाले, फल, सब्जियां, फलों के रस, मांस और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलने की संभावना है। ब्रिटेन के कृषि आयात बाजार में भारतीय उत्पादों की पहुंच बढ़ने से किसानों की आय में सुधार हो सकता है और कृषि आधारित उद्योगों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। हालांकि सरकार ने घरेलू कृषि हितों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। डेयरी उत्पादों, सब्जियों, सेब, खाद्य तेल, मोटे अनाज और कुछ अन्य संवेदनशील कृषि उत्पादों को समझौते में विशेष सुरक्षा दी गई है। इन उत्पादों पर ब्रिटेन को शुल्क में छूट नहीं दी गई है। इसका उद्देश्य भारतीय किसानों और घरेलू बाजार को संभावित नुकसान से बचाना है।

छोटे और मध्यम उद्योगों यानी एसएमई के लिए भी सीईटीए में विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारत के कुल निर्यात में एसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। समझौते के तहत सीमा शुल्क प्रक्रिया को आसान बनाने, डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने और दस्तावेजी प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। इससे छोटे कारोबारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना आसान होगा।

एसएमई को व्यापार संबंधी जानकारी, वित्तीय सहायता, डिजिटल कौशल और व्यवसायिक सुविधाओं के क्षेत्र में भी सहयोग मिलेगा। इससे स्थानीय स्तर पर काम करने वाले छोटे उद्योग वैश्विक बाजार से जुड़ सकेंगे और अपनी क्षमता का विस्तार कर सकेंगे।

मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के लिए भी यह समझौता लाभकारी साबित हो सकता है। भारत में करोड़ों लोगों की आजीविका इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। बेहतर बाजार पहुंच मिलने से समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के मछुआरों और मत्स्य उद्योग से जुड़े लोगों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

'भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर धरने पर बैठे 69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी

एजेंसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ में बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। निशातगंज स्थित निदेशालय परिसर के बाहर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर जुटे और सरकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की।

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो समय मांगा था, वह पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक शिक्षक भर्ती की सूची का पुनरीक्षण नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि सरकार न्यायालय में दिए गए आश्वासन के अनुरूप काम नहीं कर रही है, जिसके कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों के अनुसार, 19 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता ने 13 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर भर्ती सूची का पुनरीक्षण करने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा था। अब यह अवधि पूरी होने के बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है।

अभ्यर्थियों ने कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होनी है और वे चाहते हैं कि उससे पहले सरकार स्पष्ट कदम उठाए। अभ्यर्थी अमित मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी के कारण आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए। उन्होंने कहा कि पिछले करीब छह वर्षों से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

वहीं, धनंजय गुप्ता ने आरोप लगाया कि सरकार दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान करने में देरी कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि भर्ती सूची का जल्द पुनरीक्षण कर आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन किया जाए, ताकि पात्र अभ्यर्थियों को उनका अधिकार मिल सके।

देवरिया में आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर चार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

फीडबैक समीक्षा में शिकायतकर्ताओं की असंतुष्टि मिलने पर कार्रवाई, संतोषजनक जवाब न मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई

एजेंसी, देवरिया

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने आईजीआरएस (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) के मामलों में त्रुटिपूर्ण कार्रवाई और शिकायतों के गलत निस्तारण को लेकर चार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

अधिकारियों से तय समय के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी इन दिनों जिले में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत भी मिले। इसके लिए जिलाधिकारी स्वयं कई मामलों में शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेकर निस्तारण की गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं।

समीक्षा के दौरान कई मामलों में अधिकारियों की ओर से की गई कार्रवाई में खामियां सामने आईं। जांच में पाया गया कि कुछ शिकायतों का निस्तारण सही तरीके से नहीं किया गया और रिपोर्ट में भी त्रुटियां पाई गईं। इसके बाद जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

जारी नोटिस के अनुसार सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) भटनी को दो अलग-अलग मामलों में लापरवाही बरतने पर नोटिस दिया गया है। इन मामलों में ग्राम पंचायतों में साफ-सफाई व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों का उचित समाधान नहीं किए जाने का आरोप है। जिलाधिकारी ने इस मामले में अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) बरहज को भूमिगत नाली निर्माण से जुड़ी शिकायत के गलत निस्तारण को लेकर नोटिस जारी किया गया है। शिकायतकर्ता की समस्या के समाधान में लापरवाही बरतने और रिपोर्ट में उचित कार्रवाई नहीं दर्शाने को लेकर जवाब मांगा गया है। इसके अलावा खंड विकास अधिकारी भटनी को प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित शिकायत के त्रुटिपूर्ण निस्तारण के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

प्रशासन का कहना है कि सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे पात्र लाभार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) भागलपुर को भी नाली निर्माण से संबंधित शिकायत के अनुचित निस्तारण के मामले में नोटिस दिया गया है। प्रशासन ने सभी अधिकारियों से मामले की पूरी जानकारी और अपने पक्ष में स्पष्ट जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।

न्यूज ब्रीफ

सुप्रीम कोर्ट की सुलह पहल बेनतीजा दोनों पक्षों का मध्यस्थता से इनकार

एजेंसी, वाराणसी। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर मंगलवार को हुई मध्यस्थता प्रक्रिया बेनतीजा रही। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर स्थित मध्यस्थता केंद्र में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन दोनों पक्षों ने समझौते या सुलह की प्रक्रिया से इनकार कर दिया। दोनों अपने-अपने दावों पर कायम रहे। अब मध्यस्थता की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी। अदालत आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर फैसला लेगी। मुस्लिम पक्ष की अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी पहले ही बैठक में शामिल होने से मना कर चुकी थी। वहीं हिंदू पक्ष ने भी अंतिम समाधान न्यायालय के निर्णय से होने की बात कही है।

जालौन में दो बाइक आपस में भिड़ीं इंटरमीडिएट के छात्र की मौत

एजेंसी, उरई। जालौन में मंगलवार को दो बाइकों की भिड़ंत में इंटरमीडिएट के 18 वर्षीय छात्र सत्यम सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। सत्यम गांव से उरई स्थित अपने कमरे पर लौट रहा था, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद टक्कर मारने वाला बाइक सवार फरार हो गया। बेटे की मौत से परिवार में मातम छा गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

सोनभद्र में सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आकर दो युवकों की मौत

एजेंसी, सोनभद्र। सोनभद्र के करमा थाना क्षेत्र में मंगलवार को दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। रॉबर्ट्सगंज-मिर्जापुर मार्ग पर खैराही के पास बाइक सवार सुरेंद्र कुमार पाल (22) और मुन्ना (27) सड़क पर खड़े वाहन से टकरा गए। हादसे में सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल मुन्ना ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों युवक देर रात हिन्दुआरी से अपने घर लौट रहे थे। सूचना मिलते ही करमा पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत,बेटे और पति बाल-बाल बचे

एजेंसी, औरैया। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। श्याम नगर निवासी मोहिनी पोरवाल (27) अपने पति और पांच वर्षीय जुड़वां बेटों के साथ स्कूटी से बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थीं। सिंह वाहिनी महाविद्यालय के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने स्कूटी को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में मोहिनी गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि पति और बच्चे सुरक्षित बच गए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी है।

बारिश की पहली मार में टूटा वाराणसी-भदोही राष्ट्रीय राजमार्ग, जगह-जगह गड्ढे

एजेंसी, वाराणसी। वाराणसी-भदोही के बीच बने राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत मानसून की पहली बारिश में खराब हो गई है। लोहता से जंसा और कपसेठी मार्ग पर कई जगह छोटे-बड़े गड्ढे बन गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दो साल से भी कम समय में सड़क खराब होना चिंता का विषय है। इस मार्ग से रोजाना हजारों लोग आवागमन करते हैं। बारिश के बाद गड्ढों में पानी भरने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है और हादसों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है।

गंग नहर में नहाते समय आठ वर्षीय बच्ची डूबी, शव की तलाश में जुटी एनडीआरफ

एजेंसी, नोएडा। नोएडा के थाना दनकौर क्षेत्र के खेरली गांव के पास मंगलवार को गंग नहर में नहाते समय आठ वर्षीय बच्ची डूब गई। बच्ची की पहचान ममता पुत्र संतोष के रूप में हुई है। वह चार सहेलियों के साथ नहर में नहाने गई थी। तेज बहाव की चपेट में आने से वह पानी में बह गई। बच्चों के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एनडीआरएफ टीम को बुलाया। गोताखोरों की मदद से बच्ची की तलाश जारी है। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

आगरा में डीएसएस पिटाई मामला, पत्नी ने आरपीएफ जवानों की बर्खास्तगी की उठाई मांग

एजेंसी, आगरा। आगरा में उप स्टेशन प्रबंधक नरेंद्र सिंह चाहर की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विरोध में पूरा परिवार और बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर उतर आईं। डीआरएम कार्यालय में पहुंची नरेंद्र की पत्नी हरेंद्र ने पति के सम्मान की रक्षा के लिए न्याय की मांग की और कार्रवाई नहीं होने पर बड़ा कदम उठाने की बात कही। वहीं, नरेंद्र की बहन सहित कई महिलाएं कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचीं और ट्रैक पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। कुछ महिलाएं पटरी पर लेट गईं। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को बर्खास्त करने की मांग की। मौके पर रेलवे अधिकारी और सुरक्षा बल स्थिति संभालने में जुटे रहे।

प्रेमानंद महाराज के शिष्य के पिता से 2.90 करोड़ की चोरी, 4 आरोपी गिरफ्तार

एजेंसी, मथुरा। मथुरा के वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के शिष्य के यहां हुई 2.90 करोड़ रुपये की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जैंत थाना पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2.60 करोड़ रुपये नकद, कार, आभूषण और महंगे सामान बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी की रकम से ऐश-ओ-आराम की चीजें खरीद रहे थे और पासपोर्ट बनवाकर दुबई भागने की तैयारी में थे। आरोपियों ने एक व्यक्ति को प्लॉट दिखाने के बहाने बाहर भेजकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने चारों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

सीजीएचएस के बाद अब रेलवे फार्मासिस्ट भर्ती में बड़ा बदलाव: सुनील यादव

एजेंसी, लखनऊ

भारत सरकार की ओर से फार्मेसी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने फार्मासिस्ट के पदों पर सीधी भर्ती के लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी (बीफार्मा) अथवा डॉक्टर ऑफ फार्मेसी (फार्म डी) को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की है। इससे पहले केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) में भी फार्मासिस्ट पदों के लिए इसी योग्यता को लागू किया जा चुका है।

सरकार के इस फैसले को फार्मेसी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। फार्मासिस्ट फेडरेशन सेंट्रल कमेटी के अध्यक्ष चीफ फार्मेसिस्ट सुनील यादव ने कहा कि नई योग्यता व्यवस्था से स्वास्थ्य सेवाओं में प्रशिक्षित और अधिक सक्षम फार्मेसी विशेषज्ञों की भूमिका बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था में फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है।

दवाओं की सही जानकारी, मरीजों को परामर्श और सुरक्षित दवा उपयोग में फार्मासिस्ट की अहम भूमिका होती है। ऐसे में उच्च शिक्षा प्राप्त फार्मासिस्टों की जरूरत लगातार बढ़ रही है। हालांकि, सुनील यादव ने डिप्लोमा फार्मासिस्टों के भविष्य को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश में बड़ी संख्या में डिप्लोमा फार्मासिस्ट निजी और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं। उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए डिप्लोमा फार्मासिस्टों को उच्च शिक्षा से जोड़ने और उन्हें अपग्रेड करने की व्यवस्था जरूरी है।

उन्होंने सुझाव दिया कि डिप्लोमा फार्मासिस्टों के लिए बीफार्मा प्रैक्टिस ब्रिज कोर्स शुरू किया जाना चाहिए। इससे वे अपनी योग्यता को बढ़ाकर सरकारी क्षेत्र में आने वाली नई आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। सुनील यादव ने देश के सभी विश्वविद्यालयों, फार्मेसी कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों से अपील की कि वे जल्द से जल्द बीफार्मा प्रैक्टिस ब्रिज कोर्स शुरू करें। उन्होंने कहा कि इससे कार्यरत डिप्लोमा फार्मासिस्टों को उच्च शिक्षा हासिल करने का मौका मिलेगा और देश को अधिक प्रशिक्षित एवं आधुनिक फार्मेसी कार्यबल उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार और अनुभव को जोड़कर फार्मेसी क्षेत्र को मजबूत किया जा सकता है, जिससे मरीजों को सुरक्षित व बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

बाराबंकी में विवादित होर्डिंग से सियासी पारा चढ़ा, सपाइयों ने फाड़े पोस्टर

एजेंसी, बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी शहर में मंगलवार को एक विवादित होर्डिंग लगाए जाने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया। होर्डिंग में समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव तथा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर टिप्पणी की गई थी। होर्डिंग की जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई।

सूचना मिलने के बाद समाजवादी पार्टी नेता ताज बाबा राईन बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और विवादित होर्डिंग व पोस्टर को हटाकर फाड़ दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि जानबूझकर पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई है।

घटना की सूचना मिलने के बाद नगर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर स्थिति को संभाला और मौके से विवादित होर्डिंग को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नगर कोतवाली प्रभारी सुधीर सिंह ने बताया कि होर्डिंग को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि होर्डिंग किसने लगाई थी और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभी तक मामले में किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। शिकायत मिलने के बाद तथ्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। घटना के बाद इलाके में पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच जारी है और होर्डिंग लगाने वाले लोगों की पहचान के लिए सभी संभावित साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वाराणसी लॉन एसोसिएशन ने प्राधिकरण उपाध्यक्ष के सामने रखी अपनी मांगें, शासन भेजी जाएगी फाइल

एजेंसी, वाराणसी

वाराणसी विकास प्राधिकरण में मंगलवार को वाराणसी लॉन एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्राधिकरण उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं। लॉन संचालकों ने प्राधिकरण की ओर से बनाए गए नए नियमों को लेकर चिंता जताई और कहा कि मौजूदा लॉन मालिकों के लिए इन नियमों का पूरी तरह पालन करना काफी मुश्किल है।

एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि वाराणसी में कई लॉन वर्षों से संचालित हो रहे हैं और इनसे बड़ी संख्या में लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है। ऐसे में पहले से चल रहे लॉन को नए नियमों के दायरे से बाहर रखते हुए उन्हें कुछ राहत दी जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि पुराने लॉन संचालकों के लिए नियमों में व्यावहारिक बदलाव किए जाएं, ताकि वे अपनी गतिविधियां सुचारु रूप से चला सकें। लॉन मालिकों का कहना है कि नए प्रावधानों के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्राधिकरण से मांग की कि नियम बनाते समय पुराने लॉन, उनकी स्थिति और वर्षों से चल रहे व्यवसाय को ध्यान में रखा जाए। इस मामले में वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने कहा कि लॉन संचालकों की मांगों को सुना गया है। हालांकि, अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता।

◆ **लॉन मालिकों ने कहा- नए नियमों में व्यावहारिक बदलाव से मिलेगी राहत**

उन्होंने बताया कि लॉन एसोसिएशन की ओर से दिए गए मांग पत्र और प्राधिकरण की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट को शासन स्तर पर भेजा जाएगा। इसके बाद ही इस संबंध में कोई निर्णय संभव होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि लॉन से जुड़े सभी नियमों और प्रावधानों का पालन करना प्रत्येक संचालक के लिए आवश्यक है। नियमों के पालन को लेकर किसी तरह की छूट देने का फैसला शासन स्तर पर ही लिया जा सकता है।

पत्नी से विवाद के बाद युवक ने थाने के बाहर खुद को लगाई आग, बचाने पहुंचे पुलिसकर्मी झुलसे

एजेंसी, कानपुर

उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में मंगलवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां महाराजपुर थाना के मुख्य द्वार पर एक युवक ने खुद को आग लगा ली। युवक को बचाने के प्रयास में थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मी भी झुलस गए। घटना के बाद सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह के अनुसार, महाराजपुर थाना क्षेत्र के राजथोक फुफुवार निवासी महेश मंगलवार को थाने पहुंचा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वह लगातार न्याय की मांग करते हुए शोर कर रहा था। पुलिसकर्मी उससे बातचीत कर ही रहे थे कि उसने अचानक जेब से एक बोतल निकाली और अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया। इसके बाद माचिस जलाकर खुद को आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही महेश लपटों से घिर गया और इधर-उधर भागने लगा। मौके पर मौजूद थाना प्रभारी जनार्दन सिंह, उपनिरीक्षक गौरव सौलिया और आरक्षी अरुण कुमार ने तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ लगाई।

पुलिसकर्मियों ने कंबल डालकर आग बुझाई और युवक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस दौरान तीनों पुलिसकर्मी भी आग की चपेट में आकर झुलस गए। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल महेश को तत्काल उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं झुलसे पुलिसकर्मियों को भी प्राथमिक उपचार दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी घायलों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महेश का अपनी पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा था।

उसकी पत्नी पूनम ने एक दिन पहले महाराजपुर थाने में उसके खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया था। इसी मामले को लेकर महेश थाने पहुंचा था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आत्मदाह के प्रयास के पीछे की वजह और पूरे पारिवारिक विवाद की जांच की जा रही है। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई करेगी।

कब्जामुक्ति तहसीलदार न्यायालय के आदेश के बाद कब्रिस्तान की जमीन को कब्जामुक्त कराया गया

प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनी अवैध ईदगाह को किया जमींदोज

एजेंसी, संभल

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को असमोली थाना क्षेत्र के मढ़न गांव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित रूप से अवैध रूप से बने ढांचे को ध्वस्त कर दिया। राजस्व विभाग की टीम की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई।

इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तीन थानों की पुलिस फोर्स के साथ सुरक्षा बल तैनात किया गया था। प्रशासन के अनुसार, मढ़न गांव में कब्रिस्तान के लिए सुरक्षित भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी। मामले की सुनवाई तहसीलदार न्यायालय में चल रही थी, जिसके बाद न्यायालय ने बेदखली के आदेश जारी किए थे। आदेश के अनुपालन में तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने नायब तहसीलदार दीपक जुरैल के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी। मंगलवार को राजस्व अधिकारियों और पुलिस बल के साथ टीम गांव पहुंची और कार्रवाई शुरू की।

अधिकारियों के मुताबिक, मढ़न गांव में गाटा संख्या 208, 210, 218 और 417 की जमीन कब्रिस्तान के लिए सुरक्षित दर्ज थी। प्रशासन का कहना है कि इनमें से कुछ भूमि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य से अलग किया जा रहा था। तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गाटा संख्या 210 अभी भी कब्रिस्तान के रूप में उपयोग हो रही है, जबकि गाटा संख्या 208 पर कथित रूप से अवैध निर्माण कर उसे दूसरे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।

प्रशासन ने बताया कि सरकारी रिकॉर्ड और न्यायालय के आदेश के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने, इसके लिए पुलिस बल को पहले से तैनात किया गया था। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराया। तहसीलदार ने कहा कि सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

उन्होंने बताया कि प्रशासन का उद्देश्य सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की भूमि को सुरक्षित रखना है। अवैध कब्जों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं, इस कार्रवाई के बाद गांव में प्रशासन की गतिविधियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिकॉर्ड की जांच और न्यायालय के आदेशों के आधार पर आगे भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

संपत्ति विवाद में घर में घुसकर तोड़फोड़ का आरोप, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल

एजेंसी, उरई

जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम जगम्मनपुर में संपत्ति विवाद को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। गांव निवासी राजकुमार और शिवशंकर ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक जालौन विनय कुमार सिंह को शिकायती पत्र देकर पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि संपत्ति विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद पुलिस ने एक पक्ष के समर्थन में कार्रवाई की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे और जबरन प्रवेश कर तोड़फोड़ की। इसके बाद परिवार के सदस्यों को थाने ले जाकर दबाव बनाते हुए कथित रूप से हस्तलिखित समझौते पर हस्ताक्षर कराए गए। पीड़ितों के अनुसार, विवादित संपत्ति का मामला माधौगढ़ न्यायालय में वाद संख्या 23/2025 के रूप में लंबित है। इसके बावजूद 11 जुलाई को पुलिस ने कार्रवाई की। उन्होंने दावा किया कि पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने अपनी आपबीती बताई है। हालांकि, वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। शिकायत में पीड़ितों ने घटना से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग की है।

◆ **पुलिस पर दबाव में समझौता कराने का आरोप**

उन्होंने 11 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज, जनरल डायरी, ड्यूटी रजिस्टर, वाहन लॉगबुक और कॉल डिटेल की जांच कराने की मांग की है। साथ ही निष्पक्ष जांच पूरी होने तक संबंधित पुलिसकर्मियों को मामले से अलग रखने की भी अपील की गई है। मामले से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा तेज हो गई है। पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रकरण की जांच के आदेश क्षेत्राधिकारी को दिए हैं। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी।

हुड्डा सेक्टर में चल रहे स्पा सेंटर पर पुलिस की रेड, तीन युवतियों का रेस्क्यू

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद

शहर के हुडा सेक्टर में मंगलवार को पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापेमारी कर तीन युवतियों को हिरासत में लिया। यह स्पा सेंटर इलाके में स्थित एक शराब ठेके के ऊपर संचालित किया जा रहा था। पुलिस को लंबे समय से यहां संदिग्ध गतिविधियां संचालित होने की सूचनाएं मिल रही थीं।

सूचना के आधार पर महिला पुलिस और स्थानीय थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने योजना बनाकर स्पा सेंटर की घेराबंदी की और अचानक दबिश दी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। टीम ने सेंटर में मौजूद तीन युवतियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और उन्हें थाने ले गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, स्पा सेंटर के दस्तावेज, लाइसेंस और वहां आने-जाने वाले लोगों के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इसके अलावा सेंटर संचालक की भूमिका

की भी पड़ताल की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यहां किसी तरह की अवैध गतिविधि तो नहीं चल रही थी।

पुलिस की कार्रवाई के बाद आसपास के अन्य स्पा सेंटर संचालकों में भी हड़कंप मच गया। कई संचालक सतर्क हो गए और अपने प्रतिष्ठान बंद करते नजर आए। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।

पांच हजार जवानों के सुरक्षा घेरे में 17 जुलाई को होगा प्रधानमंत्री का हरियाणा दौरा

हाइड्रोजन ट्रेन के उदघाटन से पहले जींद में सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की तैयारियां अंतिम चरण में

भारतेन्दु संवाददाता, जींद

हरियाणा के जींद में 17 जुलाई को आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा प्रदेश के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

प्रशासन के अनुसार प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचेंगे। इसके बाद वह सड़क मार्ग से रेलवे जंक्शन जाएंगे, जहां देश की महत्वाकांक्षी हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए जींद जिले में सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंध किए गए

हैं। जिले में बड़े स्तर के आयोजन के कारण प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग पांच हजार पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था की कमान वरिष्ठ अधिकारियों के हाथों में रहेगी। पुलिस विभाग के अनुसार इस विशेष ड्यूटी में 15 भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी, 50 पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी), 200 निरीक्षक तथा 500 उपनिरीक्षक तैनात रहेंगे। इनके अलावा बड़ी संख्या में अन्य पुलिस कर्मियों और सुरक्षा एजेंसियों के जवान भी ड्यूटी पर रहेंगे।

महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दूसरे जिलों से करीब 600 महिला पुलिसकर्मियों को भी बुलाया जा रहा है। भीड़ प्रबंधन, प्रवेश द्वारों की निगरानी और महिला श्रद्धालुओं एवं आगंतुकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी महिला पुलिसकर्मियों को भी सौंपी जाएगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न जिलों से लगभग 100 पुलिस वाहन भी जींद पहुंचेंगे, जिनका उपयोग गश्त, वीआईपी मूवमेंट और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए किया जाएगा।

सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए कार्यक्रम स्थल और प्रधानमंत्री के प्रस्तावित मार्ग पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार हर 10 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी तैनात रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक की संभावना न रहे। जींद शहर में 80 स्थानों पर पुलिस नाके स्थापित किए जाएंगे, जहां आने-जाने वाले वाहनों और लोगों की सघन जांच की जाएगी। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जाएगी।

सड़क हादसे में दो पुलिसकर्मियों की मौत, एक गंभीर घायल

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम। फर्रुखनगर क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा खेड़ा खुर्रमपुर गांव के पास सवेरा कॉलेज के नजदीक हुआ। घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर है। मृतक पुलिसकर्मियों के परिवारों में मातम छा गया है। जानकारी के अनुसार, सोमवार रात करीब 11 बजे ईआरवी गाड़ी नंबर-254 हरिनगर डूमा क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस कंट्रोल रूम से फर्रुखनगर इलाके में झगड़े की सूचना मिली। सूचना मिलते ही ईआरवी में तैनात हेड कांस्टेबल छोटेलाल, हेड कांस्टेबल अनिल और कांस्टेबल धर्मेंद्र तुरंत मौके के लिए रवाना हुए। पुलिस टीम फर्रुखनगर की ओर जा रही थी। जब उनकी गाड़ी खेड़ा खुर्रमपुर गांव में सवेरा कॉलेज के पास पहुंची तो अचानक तेज रफ्तार ईआरवी सड़क किनारे खड़े पानी के टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके कई हिस्से टूटकर बिखर गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पानी का टैंकर एक ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ था और सड़क किनारे खड़ा था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, टैंकर पर कोई लाइट या रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ था। अंधेरे के कारण पीछे से आ रही ईआरवी के चालक को टैंकर दिखाई नहीं दिया और गाड़ी सीधे उससे जा टकराई। हादसे के बाद तीनों पुलिसकर्मी गाड़ी के अंदर फंस गए। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद गाड़ी के क्षतिग्रस्त हिस्सों को हटाकर तीनों पुलिसकर्मियों को बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने हेड कांस्टेबल छोटेलाल और हेड कांस्टेबल अनिल को मृत घोषित कर दिया। वहीं कांस्टेबल धर्मेंद्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मेदांता अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने दोनों मृतक पुलिसकर्मियों के शवों को सिविल अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवा दिया है। मंगलवार को दोनों शवों का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा।

न्यूज ब्रीफ

गुरुग्राम में कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले भाजपा कार्यालय के आसपास धारा 163 लागू

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम। जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त उत्तम सिंह ने सेक्टर-31 स्थित भाजपा जिला कार्यालय गुरुकमल के 300 मीटर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह कदम मंगलवार को कांग्रेस के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था, सार्वजनिक शांति और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। आदेश के अनुसार बिना अनुमति पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। इसके अलावा हथियार, लाठी, तलवार या अन्य आपत्तिजनक सामान लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। सड़क जाम करने और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। यह आदेश पुलिस व ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

हिसार एयरपोर्ट पर बंद रनवे पर उतरा चार्टर्ड प्लेन, बड़ा हादसा टला

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार। हिसार एयरपोर्ट पर मंगलवार को एक बड़ा हादसा टल गया। मुंबई से आए एक चार्टर्ड विमान ने गलती से बंद रनवे पर लैंडिंग कर दी। लैंडिंग के दौरान विमान का एक पंख रनवे पर लगी कैट आई से टकरा गया, जिससे विमान को नुकसान पहुंचा। हालांकि, इस घटना में पायलट और सभी यात्री सुरक्षित बच गए। घटना की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट अधिकारियों और संबंधित विभागों की टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में लैंडिंग में हुई चूक सामने आई है। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विमान संचालन और रनवे व्यवस्था को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। हादसे के बाद एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है।

यमुनानगर में बेकाबू हाइड्रा क्रेन की चपेट में आईं दो महिलाएं, एक की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर। यमुनानगर में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां हाइड्रा मशीन ने दो महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी बाजू कट गई। घटना के दौरान एक तीन साल की बच्ची भी साथ थी, जो टक्कर के बाद उछलकर सड़क पर जा गिरी, लेकिन वह सुरक्षित बच गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों और हाइड्रा चालक की लापरवाही की जांच की जा रही है।

केसरी रेलवे स्टेशन के पास गैस सिलेंडर फटा, मकान की दीवार ढही

भारतेन्दु संवाददाता, अंबाला। अंबाला के केसरी रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार को एक मकान की रसोई में गैस सिलिंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में घर में मौजूद दीपक कुमार गंभीर रूप से झुलस गया। उसकी हालत नाजुक होने पर उसे नागरिक अस्पताल से चंडीगढ़ सेक्टर-32 रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, दीपक खाना खाने के लिए घर आया था। बंद रसोई में गैस लीक होने के कारण गैस का दबाव जमा हो गया था। जैसे ही उसने खाना गर्म करने के लिए चूल्हा जलाया, गैस ने आग पकड़ ली। इसके बाद सिलिंडर का पाइप तेज धमाके के साथ फट गया। धमाके से रसोई की दीवार ढह गई और दरवाजे भी टूट गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

बहादुरगढ़ में डंडों से पीटकर व्यक्ति की हत्या, झाड़ियों में फेंका शव मिला

भारतेन्दु संवाददाता, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ के बेरी रोड पर व्यक्ति की हत्या मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मृतक की पहचान सत्यपाल निवासी शाहजहांपुर के रूप में हुई है। बेटे की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थाना सेक्टर-6 प्रभारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।

दो मासूम बच्चों की हत्या कर पिता ने फंदा लगाया, बहादुरगढ़ फ्लैट में मिले तीनों के शव

भारतेन्दु संवाददाता, बहादुरगढ़

हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित ओमैक्स सिटी से मंगलवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक फ्लैट में पिता और उसके दो मासूम बच्चों के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि पिता ने पहले दोनों बच्चों की हत्या की और बाद में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

जानकारी के अनुसार, घटना के समय मृतक की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। जब वह घर लौटी या परिजनों ने फ्लैट में कोई हलचल नहीं देखी, तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। फ्लैट में पिता और दोनों बच्चों के शव पड़े मिले। इसके बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं और हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है।

फिलहाल पुलिस आत्महत्या के लिए उकसाने, पारिवारिक विवाद, मानसिक तनाव या अन्य संभावित कारणों की भी पड़ताल कर रही है। हालांकि घटना के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। पड़ोसियों के अनुसार, परिवार सामान्य दिखाई देता था, इसलिए इस घटना से सभी हैरान हैं।

अंबाला में जमीन सौदे के इकरारनामे के बाद 19 लाख हड़पे, न रजिस्ट्री की न लौटाई

भारतेन्दु संवाददाता, अंबाला

अंबाला के पंजोखरा थाना क्षेत्र के निवासी नरेंद्र सिंह के साथ जमीन के सौदे के नाम पर 19 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपितों ने जमीन बेचने का इकरारनामा किया और किस्तों में लाखों रुपये ले लिए, लेकिन न तो जमीन की रजिस्ट्री कराई और न ही रकम वापस लौटाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, शिकायत में बलबीर कौर, उसके बेटे परविन्द्र सिंह निवासी गांव जिआन, जिला होशियारपुर (पंजाब) तथा सचिन भल्ला निवासी श्याम नगर एक्सटेंशन, तिलक नगर, नई दिल्ली को नामजद किया गया है। तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता नरेंद्र सिंह, जो गांव बरनाला स्थित राजा गार्डन के निवासी हैं, ने बताया कि 12 जून 2025 को उनका बलबीर कौर और परविन्द्र सिंह के साथ गांव जिआन, जिला होशियारपुर स्थित 7 कनाल जमीन खरीदने का सौदा 48 लाख रुपये में तय हुआ था। दोनों पक्षों के बीच इकरारनामा भी किया गया।

इसके बाद आरोपितों ने सौदे के तहत उनसे अलग-अलग समय पर 19 लाख रुपये ले लिए। नरेंद्र सिंह का आरोप है कि पूरी प्रक्रिया के बावजूद आरोपित लगातार रजिस्ट्री टालते रहे। जब उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री कराने या अपनी रकम वापस देने की मांग की तो आरोपितों ने टालमटोल शुरू कर दी। काफी प्रयासों के बाद भी न तो जमीन की रजिस्ट्री कराई गई और न ही 19 लाख रुपये लौटाए गए।

रेवाड़ी में महिला ने जहर खाकर दी जान

भारतेन्दु संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले में एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। महिला की शादी करीब सात साल पहले हुई थी और पिछले तीन साल से पति-पत्नी के बीच तलाक का मामला अदालत में चल रहा था। परिजनों के अनुसार, महिला काफी समय से मानसिक तनाव में थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि घरेलू विवाद और लंबित तलाक का मामला महिला की परेशानी का कारण हो सकता है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।

एक करोड़ 67 लाख लोगों का एसआईआर पूरा, 80 फीसदी डिजिटाइजेशन कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ

भारतेन्दु संवाददाता, कुरुक्षेत्र

हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाता सूची से जुड़े एन्यूमरेशन फॉर्मों के डिजिटाइजेशन कार्य ने अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया है। मंगलवार इस प्रक्रिया का अंतिम दिन है। चुनाव आयोग के अनुसार प्रदेश में कुल 2 करोड़ 6 लाख 55 हजार 929 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से 1 करोड़ 67 लाख 3 हजार 944 मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्मों का डिजिटाइजेशन पूरा किया जा चुका है। यह कुल कार्य का 80.87 प्रतिशत है, जबकि 19.13 प्रतिशत काम अभी शेष है।

चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार सभी जिलों में टीमें लगातार कार्य कर रही हैं ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिक से अधिक फॉर्मों का डिजिटाइजेशन पूरा किया जा सके। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और पारदर्शी बनाना है। डिजिटाइजेशन पूरा होने के बाद मतदाता रिकॉर्ड का सत्यापन और अद्यतन करना भी अधिक आसान होगा। प्रदेश के जिलों की प्रगति पर नजर डालें तो फतेहाबाद सबसे आगे है। यहां 92.54 प्रतिशत एन्यूमरेशन फॉर्मों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है, जिससे यह जिला प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंच गया है।

वहीं गुरुग्राम इस सूची में सबसे पीछे है, जहां अन्य जिलों की तुलना में कार्य की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में केवल दो जिले ऐसे हैं, जहां डिजिटाइजेशन का कार्य 90 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर पाया है। बाकी जिलों में भी कार्य तेजी से जारी है और संबंधित अधिकारियों को शेष काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर अभियान मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके माध्यम से पात्र मतदाताओं का सही रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, जिससे भविष्य में चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों से समयबद्ध तरीके से शेष कार्य पूरा करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटाइजेशन पूरा होने के बाद प्राप्त आंकड़ों का मिलान कर अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी। इससे दोहराव, त्रुटियों और अपात्र प्रविष्टियों को हटाने में सहायता मिलेगी तथा आगामी चुनावों की तैयारियां अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी ढंग से पूरी की जा सकेंगी।

फेसबुक प्रोफाइल क्लोनिंग का आरोपी दिल्ली से दबोचा

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद। फतेहाबाद के टोहाना में फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों से ठगी करने वाले साइबर आरोपी को पुलिस ने पश्चिमी दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान न्यू महावीर कॉलोनी निवासी सुनील कुमार शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने एक व्यक्ति के रिश्तेदार के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाई थी। इसके बाद आरोपी ने पीड़ित संदीप सिंह से संपर्क कर खुद को उसका रिश्तेदार बताया और विदेश से पैसे भेजने का झांसा दिया। इस बहाने कथित वीजा एजेंट के माध्यम से उससे 35 हजार रुपये की ऑनलाइन ठगी की गई। शिकायत मिलने के बाद टोहाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। साइबर सेल की मदद से तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई गई। पुलिस मामले में पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

पति पर अप्राकृतिक संबंध बनाने का आरोप, 24 दिन बाद महिला को निकाला

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर

हरियाणा के यमुनानगर में दूसरी शादी के महज 24 दिन बाद एक महिला को कथित तौर पर घर से निकाल दिए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने पति पर अप्राकृतिक संबंध बनाने, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने तथा धोखे से विवाह करने का आरोप लगाया है। महिला का यह भी कहना है कि विवाह कराने वाले बिचौलिए ने परिवार और पति के बारे में गलत जानकारी देकर रिश्ता तय कराया था।

पीड़िता के अनुसार, शादी के शुरुआती दिनों से ही पति का व्यवहार बदल गया था। उसने आरोप लगाया कि पति उसकी इच्छा के विरुद्ध अप्राकृतिक संबंध बनाने का दबाव डालता था। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। महिला का कहना है कि जब उसने इसका विरोध किया तो उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। महिला ने आरोप लगाया कि विवाह से पहले बिचौलिए ने पति के स्वभाव, पारिवारिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया। यदि उसे सही जानकारी दी जाती तो वह यह रिश्ता कभी स्वीकार नहीं करती। घर से निकाले जाने के बाद उसने अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी और उनकी मदद से पुलिस से संपर्क किया।

पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता के आरोपों की हर पहलू से जांच की जाएगी। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के सभी तथ्यों और जिम्मेदारियों की स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी। मामले के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भी चर्चा का माहौल है।

भिवानी के बंसीलाल अस्पताल में छत गिरने की घटना, जांच के सख्त निर्देश हुए जारी

भारतेन्दु संवाददाता, भिवानी

चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में फॉल सीलिंग गिरने से घायल हुए विद्या नगर निवासी के मामले ने अब प्रशासनिक स्तर पर भी गंभीर रूप ले लिया है। घायल व्यक्ति के उपचार और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग सोमवार को आयोजित समाधान शिविर में प्रमुखता से उठाई गई। मामले को लेकर अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में आयोजित समाधान शिविर के दौरान गैर सरकारी सदस्य सुनील वर्मा नंबरदार ने इस घटना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर इस तरह की घटना गंभीर लापरवाही को दर्शाती है। उन्होंने मांग की कि घायल व्यक्ति का बेहतर उपचार सुनिश्चित किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी

अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। मामले पर संज्ञान लेते हुए डीडीपीओ सोमबीर कादयान ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को घटना की विस्तृत जांच करने और जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में फॉल सीलिंग का एक हिस्सा गिरने से विद्या नगर निवासी व्यक्ति घायल हो गया था। घटना के बाद अस्पताल की भवन सुरक्षा और रखरखाव व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हुए थे। इस घटना ने मरीजों और उनके परिजनों में भी चिंता बढ़ा दी थी।

इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने भी अपने भिवानी दौरे के दौरान इस घटना का संज्ञान लेते हुए विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए थे। अब समाधान शिविर में भी मामला उठने के बाद जांच प्रक्रिया को और गति मिलने की उम्मीद है। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अस्पताल की इमारत और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

एसआईआर में 28 लाख वोटर नहीं मिले, पंचकूला में सबसे ज्यादा मामले

हरियाणा में 28 लाख से ज्यादा वोटर्स का नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर, दावा-आपत्ति के दौरान मिलेगा सुधार का मौका

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं का सत्यापन नहीं हो पाया है। निर्वाचन विभाग के अनुसार प्रदेश में कुल 28 लाख 687 मतदाता ऐसे मिले हैं, जिनका बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) द्वारा सत्यापन नहीं किया जा सका। इन मतदाताओं को अब एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट) श्रेणी में रखा गया है। इसके चलते 21 जुलाई 2026 को जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में इन लोगों के नाम शामिल नहीं होंगे।

निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में नहीं आएंगे, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपना नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल करवाने का पूरा अवसर दिया जाएगा। इसके लिए 21 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय निर्धारित किया गया है। इस अवधि के दौरान पात्र नागरिक अपना नाम जुड़वाने, गलत जानकारी में सुधार करवाने या किसी अन्य त्रुटि को ठीक कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

एसआईआर अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अपडेट करना है। निर्वाचन विभाग की ओर से बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस प्रक्रिया में कई मतदाता अपने पुराने पते पर नहीं मिले, कुछ लोग दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके थे, जबकि कुछ मामलों में मृत्यु या दोहरे पंजीकरण की स्थिति सामने आई।

जिलावार आंकड़ों के अनुसार पंचकूला जिले में सबसे ज्यादा मतदाता ऐसे पाए गए हैं, जिनका सत्यापन नहीं हो सका। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम

एएसडी श्रेणी में शामिल किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अंतिम मतदाता सूची तैयार करने से पहले सभी दावों और आपत्तियों की जांच की जाएगी।

निर्वाचन विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद अपने नाम की जांच जरूर करें। अगर किसी योग्य व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है तो वह निर्धारित समय के अंदर आवेदन कर सकता है। आवेदन के लिए संबंधित बीएलओ, निर्वाचन कार्यालय या ऑनलाइन माध्यम का सहारा लिया जा सकता है।

अधिकारियों के मुताबिक, दावा-आपत्ति अवधि के बाद प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और सही पाए जाने वाले नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। वहीं, जो लोग इस अवधि में कोई दावा पेश नहीं करेंगे, उनके नाम अंतिम सूची से हटाए जा सकते हैं। मतदाता सूची में नाम होना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। इसलिए निर्वाचन विभाग ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपनी जानकारी की जांच करें और किसी भी तरह की गलती होने पर तुरंत सुधार के लिए आवेदन करें।

अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी ताकि चुनाव के दौरान सही और पारदर्शी मतदाता सूची उपलब्ध हो सके। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए सभी स्तरों पर जांच प्रक्रिया पूरी की जा रही है। दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद ही अंतिम सूची प्रकाशित होगी। इससे योग्य मतदाताओं को मतदान का अधिकार सुरक्षित मिलेगा और चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं निष्पक्ष बन सकेगी। अधिकारियों ने बताया कि सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समय सीमा के अनुसार पूरी की जा रही हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं में कथित गड़बड़ी पर अधिकारियों से पूछताछ तेज

दिल्ली हेल्थ स्कैम की परतें खोलने के लिए अस्पतालों की खरीद व्यवस्था की होगी पड़ताल

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली में सामने आए करीब 650 करोड़ रुपये के स्वास्थ्य घोटाले की जांच अब और आगे बढ़ गई है। दवा और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितताओं के बाद जांच का दायरा सरकारी अस्पतालों तक पहुंच गया है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि अस्पतालों में खरीद प्रक्रिया के दौरान किन नियमों का उल्लंघन किया गया और किस स्तर पर लापरवाही बरती गई।

मामले की शुरुआती जांच में दवा, मेडिकल उपकरण और अन्य स्वास्थ्य सामग्री की खरीद से जुड़े कई मामलों में गड़बड़ियों की आशंका जताई गई है। अधिकारियों के अनुसार, कुछ स्थानों पर खरीद प्रक्रिया, टेंडर व्यवस्था और आपूर्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच टीम यह भी देख रही है कि खरीदी गई सामग्री की गुणवत्ता, मात्रा और उपयोग की स्थिति क्या रही। जांच का दायरा बढ़ने के बाद दिल्ली के कई अस्पतालों से रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अस्पतालों में होने वाली खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करना जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा संबंध मरीजों की सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा होता है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ मामलों में नियमों की अनदेखी कर खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा उपकरणों की उपलब्धता, रखरखाव और उपयोग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जांच एजेंसियां संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ कर रही हैं, ताकि पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने जांच में पूरी सहायता करने की बात कही है और कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस मामले में जांच एजेंसियां दस्तावेजों की जांच के साथ-साथ वित्तीय लेन-देन और खरीद प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। अधिकारियों का मानना है कि विस्तृत जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि घोटाले में किन लोगों की भूमिका रही और किस स्तर पर गड़बड़ी हुई। 650 करोड़ रुपये के इस मामले ने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी खरीद प्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। प्रशासन का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कदम उठाए जाएंगे।

राजधानी के कई इलाकों में मरम्मत कार्यों के चलते होगी पावर कटौती

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली में बिजली संकट, 15 जुलाई को कई इलाकों में कटौती

दिल्ली के कई इलाकों में 15 जुलाई को बिजली आपूर्ति प्रभावित रहने वाली है। बिजली कंपनियों की ओर से रखरखाव और जरूरी तकनीकी कार्यों के चलते अलग-अलग क्षेत्रों में तय समय के लिए बिजली कटौती की जाएगी। इसके कारण लोगों को कुछ घंटों तक बिजली की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

बिजली विभाग के अनुसार, गर्मी के मौसम में बिजली नेटवर्क को बेहतर बनाए रखने और भविष्य में किसी बड़े फॉल्ट से बचने के लिए समय-समय पर मेंटेनेंस कार्य किया जाता है। इसी वजह से राजधानी के कई इलाकों में बिजली सप्लाई अस्थायी रूप से बंद रहेगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे कटौती के समय से पहले जरूरी काम पूरे कर लें और बिजली से जुड़े उपकरणों का सावधानी से इस्तेमाल करें। 15 जुलाई को बिजली कटौती अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर होगी। कुछ इलाकों में सुबह के समय बिजली बाधित रहेगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में दोपहर या शाम के दौरान सप्लाई प्रभावित हो सकती है। बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे अपने क्षेत्र के अनुसार कटौती का समय पहले से जांच लें।

प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पानी की मोटर, मोबाइल चार्जिंग और अन्य जरूरी कार्य समय से पूरा करने की सलाह दी गई है। बिजली विभाग ने कहा है कि निर्धारित समय के बाद आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह कटौती असुविधा के लिए नहीं बल्कि बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के उद्देश्य से की जा रही है।

फरीदाबाद इंडस्ट्री अलर्ट, मध्य-पूर्व तनाव से आयात-निर्यात पर खतरा

एजेंसी, नई दिल्ली

मध्य-पूर्व में बढ़ते युद्ध तनाव का असर अब फरीदाबाद के औद्योगिक क्षेत्र पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। शहर के उद्योगपतियों का कहना है कि यदि संघर्ष लंबे समय तक जारी रहा तो इसका सीधा प्रभाव कच्चे माल की कीमतों, आयात-निर्यात और उत्पादन लागत पर पड़ सकता है। उद्योग जगत पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा है और ऐसे समय में अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता से परेशानियां और बढ़ सकती हैं। उद्योगपतियों के अनुसार मध्य-पूर्व के कई देश वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। युद्ध की स्थिति लंबे समय तक बनी रहने पर परिवहन खर्च बढ़ सकता है और कच्चे माल की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। इससे मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य औद्योगिक उत्पादों के निर्माण की लागत में वृद्धि होने की संभावना है।

फरीदाबाद के उद्यमियों का कहना है कि महंगे कच्चे माल के कारण उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर घरेलू बाजार के साथ-साथ निर्यात कारोबार पर भी पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना उद्योगों के लिए चुनौती बन सकता है।

गुरुग्राम नगर निगम का एक्शन, कचरा फेंकने वाले पर 10 हजार का चालान

एजेंसी, नई दिल्ली

गुरुग्राम नगर निगम ने शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी अभियान के तहत नगर निगम की टीम ने पटेल नगर बांध क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकने के मामले में एक व्यक्ति पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। खास बात यह रही कि जुर्माने की राशि मौके पर ही ऑनलाइन माध्यम से जमा कराई गई।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए खुले स्थानों पर कचरा डालने वालों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्रों में कूड़ा फेंकना नियमों का उल्लंघन है और ऐसे लोगों के खिलाफ निर्धारित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। निगम की टीम ने निरीक्षण के दौरान पटेल नगर बांध क्षेत्र में गंदगी फैलाने वाले व्यक्ति की पहचान की और तत्काल कार्रवाई करते हुए चालान जारी किया। अधिकारियों ने बताया कि स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए नागरिकों की भागीदारी बेहद जरूरी है। लोगों से अपील की गई है कि वे घरों और दुकानों का कचरा निर्धारित स्थानों पर ही डालें और सार्वजनिक जगहों को साफ रखने में सहयोग करें। निगम ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी इस तरह के उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली के शाहदरा में दर्दनाक अंडरपास पर पलटी बेकाबू कार

एजेंसी, नई दिल्ली

पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में मस्कान चौक अंडरपास पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा मंगलवार सुबह हुआ, जिसमें कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि दुर्घटना में कार चालक को गंभीर चोट नहीं आई और वह सुरक्षित बच गया।

जानकारी के अनुसार, कार चालक अंडरपास से होकर गुजर रहा था। इसी दौरान तेज गति के कारण अचानक उसका वाहन नियंत्रण से बाहर हो गया और सड़क पर पलट गया। कार के पलटते ही मौके पर आसपास मौजूद लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने चालक को बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और स्थिति को संभाला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा काफी तेज था और कार कई बार पलटने के बाद सड़क पर रुक गई। हालांकि, कार में सवार व्यक्ति को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन पर नियंत्रण खोना हादसे की मुख्य वजह मानी जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि घटना की सही जानकारी मिल सके।

इस घटना के बाद यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अंडरपास और भीड़भाड़ वाले इलाकों में निर्धारित गति सीमा का पालन करें। तेज रफ्तार वाहन चलाने से न केवल चालक बल्कि अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित ड्राइविंग करने की अपील की है।

गुरुग्राम सड़क हादसे में बड़ा नुकसान, दो पुलिसकर्मी नहीं रहे

एजेंसी, नई दिल्ली। गुरुग्राम में हुए एक भीषण सड़क हादसे में गश्त कर रहे दो पुलिसकर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल है। घायल पुलिसकर्मी का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे में पुलिस की गश्ती गाड़ी भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार, पुलिसकर्मी इलाके में नियमित गश्त पर थे, तभी अचानक एक तेज रफ्तार वाहन ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने तुरंत सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दो पुलिसकर्मियों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर है। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और हादसे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस टक्कर मारने वाले वाहन और चालक के बारे में जानकारी जुटा रही है।

न्यूज ब्रीफ

नोएडा प्राधिकरण का बड़ा फैसला, अब भूखंडों के निर्माण पर होगी सख्त निगरानी

एजेंसी, नई दिल्ली। नोएडा प्राधिकरण ने आवंटित भूखंडों पर निर्माण कार्य की निगरानी को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब आवंटी भूखंडों पर होने वाले निर्माण की जांच संबंधित वर्क सर्किल के अधिकारी करेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य उन आवंटियों पर नजर रखना है, जो तय समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं और लंबे समय तक भूखंडों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, कई मामलों में भूखंड आवंटित होने के बाद भी निर्धारित अवधि में निर्माण शुरू नहीं किया जाता है। इससे जमीन का उचित उपयोग नहीं हो पाता और विकास योजनाओं पर भी असर पड़ता है। नई व्यवस्था के तहत अधिकारी नियमित रूप से मौके का निरीक्षण करेंगे और निर्माण की स्थिति की रिपोर्ट तैयार करेंगे। वर्क सर्किल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे आवंटित भूखंडों की स्थिति की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी नियमों का पालन करते हुए निर्माण कार्य समय पर पूरा हो। यदि किसी भूखंड पर लंबे समय तक निर्माण नहीं किया गया या नियमों का उल्लंघन पाया गया तो प्राधिकरण नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि इस कदम से शहर में भूमि के बेहतर प्रबंधन और नियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही खाली पड़े भूखंडों के कारण होने वाली समस्याओं को भी कम किया जा सकेगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्राधिकरण की निगरानी व्यवस्था और अधिक प्रभावी होने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि आवंटियों को भी समय पर निर्माण पूरा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे नोएडा के विकास को गति मिल सके।

गाजियाबाद कोर्ट सख्त, दुष्कर्म आरोपी को नहीं मिली राहत

एजेंसी, नई दिल्ली। गाजियाबाद की पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी विष्णु सैनी की पहली जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश नीरज गौतम ने मामले की गंभीरता और पीड़िता के नाबालिग होने को ध्यान में रखते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया। अभियोजन की ओर से दलील दी गई कि आरोपी पर लगे आरोप संवेदनशील प्रकृति के हैं और पीड़िता की उम्र को देखते हुए आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने आरोपी विष्णु सैनी के खिलाफ शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य जुटाए और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद आरोपी की ओर से अदालत में पहली बार जमानत के लिए आवेदन किया गया था।

ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक सुधार की बड़ी पहल, जल्द बनेगा एलिवेटेड रोड

एजेंसी, नई दिल्ली

ग्रेटर नोएडा में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और रोजाना लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए एक नए एलिवेटेड रोड के निर्माण की योजना तैयार की जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सेतु निगम को सर्वेक्षण करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीपीआर तैयार होने के बाद परियोजना की लागत, डिजाइन और निर्माण की समय-सीमा तय की जाएगी।

प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का मुख्य उद्देश्य डीएससी रोड पर तिलपता गांव के पास लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम को कम करना है। इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं, जिसके कारण सुबह और शाम के समय लंबा जाम लग जाता है। इससे कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नया एलिवेटेड रोड बनने के बाद वाहनों की आवाजाही अधिक सुगम होगी और यात्रा में लगने वाला समय भी कम होगा। अधिकारियों के अनुसार सर्वे के दौरान सड़क की वर्तमान स्थिति, यातायात का दबाव, आसपास के क्षेत्र का विकास और भविष्य की जरूरतों का आकलन किया जाएगा। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए डीपीआर तैयार की जाएगी। रिपोर्ट स्वीकृत होने के बाद परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस परियोजना से न केवल ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों के बीच संपर्क भी बेहतर होगा। बेहतर सड़क सुविधा मिलने से औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि लंबे समय से इस मार्ग पर जाम की समस्या बनी हुई है और एलिवेटेड रोड बनने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

गाजियाबाद में पिंक बूथ पर तड़पता रहा युवक, मदद न मिलने से गई जान

एजेंसी, नई दिल्ली

गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि एक युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क किनारे स्थित एक पिंक बूथ तक पहुंचा और काफी देर तक मदद की गुहार लगाता रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक बार-बार पानी और उपचार की मांग कर रहा था, लेकिन समय रहते उसे आवश्यक सहायता नहीं मिल सकी। आरोप है कि सूचना मिलने के बावजूद पुलिस ने तत्काल सक्रियता नहीं दिखाई, जिससे उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई।

स्थानीय लोगों ने युवक की स्थिति देखकर उसे संभालने की कोशिश की और पुलिस तथा एंबुलेंस को सूचना दी। लोगों का कहना है कि यदि समय पर चिकित्सीय सहायता मिल जाती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। काफी देर बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों में नाराजगी फैल गई और उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी परिस्थितियों की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि युवक घायल कैसे हुआ। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। अधिकारियों ने कहा है कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ताहिर हुसैन मामले में केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी, भाजपा और ओवैसी पर साधा निशाना

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली दंगों से जुड़े चर्चित मामले में ताहिर हुसैन को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन का आम आदमी पार्टी से अब कोई संबंध नहीं है और वर्ष 2020 में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद पार्टी ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया था। केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगने की स्थिति में पार्टी उसे संरक्षण देने के पक्ष में नहीं रही है।

केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वह इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए बार-बार उठा रही है। उनका कहना था कि भाजपा जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पुराने मामलों को उछाल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति कानून का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही केजरीवाल ने एआईएमआईएम और उसके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन अब ओवैसी की पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसलिए भाजपा को आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाने के बजाय इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि वर्तमान में वह किस राजनीतिक दल का हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा और ओवैसी की पार्टी दोनों इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं।

गुरुग्राम में सुंदरकांड पाठ से पहले कड़ी सुरक्षा

कांग्रेस के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए सख्त कदम

एजेंसी, नई दिल्ली

गुरुग्राम जिला प्रशासन ने कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा के जिला कार्यालय 'गुरुकमल' के बाहर प्रस्तावित सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम को देखते हुए एहतियातन बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने मंगलवार को जिला भाजपा कार्यालय और उसके आसपास के क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार यह निर्णय कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के उद्देश्य से लिया गया है।

गुरुग्राम में धारा 163 लागू, कांग्रेस कार्यक्रम पर रोक

जारी आदेश के तहत निर्धारित क्षेत्र में बिना अनुमति किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी या बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। इसके अलावा लाठी, डंडा, हथियार या ऐसी किसी भी वस्तु को लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेताओं ने भाजपा कार्यालय के बाहर सुंदरकांड पाठ आयोजित करने की घोषणा की थी। कार्यक्रम को लेकर पहले से ही राजनीतिक माहौल गर्म था। इसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और पूरे इलाके में लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जारी आदेशों का पालन करें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। अधिकारियों का कहना है कि सभी आवश्यक कदम केवल शांति, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं। जिला प्रशासन ने यह भी कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी उचित निर्णय लिए जाएंगे, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और शहर में सामान्य स्थिति बनी रहे।

आरआरयू चोरी कर विदेश भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़

एजेंसी, नई दिल्ली

मोबाइल टावरों से रिमोट रेडियो यूनिट (आरआरयू) चोरी कर उन्हें नकली इनवाइस के जरिए विदेश भेजने वाले गिरोह का दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान हर्ष विहार निवासी हेमंत गुप्ता, संगम विहार निवासी विकास पासवान, गाजियाबाद निवासी फरीद और मेरठ निवासी शेर मोहम्मद के रूप में हुई है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 70 लाख रुपये कीमत की 43 चोरी की गई आरआरयू बरामद की हैं। जांच में सामने आया कि गिरोह चोरी किए गए टेलीकॉम उपकरणों को नकली दस्तावेजों के आधार पर एयरलाइन कार्गो के जरिए हांगकांग भेजता था। पुलिस ने दावा किया है कि इस कार्रवाई से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा में आरआरयू चोरी के 19 मामलों का खुलासा हुआ है। डीसीपी आदित्य गौतम के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि कई राज्यों में मोबाइल टावरों से चोरी किए गए आरआरयू को दिल्ली के ट्रांस-यमुना इलाके में जमा कर विदेश भेजा जा रहा है। इसके बाद जांच शुरू की गई। 10 जुलाई को पुलिस टीम को सूचना मिली कि चोरी की आरआरयू की खेप महिपालपुर स्थित कूरियर एजेंसी के जरिए भेजी जाने वाली है।

सूचना के आधार पर पुलिस ने महिपालपुर में जाल बिछाकर हेमंत गुप्ता को 19 चोरी की आरआरयू के साथ गिरफ्तार किया। इसके बाद फरीद और शेर मोहम्मद भी नौ चोरी की आरआरयू लेकर पहुंचे, जिन्हें पकड़ लिया गया। गोदाम की तलाशी में चार और आरआरयू बरामद हुईं। इसके अलावा एक पोर्टर के माध्यम से पहुंचाई जा रही 11 आरआरयू बरामद की गईं।

अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का 13वां जत्था रवाना

अमरनाथ यात्रा के 13वें जत्थे में 5,335 श्रद्धालु रवाना, सुरक्षा घेरे में आगे बढ़ा काफिला

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। वार्षिक अमरनाथ यात्रा के तहत मंगलवार सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से श्रद्धालुओं का 13वां जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में कुल 5,335 तीर्थयात्री शामिल रहे जो कश्मीर के बालटाल और पहलगाम स्थित दोहरे आधार शिविरों की ओर बढ़े। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने यात्रा मार्गों पर सुरक्षा के साथ-साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान लगातार यात्रा मार्गों पर तैनात हैं ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही सुरक्षित और सुचारू रूप से जारी रह सके।

संयुक्त पुलिस नियंत्रण कक्ष के अनुसार मंगलवार तड़के बालटाल मार्ग के लिए पहला काफिला सुबह 2 बजकर 42 मिनट पर रवाना हुआ जबकि पहलगाम मार्ग की ओर जाने वाला काफिला सुबह 3 बजकर 10 मिनट पर निकला। सुरक्षा घेरे में निकले इस जत्थे में 1,736 श्रद्धालुओं ने बालटाल मार्ग को चुना जबकि 3,599 तीर्थयात्री पारंपरिक पहलगाम मार्ग से आगे बढ़े। दोनों मार्गों पर सुरक्षा बलों की विशेष निगरानी रखी जा रही है। यात्रा मार्ग पर संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।

93 हजार से अधिक श्रद्धालु हुए रवाना।

उमड़ा आस्था का सैलाब

अमरनाथ यात्रा धार्मिक आस्था के साथ-साथ जम्मू कश्मीर की संस्कृति और पर्यटन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर साल देश और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस वर्ष भी श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।

पहलगाम मार्ग से आगे बढ़े 5,335 तीर्थयात्री

इस जत्थे में 3,911 पुरुष श्रद्धालु, 1,288 महिला श्रद्धालु, 21 बच्चे, 90 साधु, 24 साध्वियां और एक ट्रांसजेंडर तीर्थयात्री शामिल थे। श्रद्धालुओं को लेकर रवाना हुए काफिले में कुल 232 वाहन शामिल रहे। इनमें 138 बसें, 36 मध्यम मोटर वाहन, 57 हल्के मोटर वाहन और एक दोपहिया वाहन शामिल था।

93 हजार से अधिक श्रद्धालु पहुंचे बाबा के दरबार

13वें जत्थे के प्रस्थान के साथ ही इस वर्ष भगवती नगर जम्मू आधार शिविर से अमरनाथ गुफा मंदिर की ओर रवाना होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 93 हजार से अधिक पहुंच गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से यात्रा मार्गों पर लगातार रौनक बनी हुई है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए उत्साह और आस्था के साथ यात्रा कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के ठहरने भोजन चिकित्सा और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया गया

जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। चंद्रकोट रामबन और बनिहाल जैसे प्रमुख स्थानों पर सुरक्षाबलों की विशेष तैनाती की गई है। यात्रा काफिलों की सुरक्षित आवाजाही के लिए यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया जा रहा है। सुरक्षा कारणों से कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही को निर्धारित समय और योजना के अनुसार संचालित किया जा रहा है।

पूर्ण राज्य बहाली की मांग पर एनसी का बड़ा ऐलान, दिल्ली में करेगी प्रदर्शन

अनुमति नहीं मिली तो गिरफ्तारी देगी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलती है, तब भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत सभी एनसी विधायक दिल्ली पहुंचकर विरोध दर्ज कराएंगे और आवश्यकता पड़ने पर गिरफ्तारी भी देंगे। इस मुद्दे को लेकर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और 16 जुलाई तक प्रशासन की ओर से अनुमति मिलने का इंतजार करने का फैसला किया है।

एनसी नेताओं का कहना है कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू-कश्मीर के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग है। उनका मानना है कि यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि जनता के अधिकारों और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा विषय है। पार्टी का कहना है कि यदि समय रहते अनुमति मिल जाती है तो जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं अनुमति नहीं मिलने की स्थिति में भी पार्टी अपने कार्यक्रम में बदलाव नहीं करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराएगी।

प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देश के 52 राजनीतिक दलों को भी समर्थन के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि अब तक किसी भी दल ने औपचारिक रूप से अपनी सहमति नहीं दी है। जम्मू-कश्मीर सरकार की सहयोगी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों की ओर से भी अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसके बावजूद एनसी का कहना है कि पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली का मुद्दा उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पूर्ण राज्य की बहाली की मांग को लेकर दिल्ली कूच की तैयारी में नेशनल कॉन्फ्रेंस।

न्यूज ब्रीफ

सोपोर में ड्रग तस्कर की 1.23 करोड़ की संपत्ति जब्त

भारतेंदु संवाददाता, सोपोर। सौ दिवसीय 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और तेज करते हुए सोपोर पुलिस ने एक फरार और कुख्यात ड्रग तस्कर की 1.23 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की दो अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में एक दो मंजिला आवासीय मकान (चारदीवारी सहित) तथा सर्वे नंबर 365 मिन के तहत 1 कनाल 10 मरला भूमि शामिल है। इन दोनों संपत्तियों का कुल मूल्य 1.23 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है।

जम्मू-कश्मीर में नशामुक्ति पंजीकरण के लिए आधार जरूरी

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने ड्रग डी-एडिक्शन रजिस्ट्री पोर्टल के तहत रजिस्टर करने वाले लोगों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी कर दिया है। इस कदम का मकसद पूरे केंद्र शासित प्रदेश में डी-एडिक्शन सेवाओं में ज्यादा पारदर्शिता लाना और उनके गलत इस्तेमाल को रोकना है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जारी एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार डीडीआरपी के जरिए इलाज कराने वाले लाभार्थियों को आधार का इस्तेमाल करके अपनी पहचान वेरिफाई करनी होगी या आधार नंबर होने का सबूत देना होगा।

पुंछ में भालू का आतंक जारी, एक व्यक्ति घायल, 6 बकरियां भी बनीं शिकार

भारतेंदु संवाददाता, पुंछ। मंडी सब-डिविजन के सावजियां सुंदरी इलाके में मंगलवार को एक जंगली भालू के हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। घायल व्यक्ति की पहचान मोहम्मद सादिक पुत्र मोहम्मद अली निवासी सावजियां सुंदरी के तौर पर हुई है। जानकारी के अनुसार मोहम्मद सादिक पर भालू ने अचानक हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। उसे तुरंत सावजियां ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे आगे के इलाज के लिए सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडी रेफर कर दिया।

कठुआ: कमरे में फंदे से लटका मिला नाबालिग, जांच में जुटी पुलिस

भारतेंदु संवाददाता, कठुआ। रामकोट क्षेत्र से लगभग 25 किलोमीटर दूर पंचायत अगली धार क्षेत्र में 16 वर्षीय युवक सोनू कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी अगली धार वार्ड नंबर 1 ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर में फंदा लगाया। जानकारी के अनुसार सोनू कुमार ने अपने चचेरे भाई को नकली पैसे देकर दुकान पर भेजा और वहां से खाने के लिए चिप्स और कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। इसी बात को लेकर चाचा ने सोनू से सवाल किया। थोड़ी देर बाद रमेश कुमार जब कमरे के अंदर पहुंचा तो उसे फंदे से लटका हुआ बालक का शव मिला।

बुड्ढा अमरनाथ यात्रा से पहले प्रशासन अलर्ट तैयारियों का लिया जायजा

भारतेंदु संवाददाता, पुंछ। आने वाली श्री बुड्ढा अमरनाथ जी यात्रा 2026 से पहले तहसीलदार हवेली अजहर मजीद और पुंछ इंस्पेक्टर तानिया गुप्ता ने विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों और विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर पुंछ में तीर्थयात्रियों के ठहरने की जगहों का संयुक्त निरीक्षण किया। दौरे के दौरान टीम ने उन जगहों का निरीक्षण किया जहां सालाना यात्रा के दौरान श्रद्धालु ठहरेंगे।

ठाठरी कस्बे के निवासियों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन

भारतेंदु संवाददाता, डोडा। डोडा जिले के ठाठरी कस्बे के निवासियों ने मंगलवार को जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि 7 जुलाई को भीषण बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के बाद से कई इलाकों में पीने के पानी की आपूर्ति बाधित है। आर्मी आरपी गेट के पास निवासियों का एक समूह इकट्ठा हुआ और उन्होंने जल शक्ति विभाग के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने विभाग पर पिछले सात दिनों से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उनके इलाके में पानी की आपूर्ति बहाल न करने का आरोप लगाया।

18 जुलाई से जम्मू-कश्मीर में बदलेगा मौसम, भारी बारिश का अलर्ट जारी

पहाड़ी इलाकों में बरसेंगे बादल, भूस्खलन को लेकर प्रशासन सतर्क।

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। मौसम विभाग ने 18 जुलाई से जम्मू-कश्मीर में मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव आने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार, 17 जुलाई तक प्रदेश में मौसम सामान्य रूप से गर्म और उमस भरा रहेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन 18 जुलाई से वर्षा की गतिविधियों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने खासकर संवेदनशील इलाकों में भारी बारिश, अचानक बाढ़ और भूस्खलन को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है।

पूर्वानुमान के अनुसार, 18 जुलाई से आसमान में आंशिक से लेकर पूर्ण रूप से बादल छाए रहेंगे और जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। जम्मू संभाग के कुछ क्षेत्रों में कम समय में अत्यधिक तेज बारिश होने की भी आशंका है। 20 से 22 जुलाई के बीच बारिश का दौर और तेज होने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार वर्षा हो सकती है, जबकि 21 जुलाई को सबसे अधिक बारिश होने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि चिनाब घाटी, पीर पंजाल पर्वतमाला और कश्मीर संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण अचानक बाढ़, भूस्खलन और चट्टानें गिरने जैसी घटनाएं हो सकती हैं।

लद्दाख: लेह और कारगिल की तर्ज पर अब सातों जिलों में होगी हिल काउंसिल

भारतेंदु संवाददाता, लेह। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने घोषणा की है कि केंद्र शासित प्रदेश के सभी सात जिलों में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों का गठन किया जाएगा। इस कदम को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्तर पर शासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अब तक केवल लेह और कारगिल जिलों में ही निर्वाचित स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदें कार्य कर रही थीं। नए फैसले के बाद शाम नुब्रा चांगथांग ज़ांस्कर और द्रास समेत सभी नए जिलों को भी वही अधिकार मिलेंगे जो लेह और कारगिल को प्राप्त हैं।

मुख्य सचिव ने बताया कि लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम की धारा 3(1) के तहत प्रत्येक जिले में परिषद बनाने का प्रावधान पहले से मौजूद है। इसके लिए अब जरूरी कानूनी संशोधन और निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन पूरा किया जाएगा। अप्रैल 2026 में शाम नुब्रा चांगथांग ज़ांस्कर और द्रास को नए जिले के रूप में अधिसूचित किए जाने के बाद लद्दाख में जिलों की संख्या दो से बढ़कर सात हो गई थी। अब इन सभी जिलों में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचित परिषदों का गठन किया जाएगा।

> **लद्दाख** स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम की धारा 3(1) के तहत प्रत्येक जिले में परिषद बनाने का प्रावधान पहले से मौजूद है। इसके लिए अब जरूरी कानूनी संशोधन और निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन पूरा किया जाएगा। नई परिषदों को लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम के तहत पूरी शक्तियां प्रदान की जाएंगी।
> -लद्दाख प्रशासन।

नई परिषदों को लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम के तहत पूरी शक्तियां प्रदान की जाएंगी। इन परिषदों के पास अपने जिले के भीतर जमीन से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण अधिकार होंगे। इनमें भूमि के मालिकाना हक और जमीन के आवंटन जैसे विषय शामिल हैं। नए जिलों की परिषदें अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार इन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेंगी।

श्रीनगर के नक्शबंद साहिब में दूसरे दिन भी रही सख्त पाबंदी

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के पुराने शहर स्थित नक्शबंद साहिब और नौहट्टा इलाकों में शहीद दिवस के मद्देनजर लगातार दूसरे दिन भी एहतियाती पाबंदियां लागू रहीं। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। संवेदनशील इलाकों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई तथा कई स्थानों पर बैरिकेड लगाकर लोगों की आवाजाही पर निगरानी रखी गई। अधिकारियों के अनुसार यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया ताकि नक्शबंद साहिब स्थित शहीद कब्रिस्तान में किसी बड़े जमावड़े को रोका जा सके और शांति व्यवस्था बनी रहे।

◆ **सुरक्षा व्यवस्था कायम रही**

प्रशासन ने बताया कि नक्शबंद साहिब के साथ-साथ नौहट्टा और पुराने शहर के अन्य संवेदनशील हिस्सों में भी सुरक्षा बल लगातार गश्त करते रहे। सोमवार को भी पूरे इलाके को सील कर दिया गया था और मंगलवार को भी वही व्यवस्था जारी रखी गई। सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए थीं ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो। अधिकारियों का कहना है कि लोगों की सुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। दरअसल 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर हुए गोलीकांड में 22 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी। इस घटना की स्मृति में वर्षों तक 13 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता रहा।

पहलगाम हमले के आरोपी हाफिज सईद को गैर-जमानती वारंट जारी

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को बड़ी सफलता मिली है। जम्मू की विशेष एनआईए अदालत ने लश्कर-ए-ताइबा के संस्थापक और पाकिस्तान स्थित आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने यह आदेश एनआईए द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र पर सुनवाई के बाद पारित किया। जांच एजेंसी ने हाफिज सईद को पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रचने वाले प्रमुख आरोपियों में शामिल किया है। एनआईए का कहना है कि हाफिज सईद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-ताइबा और उसके सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) की गतिविधियों का संचालन करता है तथा भारत विरोधी आतंकी साजिशों में उसकी अहम भूमिका रही है।

एनआईए के अनुसार हाफिज सईद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा का निवासी है और लंबे समय से गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा है। एजेंसी ने अदालत से उसके खिलाफ खुली अवधि वाला गैर-जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया था ताकि उसके विरुद्ध आगे की कानूनी प्रक्रिया प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाई जा सके। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले की निष्पक्ष, व्यापक और प्रभावी जांच के लिए आरोपी की गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। इसके बाद वारंट को तामील कराने के लिए एनआईए जम्मू के उप महानिरीक्षक को भेज दिया गया है।

एनआईए द्वारा दाखिल पूरक आरोपपत्र में हाफिज सईद पर भारतीय न्याय संहिता 2023 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। एजेंसी का मानना है कि पहलगाम हमले की साजिश सीमा पार से रची गई थी और इसमें आतंकी संगठनों की सक्रिय भूमिका रही। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर हाफिज सईद का नाम आरोपियों में शामिल किया गया है।

एशिया की बड़ी मीठे पानी की झीलों में शामिल वुलर बनी आकर्षण केंद्र

नीले पानी और पहाड़ों के बीच वुलर झील बनी पर्यटकों की नई पसंद, दुनियाभर से आ रहे पर्यटक

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित वुलर झील अब पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यह झील सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। नीले पानी का विशाल विस्तार चारों ओर फैले पहाड़ और झील के आसपास दिखाई देने वाले विभिन्न प्रजातियों के पक्षी पर्यटकों को एक अलग अनुभव दे रहे हैं। लंबे समय तक डल झील और गुलमर्ग जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के पीछे रहने वाली वुलर झील अब अपनी अलग पहचान बना रही है।

गुरेज घाटी और उत्तर कश्मीर के अन्य पर्यटन स्थलों की यात्रा करने वाले कई पर्यटक अब वुलर झील पर भी रुकने लगे हैं। झील का मनमोहक दृश्य व शांत वातावरण लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वुलर विंटेज पार्क सनसेट पॉइंट और अन्य खूबसूरत स्थान पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं।

वुलर झील की खूबसूरती ने पर्यटकों को बनाया अपना दीवाना।

कश्मीर का नया पर्यटन गंतव्य बन रही वुलर झील

पर्यटकों की बढ़ती संख्या से स्थानीय लोगों को भी फायदा मिल रहा है। झील पर नाव चलाने वाले लोगों खाने पीने की दुकान लगाने वाले छोटे कारोबारियों और अन्य स्थानीय व्यवसायियों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस वर्ष वुलर झील पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा और दिल्ली से आए कई पर्यटकों ने वुलर झील की खूबसूरती की सराहना की है। उनका कहना है कि यह झील अपनी विशालता और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण डल झील से अलग अनुभव देती है। हालांकि स्थानीय लोग अभी भी बेहतर सड़क सुविधा ठहरने की व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जरूरत महसूस कर रहे हैं।

नागालैंड में आईईडी ब्लास्ट ने छीना सेना का जवान, सेना ने दी श्रद्धांजलि

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। नागालैंड के चुमौकेदिमा जिले में ड्यूटी के दौरान हुए संदिग्ध आईईडी विस्फोट में जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के रहने वाले असम राइफल्स के हवलदार मोहम्मद इकबाल बलिदान हो गए। इस घटना में चार अन्य जवान घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। विस्फोट के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और घटना की गहन जांच की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, असम राइफल्स का एक काफिला सोखुवी क्षेत्र से दीमापुर लौट रहा था। इसी दौरान चुमौकेदिमा जिले के सोखुवी गांव के पास अचानक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसकी चपेट में काफिले के वाहन आ गए। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई है कि यह हमला पहले से लगाए गए आईईडी के माध्यम से किया गया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि विस्फोट में 28 असम राइफल्स में तैनात हवलदार मोहम्मद इकबाल ने सर्वोच्च बलिदान दिया। वह असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल, शोक्हुवी में तैनात थे। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

चुमौकेदिमा के पुलिस उपायुक्त निको वेन्यू ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बम निरोधक दस्ते और फोरेंसिक विशेषज्ञों को मौके पर भेजा गया है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि विस्फोट में किस प्रकार के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया और क्या यह हमला सुरक्षाबलों के काफिले को निशाना बनाकर पूर्व नियोजित तरीके से किया गया था।

◆ **आईईडी धमाके में असम राइफल्स के हवलदार मोहम्मद इकबाल बलिदान**

◆ **नागालैंड हमले में पुंछ के जवान ने दी सर्वोच्च कुर्बानी**

सांबा के खेत में मिला संदिग्ध ड्रोन, फोरेंसिक जांच शुरू

भारतेंदु संवाददाता, सांबा। जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में मंगलवार सुबह एक खेत से संदिग्ध ड्रोन मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। अधिकारियों के अनुसार, चक सलारिया निवासी एक व्यक्ति सुबह मॉर्निंग रन के दौरान देवक क्षेत्र के पास कृषि भूमि में पड़े ड्रोन को देखकर तुरंत सेना को सूचना दी। सूचना मिलते ही सेना की टीम मौके पर पहुंची और ड्रोन को अपने कब्जे में लेकर क्षेत्र की जांच की। प्रारंभिक आशंका है कि ड्रोन का संबंध सीमा पार की किसी गतिविधि से हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। ड्रोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है ताकि उसकी तकनीकी विशेषताओं, उड़ान मार्ग और संभावित उपयोग का पता लगाया जा सके। जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि ड्रोन भारतीय सीमा में कैसे पहुंचा और क्या इसका इस्तेमाल किसी संदिग्ध या अवैध गतिविधि के लिए किया गया था।

◆ **ड्रोन मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क**

पांच सौ करोड़ चांदी मामले में जांच तेज, अधिकारी तलब

वैष्णो देवी चढ़ावा मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर से जुड़े करीब 500 करोड़ रुपये के कथित नकली चांदी चढ़ावा मामले में जम्मू की चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अदालत ने क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी को संबंधित रिकॉर्ड के साथ तलब किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई तय की है। यह मामला मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाई गई चांदी में कथित मिलावट और उसके उपयोग में अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा है, जिसकी जांच को लेकर अदालत ने गंभीर रुख अपनाया है।

मामले की शुरुआत तब हुई जब अधिवक्ता दीपक शर्मा ने 9 मई को आईजी क्राइम ब्रांच और एसएसपी क्राइम ब्रांच ईओडब्ल्यू जम्मू के समक्ष शिकायत दर्ज कर कथित अनियमितताओं की एफआईआर दर्ज करने की मांग की। शिकायतकर्ता का आरोप था कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई चांदी के संरक्षण और उपयोग में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं। कार्रवाई में देरी होने पर उन्होंने अदालत का रुख किया और जांच की प्रगति रिपोर्ट तथा एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की।

रामबन में खाई में गिरा उत्खनन यंत्र, ऑपरेटर की मौत

भारतेंदु संवाददाता, रामबन। रामबन जिले में सड़क निर्माण परियोजना के दौरान सोमवार रात एक दर्दनाक हादसे में एलएंडटी का उत्खनन यंत्र गहरी खाई में गिर गया, जिससे उसके ऑपरेटर की मौत हो गई। यह दुर्घटना चंदरकोट थाना क्षेत्र के गजपथ किला इलाके में हुई। पुलिस के अनुसार, हादसे की सूचना रात करीब साढ़े आठ बजे मिली, जिसके बाद रामबन पुलिस और नागरिक त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) के स्वयंसेवक तत्काल मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया।

◆ **सड़क निर्माण के दौरान उत्खनन यंत्र दुर्घटनाग्रस्त ऑपरेटर की मौत**

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सड़क निर्माण कार्य के दौरान उत्खनन यंत्र अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से फिसल गया और कई सौ फीट गहरी खाई में जा गिरा। दुर्घटना के बाद मशीन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसका ऑपरेटर उसके नीचे दब गया। बचाव दल ने जेसीबी मशीन और अन्य उपकरणों की सहायता से कई घंटों तक राहत एवं बचाव कार्य चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद देर रात ऑपरेटर का शव मलबे के नीचे से बाहर निकाला गया।

मृतक की पहचान डोडा जिले के कहारा निवासी अख्तर हुसैन के रूप में हुई है, जो हुसैन खंडे के पुत्र थे। शव को पोस्टमार्टम और अन्य चिकित्सा-कानूनी औपचारिकताओं के लिए जिला अस्पताल रामबन भेज दिया गया है। पुलिस ने घटना का मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारी यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हादसा तकनीकी खराबी, सड़क की स्थिति या किसी अन्य कारण से हुआ। इस घटना के बाद निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

न्यूज ब्रीफ

बच्चों ने कराटे बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट में दिखाई प्रतिभा

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। जिला कांगड़ा के गांव धलूं (एएमडीपीएस स्कूल योल कैंट) के बच्चों ने कराटे बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यह टेस्ट जिला हमीरपुर के नादौन में हुआ, जिसमें शितोरियो से फूकान कराटे के करोह चीफ इंस्ट्रक्टर आर. पी. डोगरा ने बच्चों की परीक्षा ली। ग्रेडिंग टेस्ट में दो बच्चों ने जूनियर प्राउन थर्ड डिग्री व एक बच्चे ने जूनियर ग्रीन बेल्ट का टेस्ट सफलतापूर्वक पास किया। इन बच्चों को कांगड़ा के कराटे प्रशिक्षक सेंसेई अमित कुमार ने प्रशिक्षण दिया है। चीफ इंस्ट्रक्टर आरपी. डोगरा ने सफल खिलाड़ियों को बधाई देते हुए बताया कि अब उन्हें दिल्ली में आयोजित होने वाली आगामी कराटे प्रतियोगिता के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं, धलूं गांव में 20 से 25 जुलाई तक कराटे प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा।

एनटीपीसी कोलडैम में पौधरोपण अभियान शुरू

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एनटीपीसी कोलडैम परियोजना क्षेत्र में पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। हिमाचल प्रदेश के प्रधान मुख्य अरण्यपाल (पीसीसीएफ) डॉ. संजय सूद ने पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की और पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया। एनटीपीसी कोलडैम परियोजना के परियोजना प्रमुख एसएस राव ने कहा कि हरित आवरण बढ़ाने, जैव विविधता के संरक्षण व सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए परियोजना क्षेत्र में लगातार पौधरोपण व पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। डॉ. संजय सूद ने कहा कि पौधे लगाने के साथ-साथ उनका संरक्षण और देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने बताया कि बिलासपुर वन मंडल में इस वर्ष विभिन्न योजनाओं के तहत 50 हजार से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। ग्रीन एडॉप्शन स्कीम के तहत एसीसी बरमाणा के सहयोग से 5 हजार पौधे तथा ग्रीन क्रेडिट स्कीम के तहत एनटीपीसी के सहयोग से 50 हेक्टेयर क्षेत्र में वन विकास कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर वन विभाग और एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

एमसी के कार्यालय भवन का शिलान्यास और दुकानों का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू बुधवार को हमीरपुर का दौरा करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह करीब 11 बजे हमीरपुर पहुंचेंगे। थोड़ी देर के लिए सर्किट हाउस में रुकने के बाद वह करीब 11:45 बजे बस स्टैंड के सामने रानी झांसी पार्क के पास नगर निगम की 11 दुकानों का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह टाउन हॉल के परिसर में नगर निगम के कार्यालय भवन का शिलान्यास भी करेंगे। शिलान्यास के बाद वह टाउन हॉल में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद मुख्यमंत्री शिमला लौट जाएंगे। डीसी गंधर्व राठौड़ ने नगर निगम के अधिकारियों को उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

एबीवीपी ने सरकार पर लगाए राजनीति के आरोप

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के स्कूली विद्यार्थी कार्य के प्रदेश संयोजक विशाल ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देउरी के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर उद्घाटन किए बिना ही मौके से लौट गए और बाद में उद्घाटन पट्टिका भी हटा दी गई। विशाल ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2023 में आई आपदा के दौरान देउरी स्कूल का भवन क्षतिग्रस्त हुआ था। इसके बाद नए भवन का निर्माण किया गया, लेकिन उद्घाटन प्रक्रिया पूरी न होने से विद्यार्थियों को नए भवन में बैठने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में राजनीति कर रही है और छात्रों की सुविधा को नजरअंदाज किया जा रहा है। एबीवीपी ने मांग की है कि नवनिर्मित स्कूल भवन को तुरंत विद्यार्थियों के लिए खोला जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा जैसे विषय पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

16 व 18 जुलाई को बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बिजली उपमंडल-1 के सहायक अभियंता ई. सन्नी जगोता ने बताया कि छडोल अनुभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में बिजली लाइनों की आवश्यक मरम्मत और पेड़ों की कांट-छांट के कार्य के चलते 16 और 18 जुलाई को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि 16 जुलाई को कल्लर, तरसली, तुन्दू, डाबर, कोट, गंबर, जामली, नेरी और छडोल सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इसी प्रकार 18 जुलाई को डाबर, जामली, नेरी, छडोल, बनाली तथा आसपास के क्षेत्रों में निर्धारित समय के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि यह शटडाउन मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से सहयोग बनाए रखने की अपील की है।

निगम व बोर्ड कर्मियों ने लंबित पेंशन बहाली मांगी

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न निगमों और बोर्डों के करीब 6500 सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की लंबित पेंशन का मामला एक बार फिर उठ गया है। वन निगम कर्मचारी महासंघ के पूर्व उपाध्यक्ष हेम सिंह रावत ने कहा कि पेंशन न मिलने से प्रभावित परिवार आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 1999 में तत्कालीन सरकार ने निगमों एवं बोर्डों के कर्मचारियों के लिए पेंशन संबंधी अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत 1999 से 2004 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है। वहीं, 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित रखा गया है। हेम सिंह रावत ने कहा कि कई कर्मचारी ऐसे हैं, जो 2004 से पहले नियुक्त हुए थे, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। उन्होंने इसे समानता और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मांग की कि वर्ष 1999 की पेंशन अधिसूचना को दोबारा लागू कर निगमों और बोर्डों के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जाए। उन्होंने कर्मचारी संगठनों और जनप्रतिनिधियों से भी इस मांग को प्रभावी रूप से उठाने की अपील की।

ग्रामीणों को किया जागरूक, योजनाओं का बताया लाभ

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने विशेष प्रचार अभियान चलाया। अभियान के तहत झंडूता विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बड़गांव और बल्हसीणा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में विभाग द्वारा अनुमोदित मां वैष्णों सांस्कृतिक दल बरठीं के कलाकारों ने लोकगीतों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को शिक्षा, रोजगार, गृह अनुदान, स्वास्थ्य योजनाओं, सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण तथा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी दी। कलाकारों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के माध्यम से पात्र लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा कार्यक्रम में नशे के दुष्प्रभावों को लेकर भी ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर करीब 70 से 80 लोगों ने भाग लिया। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से सरकारी योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में मिलती है और पात्र लोग इनका लाभ उठा सकते हैं। कार्यक्रम में दोनों पंचायतों के प्रधानों, उपप्रधानों, वार्ड सदस्यों, महिला मंडल पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने ममलीग में ग्रीन पंचायत योजना के तहत सौर ऊर्जा परियोजना का किया उद्घाटन

पंचायत को होगी 14 लाख वार्षिक आय

अनिल कुमार शर्मा/भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से जिला सोलन की ग्राम पंचायत ममलीग में ग्रीन पंचायत योजना के अंतर्गत 500 किलोवाट क्षमता की ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। दो करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना का कार्य 23 दिसंबर, 2024 को आरंभ किया गया था तथा 24 फरवरी, 2026 को विद्युत ग्रिड से जोड़ दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से वर्तमान में लगभग 3000 यूनिट प्रतिदिन स्वच्छ बिजली का उत्पादन हो रहा है तथा वार्षिक लगभग आठ लाख यूनिट उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि बिजली खरीद समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड 3.50 रुपए प्रति यूनिट खरीद करेगा, जिससे राज्य को स्वच्छ ऊर्जा के साथ-साथ दीर्घकालिक एवं स्थिर राजस्व प्राप्त होगा। सुक्खू ने कहा कि इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका जनहितकारी राजस्व वितरण मॉडल है तथा प्राप्त आय का 25 प्रतिशत ग्राम पंचायत के विकास कार्यों, 25 प्रतिशत अनाथों एवं विधवाओं के कल्याण, 20 प्रतिशत प्रदेश सरकार, 20 प्रतिशत हिमऊर्जा तथा 10 प्रतिशत संचालन एवं रखरखाव पर खर्च किया जाएगा। इससे स्थानीय समुदाय को प्रत्यक्ष आर्थिक एवं सामाजिक लाभ प्राप्त होंगे। इस परियोजना से ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष 14 लाख रुपए की आय होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष की परियोजना आयु वाली यह सौर ऊर्जा परियोजना स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास तथा सामाजिक समृद्धि का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रदेश के सतत विकास लक्ष्यों को सशक्त बनाने के साथ-साथ ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम सिद्ध होगी। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयास कर रही है तथा पंचायतों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण करना इस दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती से उगाए गए उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है और दूध को भी देश में सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि गांवों में भी शहरों की तर्ज पर सुविधाएं मिलें। ममलीग में उपस्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार ला रही है। मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से आज सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों के 80 प्रतिशत से ज्यादा पद भरे जा चुके हैं। इसके अलावा पैरा मेडिकल स्टाफ और टेक्नीशियन के पद भी भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश के सरकारी संस्थानों में एमआरआई, थ्री टेस्ला और रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना प्रारम्भ हो गई हैं, जो पहले केवल बड़े शहरों और बड़े अस्पतालों में थीं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ भी राज्य सरकार ने एक बड़ा अभियान छेड़ा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सभी वर्गों को अपना सहयोग देना चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश चिट्टा मुक्त बन सके। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी शिमला में उपस्थित थे।

बिलासपुर पुलिस ने 13 .39 ग्राम चिट्टे सहित 2 आरोपी किए काबू

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला बिलासपुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए दो युवकों को चिट्टा (हेरोइन) सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13.39 ग्राम चिट्टा, एक इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन तथा अन्य संबंधित सामान बरामद किया है।

मामले में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया कि पुलिस थाना कोट कहलूर की टीम ने गांव जंडोरी के समीप गश्त के दौरान मोटरसाइकिल (एचपी-20बी-5305) को जांच के लिए रोका। तलाशी लेने पर आरोपियों के कब्जे से 13.39 ग्राम चिट्टा, एक इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन और अन्य सामान बरामद हुआ। इसके बाद दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धनपत उर्फ गोल्डी पुत्र तेजू राम तथा रोहित कुमार उर्फ रोतू पुत्र विधि चंद, दोनों निवासी गांव बरोठा डवाला, डाकघर तरसूह, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना कोट कहलूर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि बरामद चिट्टा कहां से लाया गया था, इसकी आपूर्ति किसके माध्यम से की जा रही थी और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की क्या भूमिका है। अभिषेक धीमान ने कहा कि जिला पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि यदि कहीं नशा तस्करी या मादक पदार्थों के कारोबार की जानकारी मिले तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समाज को नशे के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके।

शिक्षा विभाग का काम ही भाजपा के आरोपों का सबसे बड़ा जवाब : रोहित

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा उनसे इस्तीफा मांगे जाने पर पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा बिना किसी ठोस आधार के विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के पिछले साढ़े तीन वर्षों के काम और उपलब्धियां ही सभी आरोपों का सबसे बड़ा जवाब हैं। उनके अनुसार प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधार राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहे हैं। रोहित ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सर्वेक्षणों व परफॉर्मेंस इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश की स्थिति लगातार बेहतर हुई है। उन्होंने दावा किया कि राज्य आज शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उनके अनुसार एएसईआर रिपोर्ट, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स और साक्षरता सहित कई मानकों पर हिमाचल ने उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि अब शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल की तुलना केरल जैसे अग्रणी राज्यों से की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन परियोजनाओं को लेकर भाजपा सवाल उठा रही है, उनका शिलान्यास और उद्घाटन पूरी सरकारी प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया है। उन्होंने कहा कि वह इस विषय पर अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि शिक्षा विभाग का काम ही सबसे बड़ा जवाब है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भाजपा की ओर से श्वेत पत्र जारी करने की मांग पर भी शिक्षा मंत्री ने प्रतिक्रिया दी।

बिलासपुर में 23 को कैंपस इंटरव्यू

भारतेनदु संवाददाता, बिलासपुर। जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर युवाओं के लिए 23 जुलाई को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगा। जिला रोजगार अधिकारी राजेश मैहता ने बताया कि प्रात: 11 बजे जिला रोजगार कार्यालय परिसर में एम/एस ByS Solutions प्राइवेट लिमिटेड, बद्दी के सहयोग से कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कंपनी आईटीआई फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, टूल एंड डाई मेकर/मशीनिस्ट तथा टर्नर के कुल 50 पदों पर भर्ती करेगी। संबंधित ट्रेड में दो वर्षीय आईटीआई उत्तीर्ण 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 14,060 रुपए प्रतिमाह वेतन के साथ चाय-नाश्ता, रियायती भोजन, दीपावली बोनस, अर्जित अवकाश का नकदीकरण तथा पूर्ण उपस्थिति पर 400 रुपए का अटेंडेंस रिवॉर्ड जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।

चक्की दरिया में अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त, उपायुक्त पठानकोट से मांगी रिपोर्ट

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। हिमाचल-पंजाब सीमा पर चक्की दरिया में डी-सिल्टिंग व बाढ़ सुरक्षा कार्यों की आड़ में बड़े पैमाने पर कथित अवैध खनन के आरोपों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

बेदी बजरी कंपनी के कार्यक्षेत्र से जुड़े मामले में स्थानीय निवासियों और पूर्व पार्षद योगेश ठाकुर द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पठानकोट के उपायुक्त (डीसी) से मौके की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) पठानकोट के सचिव को भी स्थल का निरीक्षण कर स्वतंत्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि डी-सिल्टिंग के नाम पर चक्की दरिया से बड़े पैमाने पर रेत, बजरी व मिट्टी निकाली जा रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि मौके पर जेसीबी मशीनों के माध्यम से लगातार खनन किया गया और प्रतिदिन करीब 100 ट्रकों में सामग्री बाहर भेजी गई। आरोप है कि यह सामग्री दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कर रही मेघा इंजीनियरिंग कंपनी को उपलब्ध कराई गई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर व्यावसायिक खनन के बावजूद अनिवार्य पर्यावरण स्वीकृति (एनवायरनमेंट क्लीयरेंस) नहीं ली गई। दूसरी ओर, खनन विभाग का कहना है कि बाढ़ के दौरान पानी का प्रवाह सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से हाईवे परियोजना के लिए मिट्टी उठाने की अनुमति दी गई थी और इसके बदले निर्धारित रॉयल्टी भी वसूली गई है। विभाग का यह भी दावा है कि राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए सामग्री उपलब्ध कराने के कुछ मामलों में पर्यावरण स्वीकृति संबंधी प्रावधान अलग हो सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने 2013 में चक्की पुल के आसपास खुदाई पर लगाए गए प्रतिबंध, पुल ढहने की घटना तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों का हवाला देते हुए कहा है कि मौजूदा खनन से पर्यावरण, नदी की संरचना और आसपास के गांवों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच, प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन पर तत्काल रोक तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। अब सभी की निगाहें 22 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

राम मंदिर चढ़ावा घोटाले के विरोध में कांग्रेस की पदयात्रा

प्रभु श्रीराम की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस नेताओं ने किया भजन-कीर्तन

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। अयोध्या स्थित प्रभु श्रीराम मंदिर में कथित चढ़ावा गड़बड़ी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर के नेतृत्व में मंगलवार को शहर में पदयात्रा निकाली गई।

पदयात्रा गांधी चौक से शुरू होकर मुख्य बाजार से होते हुए सत्यनारायण मंदिर पहुंची, जहां कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने प्रभु श्रीराम की प्रतिमा के समक्ष भजन-कीर्तन कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, पूर्व विधायक अनीता वर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुमन भारती शर्मा सहित कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहे। रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर पारदर्शिता व जवाबदेही की मांग करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराया। सीएम के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि भगवान श्रीराम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं और उनके नाम पर एकत्रित प्रत्येक रुपए का हिसाब देश की जनता को मिलना चाहिए। यदि चंदे के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, तो सरकार और संबंधित संस्थाओं का दायित्व है कि पूरे मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराई जाए। कांग्रेस का विरोध किसी धर्म या आस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार व जवाबदेही की कमी के खिलाफ है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुमन भारती शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा भगवान श्रीराम और देश की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करती रही है, लेकिन यदि श्रद्धालुओं के विश्वास से खिलवाड़ हुआ है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जनता द्वारा श्रद्धा से दिए गए चंदे का एक-एक पैसा सार्वजनिक होना चाहिए। इसी मांग को लेकर कांग्रेस ने शांतिपूर्ण पदयात्रा व भजन-कीर्तन के माध्यम से अपनी बात रखी है। पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने भी कहा कि धार्मिक आस्था के नाम पर किसी भी प्रकार की अनियमितता स्वीकार नहीं की जा सकती और पूरे मामले में सत्य जनता के सामने आना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि भगवान श्रीराम के नाम पर श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चंदे के संबंध में उठे सवालों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए, ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास कायम रहे।

कांग्रेस को राम मंदिर पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं : विजय

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री ने मंगलवार को जारी प्रेस बयान में मुख्यमंत्री सुक्खू और कांग्रेस सरकार पर हमला बोला।

उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी दस चुनावी गारंटियों की कथित विफलता, प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, बढ़ते कर्ज और प्रशासनिक नाकामी से जनता का ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस सरकार भगवान श्रीराम के नाम पर राजनीति कर रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री वास्तव में प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं, तो राम मंदिर पर बयानबाजी करने के बजाय हिमाचल प्रदेश की वास्तविक आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भगवान श्रीराम और राम मंदिर पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उनके अनुसार, कांग्रेस ने वर्षों तक श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन का विरोध किया और अब राजनीतिक लाभ के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को मुद्दा बना रही है। पूर्व विधायक ने कहा कि भ्रष्टाचार पर बोलने से पहले कांग्रेस को अपने शासनकाल में सामने आए विभिन्न चर्चित घोटालों पर भी जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का राजनीतिक इतिहास भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों से जुड़ा रहा है, इसलिए उसे भाजपा पर आरोप लगाने से पहले आत्ममंथन करना चाहिए। अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री से पूछा कि प्रदेश की दस चुनावी गारंटियों का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा, युवाओं को रोजगार, किसानों और बागवानों से किए गए आश्वासन, कर्मचारियों एवं पेंशनरों की समस्याओं का समाधान तथा प्रदेश की आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दों पर सरकार को जनता के सामने स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

स्टाफ नर्स के 71 पदों पर भर्ती

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश ने स्टाफ नर्स के 71 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। जिला रोजगार अधिकारी बिलासपुर ने बताया कि इन पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों के नाम रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रायोजित किए जाएंगे। जिला बिलासपुर के जीएनएम और बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जो निर्धारित श्रेणी और बैच के अनुसार पात्र हैं, 20 जुलाई, 2026 तक अपना पंजीकरण संबंधित रोजगार कार्यालय में अवश्य करवाएं। उन्होंने बताया कि जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण पहले से रोजगार कार्यालय में है, वे भी अपने पंजीकरण एवं पात्रता संबंधी विवरण की पुष्टि कर लें, ताकि नाम प्रायोजन के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो। भर्ती में अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल तथा स्वतंत्रता सेनानी आश्रित श्रेणियों के लिए पद निर्धारित किए गए हैं। पात्रता संबंधित बैच के आधार पर तय की गई है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर के दूरभाष 01978-222450 पर कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं।

पुरस्कृत एनआईटी हमीरपुर में एनसीसी एयर विंग का दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न

एनसीसी एयर विंग के कैंप में मंडी कॉलेज ओवरऑल विजेता

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के परिसर में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की एयर विंग का दस दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर (एटीसी-223) मंगलवार को संपन्न हो गया।

समापन अवसर पर शिविर के कमांडेंट व 1एचपी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी, कुल्लू के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर कुणाल शर्मा ने विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। महाविद्यालयों के वर्ग में वल्लभ राजकीय कालेज मंडी को समग्र चैंपियन घोषित किया गया। इस संस्थान ने कुल 18 स्वर्ण एवं 9 रजत पदक जीते। ड्रिल और अनुशासन की ट्रॉफी भी इसी संस्थान के नाम रही। एसोसिएट एनसीसी अधिकारी फ्लाइंग ऑफिसर डॉ. चमन इस संस्थान का नेतृत्व किया। फ्लाइंग ऑफिसर निश्चल शर्मा के नेतृत्व में 11 स्वर्ण और 16 रजत पदकों के साथ डिग्री कॉलेज कुल्लू ने दूसरा स्थान हासिल किया। विद्यालयों के वर्ग में डीएवी स्कूल मंडी ने 4 स्वर्ण व 8 रजत पदकों के साथ समग्र चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पनारसा 4 स्वर्ण एवं 4 रजत पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। सीनियर वर्ग में कुल्लू कॉलेज के अभिषेक और वंशिका को अपने-अपने वर्गों में बेस्ट कैडेट घोषित किया गया। जूनियर वर्ग में रावमापा पनारसा के तरुण और रावमापा जरी की प्रिया गुरुंग बेस्ट कैडेट रहीं। मंडी कालेज के मनीष बेस्ट एथलीट बने। ड्रिल प्रतियोगिता में मंडी कॉलेज और डीएवी मंडी अपने-अपने वर्गों में अव्वल रहे। सीनियर वर्ग की .22 राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में मंडी कालेज के शिवम ठाकुर और आईआईटी मंडी की भाग्यश्री प्रथम रही। स्कीट शूटिंग प्रतियोगिता में मंडी कालेज के यतिंद्र और दीपिका अव्वल रहीं।

विंग कमांडर कुनाल शर्मा ने सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई दी तथा शिविर में भाग लेने वाले प्रत्येक कैडेट की अनुशासनप्रियता, समर्पण, उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं उच्च मनोबल की सराहना की। उन्होंने कहा कि एटीसी-233 का प्रमुख उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, आपसी सहयोग, अनुशासन, राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्र सेवा की भावना का विकास करना था। उन्होंने शिविर के सफल आयोजन में सहयोग के लिए एनआईटी के निदेशक प्रोफेसर एचएन सूर्यवंशी, संस्थान के अन्य सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों, एसोसिएट एनसीसी अधिकारियों, पीआई स्टाफ, सिविल स्टाफ, एरो मॉडलिंग टीम, मोटिवेशनल स्पीकर्स और अन्य अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।

समापन अवसर पर कैडेटों ने देशभक्ति गीत, समूह नृत्य, लघु नाटिका और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से खूब समां बांधा। शिविर के समापन की पूर्व संध्या पर प्रतिभागी कैडेटों के अलावा हिमाचल प्रदेश के मशहूर कलाकारों व म्यूजिकल बैंड ने भी खूब मनोरंजन किया।

जरूरतमंद परिवार की मदद के लिए आगे आया मंजूषा सहायता केंद्र, दी 7000 रुपए की आर्थिक सहायता

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। इन दिनों सिल्ह क्षेत्र में जनगणना प्रगणक के रूप में सेवाएं दे रहे सुभाष शर्मा ने एक जरूरतमंद परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए मानवीय पहल की है। उन्होंने गांव सिल्ह निवासी स्वर्गीय सूरम सिंह के परिवार की समस्या को मंजूषा सहायता केंद्र कलोल के समक्ष रखा, जिसके बाद संस्था ने परिवार की सहायता के लिए कदम उठाया।

जानकारी के अनुसार, पिछले वर्ष भारी बारिश और भूस्खलन के कारण सूरम सिंह का मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर गिर गया था। वर्तमान में उनकी पत्नी जमना देवी और उनके दो बेटे एक जर्जर रसोई में रहने को मजबूर हैं। इस अस्थायी आवास का एक हिस्सा प्लास्टिक त्रिपाल से ढका हुआ है, जिससे परिवार को हर समय खतरा बना रहता है। परिवार के पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं है। परिवार का एक बेटा शारीरिक रूप से कमजोर है, जबकि दूसरा बेटा पढ़ाई के साथ निजी स्कूल में काम कर रहा है, जहां उसे मात्र 2000 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। यह राशि उसके आने-जाने के खर्च में ही समाप्त हो जाती है। प्रशासन की ओर से परिवार को केवल एक त्रिपाल उपलब्ध करवाई गई थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद मंजूषा सहायता केंद्र कलोल ने परिवार की मदद की। संस्था के अध्यक्ष कर्नल जसवंत सिंह चंदेल ने बताया कि संस्था पहले भी इस परिवार की सहायता कर चुकी है। इसी क्रम में बुधवार को बुधी सिंह पुत्र स्वर्गीय सूरम सिंह को 7000 रुपए की आर्थिक सहायता चेक के माध्यम से प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि इस सहायता राशि में संस्था के एक सदस्य द्वारा गुप्त रूप से दिए गए 2000 रुपए भी शामिल हैं। कर्नल चंदेल ने सुभाष शर्मा की संवेदनशील पहल की सराहना करते हुए कहा कि उनकी वजह से जरूरतमंद परिवार तक सहायता पहुंच सकी।

पाउला बडोसा का खूबसूरत अंदाज

स्पेन। पाउला बडोसा स्पेन की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। उनका जन्म 15 नवंबर 1997 को न्यूयॉर्क में हुआ था। उन्होंने जूनियर स्तर पर फ्रेंच ओपन खिताब जीता।

फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल अटलांटा स्टेडियम में फिर जीवंत होगी पुरानी प्रतिद्वंद्विता, अर्लिंग्टन में होगा फुटबॉल का रोमांच

मेस्सी का जादू चलेगा या केन का करिश्मा

एजेंसी, अटलांटा

विश्व फुटबॉल की सबसे चर्चित प्रतिद्वंद्विताओं में शुमार अर्जेंटीना और इंग्लैंड बुधवार को विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आमने-सामने होंगे। मुकाबले का सबसे बड़ा आकर्षण लियोनेल मेस्सी और हैरी केन की टक्कर होगी। मौजूदा टूर्नामेंट में मेस्सी आठ और केन छह गोल कर चुके हैं। दोनों दिग्गज पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच 2005 के बाद कोई मुकाबला नहीं हुआ।

इंग्लैंड के लिए मेस्सी को रोकना सबसे बड़ी चुनौती होगी, जबकि अर्जेंटीना की रक्षापंक्ति को केन और शानदार फॉर्म में चल रहे जूड बेलिंगहम से सतर्क रहना होगा। बेलिंगहम भी छह गोल कर चुके हैं और क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे के खिलाफ दो गोल दागकर टीम को जीत दिलाई थी।

दोनों देशों के बीच फुटबॉल प्रतिद्वंद्विता का इतिहास बेहद तीखा रहा है। 1966 विश्व कप में अर्जेंटीना के कप्तान एंटोनियो रैटिन को रेड कार्ड, 1982 के फॉकलैंड संघर्ष, 1986 में डिएगो माराडोना का चर्चित 'हैंड ऑफ गॉड' गोल और 1998 में डेविड बेकहम का रेड कार्ड इस मुकाबले को हमेशा खास बनाते रहे हैं।

मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना लगातार 12 विश्व कप मैचों से अजेय है। हालांकि नॉकआउट चरण में उसे केप वर्दे, मिस्र और स्विट्जरलैंड के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर इंग्लैंड ने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करने के बाद मैक्सिको और नॉर्वे को हराकर अंतिम चार में जगह बनाई।

इंग्लैंड की चिंता राइट-बैक पोजीशन है। जेरेल क्वांसा निलंबित हैं, जबकि रीस जेम्स की फिटनेस सवालों में है। ऐसे में एजरी कोंसा या जेड स्पेंस को जिम्मेदारी मिल सकती है। अर्जेंटीना के सभी खिलाड़ी उपलब्ध हैं और कोच लियोनेल स्कालोनी को मेस्सी के साथ जूलियन अल्वारेज़ या लोटारो मार्टिनेज में से किसी एक का चयन करना होगा।

अब तक दोनों टीमों के बीच पांच मुकाबले हुए हैं, जिनमें इंग्लैंड ने तीन और अर्जेंटीना ने दो जीते हैं। विश्व कप में दोनों का रिकॉर्ड 2-2 से बराबर है। ऐसे में यह मुकाबला सिर्फ फाइनल का टिकट नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा की जंग भी होगा।

फ्रांस मारेगा लगातार तीसरे फाइनल में एंट्री या स्पेन खत्म करेगा 16 साल का सूखा?

एजेंसी, अर्लिंग्टन

फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन और फ्रांस की भिड़ंत होने वाली है। 16 साल के बाद स्पेन ने अंतिम-4 में जगह बनाई है। तो वहीं 2 बार की चैंपियन फ्रेंच टीम के भी हौसले बुलंद हैं। इस मुकाबले में सिर्फ मैदान पर खिलाड़ियों की नहीं बल्कि फुटबॉल की 2 महाशक्तियों की भिड़ंत होने वाली है। एकतरफ से लामिन यामाल होंगे तो दूसरी ओर उन्हें रोकने के लिए किलीयन एम्बाप्पे ताल ठोकेंगे। यानी फैंस को एक दम पैसा वसूल टक्कर देखने को मिलने वाली है। भारतीय समयानुसार मैच की शुरुआत 14 जुलाई को देर रात 12:30 बजे होने वाली है।

पहले सेमीफाइनल का मेला डलास में सजने वाला है। 14 जुलाई को भारतीय समयानुसार देर रात 12 बजकर 30 मिनट पर मुकाबले की शुरुआत होने वाली है। फ्रांस और स्पेन इस वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत टीमों में से एक हैं। फ्रेंच टीम ने ग्रुप स्टेज में सेनेगल, इराक और नॉर्वे को मात दी। फिर राउंड ऑफ 32 में स्वीडन को 3-0 से हराया, अगले चरण में पैराग्वे को 1-0 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से धूल चटाकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।

दूसरी ओर स्पेन का दबदबा भी कायम रहा। केप वर्डे के खिलाफ पहला मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद टीम ने अपनी असली रफ्तार पकड़ी। दूसरे मैच में साउदी अरब को 4-0 से मात दी। उरुग्वे को 1-0 से हराया। राउंड ऑफ 32 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ 3-0 से जीत दर्ज की। पुर्तगाल को राउंड ऑफ 16 में बाहर किया। वहीं आखिरी मैच में बेल्जियम को 2-1 से हराकर अंतिम-4 में जगह बनाई।

स्पोर्ट्स विंडो

संतुलित आक्रामकता भारत की टेस्ट मैच में सफलता का राज: मजूमदार

एजेंसी, लंदन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में मिली 270 रन की शानदार जीत का श्रेय संतुलित आक्रामकता और अनुशासित प्रदर्शन को दिया। उन्होंने कहा कि बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने बुनियादी बातों पर अमल करते हुए टीम को यादगार जीत दिलाई। मजूमदार ने दूसरी पारी में 113 रन की शानदार पारी खेलने वाली यास्तिका भाटिया की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि चोट से वापसी के बाद लॉर्ड्स जैसे ऐतिहासिक मैदान पर शतक लगाना विशेष उपलब्धि है। उनके अनुसार यास्तिका का शॉट चयन और पारी को संभालने का तरीका बेहतरीन रहा। तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने मैच में सात विकेट लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। पहली पारी में पांच और दूसरी में दो विकेट लेने वाली क्रांति की लाइन-लेंथ की सराहना करते हुए मजूमदार ने कहा कि उन्होंने अनुशासित गेंदबाजी से लगातार दबाव बनाए रखा। मजूमदार ने भारतीय बल्लेबाजी को टीम की सबसे बड़ी ताकत बताया और स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष को विश्व स्तरीय बल्लेबाज करार दिया।

टेस्ट कोच पद गंवाने के बाद मैकुलम ने मांगी माफी

एजेंसी, बर्मिंघम। ब्रेंडन मैकुलम ने राष्ट्रीय टेस्ट कोच के तौर पर अपने नतीजों के लिए इंग्लैंड के क्रिकेट प्रशंसकों से माफी मांगी है और माना कि 'अब किसी और को मौका देने का समय आ गया है।' मैकुलम सीमित ओवरों की टीम के प्रभारी बने रहे लेकिन रविवार को उन्हें टेस्ट क्रिकेट में इस भूमिका से हटा दिया गया जो वह 2022 से संभाल रहे थे। न्यूजीलैंड के इस खिलाड़ी ने पुष्टि की कि उन्हें हटाया गया था और उन्होंने खुद पद नहीं छोड़ा था जैसा कि इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा था। एजबेस्टन में सोमवार को उन्होंने कहा, ''हां, मुझे पद से हटा दिया गया। मैं निराश था लेकिन साथ ही मैं इस फैसले का पूरा सम्मान करता हूं। हम नतीजों पर आधारित खेल में हैं और असल में हमारे नतीजे उतने अच्छे नहीं थे। अब किसी और को मौका देने का समय आ गया है।'' इंग्लैंड के टेस्ट कोच के तौर पर मैकुलम का रिकॉर्ड 27 जीत, दो ड्रॉ और 20 हार का रहा। कप्तान बेन स्टोक्स के साथ उनके कार्यकाल को 'बैजबॉल' नाम दिया गया था। आक्रामक खेल ने टेस्ट क्रिकेट में नई जान फूंकी और शानदार नतीजे दिए।

एशियाई अंडर-19 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नौ भारतीय फाइनल में पहुंचे

एजेंसी, जकार्ता। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। अंडर-19 पुरुष और महिला वर्ग में भारत के नौ मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई, जबकि सेमीफाइनल में हारने वाले छह खिलाड़ियों ने कांस्य पदक अपने नाम किए। अंडर-19 महिला वर्ग में भारत की सभी आठ मुक्केबाज फाइनल में पहुंचीं। चाहत (60 किग्रा), अंशिका (75 किग्रा) और प्राची टोकस (+81 किग्रा) ने चीनी ताइपे की प्रतिद्वंद्वियों को हराया, जबकि मेघा श्योकंद (80 किग्रा) प्रतिद्वंद्वी के मुकाबला जारी नहीं रख पाने के कारण फाइनल में पहुंचीं। पुरुष वर्ग में आदित्य (55 किग्रा) और शुभम राजपूत (90 किग्रा) ने जीत दर्ज कर फाइनल का टिकट कटाया। वहीं, छह भारतीय मुक्केबाजों को सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक मिला। अंडर-23 वर्ग में भारत ने सात कांस्य पदक भी अपने नाम किए, जिससे चैंपियनशिप में उसका दबदबा लगातार कायम है।

सिंधू जापान ओपन के दूसरे दौर में

एजेंसी, टोक्यो

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू ने मंगलवार को यहां मलेशिया की वोंग लिंग चिंग पर सीधे गेम में जीत दर्ज करके जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के दूसरे दौर में जगह बनाई। विश्व रैंकिंग में नंबर 10 पर काबिज सिंधू ने अपने सहज खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले दौर में विश्व रैंकिंग में नंबर 37 पर काबिज वोंग को 21-14 21-11 से हराया।

भारत के ध्रुव कपिला और तनीशा क्रास्टो ने भी अपने मिश्रित युगल मुकाबले में स्कॉटलैंड के एलेक्जेंडर डन और जूली मैकफर्सन को 21-16, 21-14 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। हालांकि, रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे पहले ही दौर में शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन के फेंग यान झे और हुआंग डोंग पिंग से 11-21, 10-21 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए।

सिंधू ने शुरुआत से ही खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा और रैलियों की गति को नियंत्रित करते हुए 7-4 की बढ़त हासिल कर ली। हालांकि वोंग ने संघर्ष जारी रखने की कोशिश की, लेकिन उनकी गलतियों ने भारतीय खिलाड़ी को लगातार आगे बढ़ने का मौका दिया। सिंधू ने इंटरवल तक 11-6 की बढ़त बना ली। भारतीय खिलाड़ी रैलियों में सहज दिख रही थीं और उन्होंने अपने स्ट्रोक्स को प्रभावी ढंग से लगाकर अपनी बढ़त को 14-9 तक पहुंचा दिया। उनके बैकहैंड नेट ड्रिबल, ड्रॉप शॉट और हाफ-स्मैश सटीक रहे।

एक सीधे शॉट से सिंधू को सात गेम प्वाइंट मिले, और उन्होंने दूसरे पर पहला गेम अपने नाम कर लिया। सिंधू ने दूसरे गेम में भी शुरू से आक्रामक रवैया अपनाया और मलेशिया की खिलाड़ी को कोई मौका नहीं दिया। भारतीय खिलाड़ी ने जल्द ही 8-2 की बढ़त हासिल कर ली। सिंधू इंटरवल तक 11-3 से आगे थी। इसके बाद भी उन्होंने बड़ा अंतर बनाए रखा और फिर 10 मैच प्वाइंट हासिल किए। भारतीय खिलाड़ी ने दूसरे मैच प्वाइंट पर मैच अपने नाम कर दिया।

न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज की बराबर

एजेंसी, प्रोविडेंस (गयाना)

बाएं हाथ के स्पिनर जेडन लेनोक्स ने 19 रन देकर पांच विकेट लिए, जिससे न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ कम स्कोर वाले दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पांच विकेट से जीत हासिल करके सीरीज बराबर कर ली। वेस्टइंडीज का स्कोर एक समय बिना किसी नुकसान के 63 रन था, लेकिन आखिर में उसकी टीम 36 ओवर में 138 रन पर आउट हो गई।

न्यूजीलैंड के लिए भी टर्न लेती पिच पर छोटे लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं रहा। उसका स्कोर भी एक समय पांच विकेट पर 96 रन था। उसके बाद टॉम लैथम (नाबाद 37) ने मार्क ब्रैसवेल (नाबाद 24) के साथ 37 रन की अटूट साझेदारी करके न्यूजीलैंड को 104 गेंद शेष रहते लक्ष्य तक पहुंचाया। न्यूजीलैंड ने 32.4 ओवर में पांच विकेट पर 141 रन बनाए। न्यूजीलैंड की यह वनडे में 400वीं जीत थी जिससे उसने पांच मैचों की सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। वेस्टइंडीज ने पहला मैच सात विकेट से जीता था।

लेनोक्स ने 31 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद अपने सातवें वनडे में पहली बार पांच विकेट लिए। उन्होंने एक ऐसे पतन की शुरुआत की जिससे जॉन कैंपबेल (43) और अकीम ऑगस्ट (18) के बीच पहले विकेट की अच्छी साझेदारी के बावजूद वेस्टइंडीज ने 65 रन के अंदर अपने सभी 10 विकेट गंवा दिए। उसके केवल चार बल्लेबाज ही दोहरे अंक तक पहुंचे। इनमें आमिर जांगू भी शामिल थे जिन्होंने 24 रन बनाए।

हेनरी निकोल्स (17) और विल यंग (28) ने न्यूजीलैंड को तेज शुरुआत दी तथा पहले विकेट के लिए लगभग पांच रन प्रति ओवर की दर से 35 रन जोड़े। न्यूजीलैंड ने यंग और मार्क चैपमैन (00) के विकेट जल्दी-जल्दी गंवा दिए। निकोल्स के आउट होने से स्कोर तीन विकेट पर विकेट पर 52 रन हो गया। डैरिल मिचेल (28) और लैथम ने चौथे विकेट के लिए 42 रन की साझेदारी की। पांच मैचों की सीरीज का तीसरा मैच वीरवार को गयाना में ही खेला जाएगा।

यूथ हॉकी5एस एशिया कप के लिए भारतीय पुरुष-महिला टीमों का ऐलान

एजेंसी, नई दिल्ली

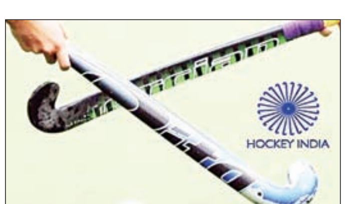

हॉकी इंडिया ने 20 से 25 जुलाई तक ओमान के मस्कट में होने वाली पहली यूथ हॉकी5एस एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय सब-जूनियर पुरुष और महिला टीमों की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट पहली बार आयोजित हो रहे एफआईएच अंडर-18 यूथ हॉकी5एस विश्व कप का एशियाई क्वालिफायर भी है।

पुरुष वर्ग में भारत के साथ मेजबान ओमान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब और बांग्लादेश हिस्सा लेंगे। महिला वर्ग में भारत, पाकिस्तान, ओमान, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान की टीमें चुनौती पेश करेंगी।

महिला टीम की कप्तानी स्वीटी कुजूर करेंगी। टीम में गोलकीपर खिली कुमारी और महक परिहार, डिफेंस में नीलम टोपनो और किरण एक्का, जबकि मिडफील्ड में दिया, पुष्पा मांझी और श्रुति कुमारी को जगह मिली है। आक्रमण की जिम्मेदारी नौशीन नाज, संदीपा कुमारी और कप्तान स्वीटी संभालेंगी। पुरुष टीम की कमान केतन कुशवाहा के हाथों में होगी। टीम में गोलकीपर सावन कुमार और आयुष रजक, डिफेंस में करण गौतम और आशीष तानी पुरती, मिडफील्ड में राहुल यादव और रोमित पाल, जबकि फॉरवर्ड लाइन में केतन, प्रह्लाद राजभर, अर्शदीप सिंह और शाहरुख अली शामिल हैं। महिला टीम की कोच रानी और पुरुष टीम के कोच सरदार सिंह ने विश्वास जताया कि युवा खिलाड़ी हॉकी5एस के तेज रफ्तार प्रारूप में दमदार प्रदर्शन करते हुए अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी छाप छोड़ेंगे।

ब्रिटेन में मंदिर की जगह मुस्लिमों को बेचने पर विवाद, हिंदू समाज पहुंचा हाईकोर्ट

एजेंसी, लंदन। लंदन से 120 किमी दूर पीटरबरो में 40 साल पुराने मंदिर और कम्युनिटी सेंटर की बिक्री को पर विवाद हो गया है। पीटरबरो सिटी काउंसिल ने न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स को नीलामी के बाद एक मुस्लिम संस्था, यूनाइटेड किंगडम इस्लामिक मिशन, को बेचने का फैसला किया है। इसी परिसर में भारत हिंदू समाज का मंदिर चलता है, जो शहर और आसपास रहने वाले हजारों हिंदुओं का प्रमुख पूजा और सांस्कृतिक केंद्र है। फैसले से नाराज भारत हिंदू समाज ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बिक्री प्रक्रिया को चुनौती दी है।

भारत हिंदू समाज संगठन का आरोप है कि काउंसिल ने मंदिर की करीब 40 साल पुरानी धार्मिक और सामुदायिक भूमिका को नजरअंदाज किया। नीलामी के मूल्यांकन में भी गंभीर खामियां रहीं। बता दें कि फरवरी 2026 में हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए काउंसिल को बिक्री पूरी करने जैसे किसी भी कदम से रोक दिया था। अब न्यायिक समीक्षा में यह जांच हो रही है कि फैसला लेने की प्रक्रिया कानून के मुताबिक थी या नहीं। मंदिर प्रबंधन ने साफ किया है कि उसका विरोध मुस्लिम संस्था से नहीं, बल्कि काउंसिल के फैसले और प्रक्रिया से है। अब कोर्ट जांच करेगा कि संपत्ति बेचने का फैसला कानून और समानता के नियमों के मुताबिक लिया गया था या नहीं। भारत हिंदू समाज का कहना है कि पीटरबरो का यह मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि इलाके के 4,000 हिंदुओं का एकमात्र सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र भी है। यदि यह परिसर बंद होता है, तो हिंदुओं को पूजा-अर्चना व त्योहारों के लिए निकटतम मंदिर (कैंब्रिज-56 किमी) या (लेस्टर-64 किमी) का रुख करना पड़ेगा।

वियतनाम नौका हादसा: चेन्नई लाए गए दो मृतकों के पार्थिव शरीर

एजेंसी, चेन्नई

वियतनाम में हुए नौका हादसे में जान गंवाने वाले तमिलनाडु के दो लोगों के पार्थिव शरीर मंगलवार सुबह चेन्नई पहुंचे। तिरुवन्नामलाई निवासी रविशंकर और वेल्लोर निवासी विनय कुमार के शवों पर टीवीके विधायक विनोद कन्नन ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिजनों को सांत्वना दी। हादसा उस समय हुआ, जब एक मोबाइल कंपनी की ओर से आयोजित पर्यटन एवं व्यावसायिक यात्रा के दौरान भारतीय प्रतिभागियों को नौका से एक द्वीप ले जाया जा रहा था। अचानक नौका पलटने से 15 भारतीयों की मौत हो गई। इनमें तमिलनाडु के 10, आंध्र प्रदेश के तीन और केरल के दो लोग शामिल हैं।

भारतीय दूतावास और तमिलनाडु सरकार के प्रयासों से सभी मृतकों के पार्थिव शरीर सोमवार रात विशेष विमान से मुंबई लाए गए। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद राज्यों के अधिकारियों को शव सौंपे गए।

मंगलवार सुबह रविशंकर और विनय कुमार के पार्थिव शरीर चेन्नई पहुंचे। विनय कुमार के परिजन शव लेने हवाई अड्डे पहुंचे, जबकि रविशंकर के परिजन नहीं पहुंच सके, जिसके बाद जिला प्रशासन ने शव को तिरुवन्नामलाई भेजने की व्यवस्था की।

अधिकारियों के अनुसार चेन्नई और तिरुवल्लूर के दो अन्य मृतकों के पार्थिव शरीर भी चेन्नई लाए जाएंगे, जबकि छह अन्य शव कोयंबटूर के रास्ते उनके गृह जिलों तक पहुंचाए जाएंगे। मृतकों के परिजनों ने सरकार और अधिकारियों की सहायता के लिए आभार जताया।

काली गंडकी और सेती नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्शन बंद

नेपाल में बाढ़ से जलमग्न हुई विश्व की सबसे बड़ी शालिग्राम शिला

एजेंसी, काठमांडू

नेपाल में लगातार दो दिन से हो रही बारिश ने जनजीवन के साथ धार्मिक स्थलों को भी प्रभावित किया है। पर्वत, स्याङ्जा और गुल्मी जिलों के संगम पर स्थित दुनिया की सबसे बड़ी शालिग्राम शिला काली गण्डकी और सेती नदी के उफान के कारण पूरी तरह जलमग्न हो गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के प्रवेश और दर्शन पर फिलहाल रोक लगा दी है।

शालिग्राम विद्याश्रम के संरक्षक कुलराज तिवारी ने बताया कि बढ़ते जलस्तर के कारण शिला तक जाने वाला मार्ग, परिक्रमा स्थल और सत्तल भी पानी में डूब गए हैं। सुरक्षा कारणों से पुजारियों और सेवा में लगे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज बहाव से शिला के आसपास की सुरक्षा संरचनाएं, तटबंध और गेबियन जाल भी जलमग्न हो गए हैं। हालांकि फिलहाल आसपास की बस्तियों को तत्काल खतरा नहीं है, लेकिन सेतीबेनी बाजार में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि काली गंडकी 'ए' जलविद्युत परियोजना के बांध के कारण हर वर्ष बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। करीब 200 व्यापारी और स्थानीय निवासी संभावित जलभराव को लेकर चिंतित हैं। जनप्रतिनिधियों ने शालिग्राम शिला की सुरक्षा के लिए नदी के प्रवाह का वैज्ञानिक समाधान निकालने की मांग की है।

पर्वत जिला पुलिस ने लगातार बारिश के बीच नदियों और नालों के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने तथा भूस्खलन और बाढ़ के खतरे को देखते हुए अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की है।

हरियाणा और आंध्र प्रदेश की एसआईआर तिथियों में बदलाव

एजेंसी, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश से जुड़ी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ी कुछ तिथियों में बदलाव किया है। हालांकि दोनों राज्यों में मसौदा और अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित किए जाने की तिथियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

चुनाव आयोग ने इस संबंध में दोनों राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने उनकी ओर से प्राप्त अनुरोध की जानकारी देते हुए नई तिथियां घोषित की है। इसके अनुसार अब बूथ स्तर के अधिकारियों की घर-घर जाने की तिथियां 15 जून से बढ़कर 24 जुलाई कर दी गई है। मतदाता केंद्रों की पुनर्व्यवस्था 24 जुलाई तक पूरी की जाएगी और 31 जुलाई तक मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसके अलावा 31 जुलाई से 30 अगस्त के बीच में दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं। 31 जुलाई से 28 सितंबर तक दावों का निस्तारण किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 3 अक्तूबर को प्रकाशित की जाएगी।

सेंसेक्स 561 अंक गिरा निफ्टी 24,052 पर बंद

एजेंसी, मुंबई

शेयर बाजार में 14 जुलाई मंगलवार को गिरावट रही। सेंसेक्स 561 अंक की गिरावट के साथ 77,055 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 159 अंक की गिरावट रही, ये 24,052 पर बंद हुआ। ऑटो, आईटी, रियल्टी और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा बिकवाली रही। वहीं फार्मा, हेल्थ केयर और मेटल में ज्यादा खरीदारी रही।

कच्चे तेल की कीमतें 2 प्रतिशत चढ़कर दोबारा 85 डॉलर के करीब पहुंच गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान के साथ हुआ समझौता अब खत्म हो चुका है। इससे कच्चे तेल के दाम में फिर से तेजी देखने को मिल रही है।

सोना 476 रुपए घटा और चांदी 2.19 लाख रुपए किलो पर पहुंची

एजेंसी, नई दिल्ली। सोने के दाम में आज यानी 14 जुलाई को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 476 रुपए घटकर 1.42 लाख रुपए पर आ गया है। वहीं, एक किलो चांदी 849 रुपए बढ़कर 2.19 लाख रुपए पर पहुंच गई है। इस साल सोने-चांदी की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 31 दिसंबर 2025 को सोने के दाम 1.33 लाख रुपए थे, जो 29 जनवरी को बढ़कर 1.76 लाख रुपए के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए थे। तब से अब तक सोना 34 हजार रुपए सस्ता हो चुका है।

जम्मू-कश्मीर के सांबा में खेत से मिला ड्रोन

एजेंसी, सांबा। जम्मू-कश्मीर के सांबा में एक ड्रोन मिला है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को सांबा जिले में एक खेत से ड्रोन मिला। यह ड्रोन चक सलारिया के एक निवासी को देवक के पास खेत में पड़ा मिला। उन्होंने सुबह इसे देखा था। उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति ने तुरंत पास की आर्मी यूनिट को सूचना दी और इसके बाद ड्रोन को जब्त कर लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि ड्रोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह कहां से आया है। इसकी तकनीकी खासियत क्या है और क्या इसका इस्तेमाल सीमा पार की किसी गतिविधि के लिए किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि सेना ने तुरंत अपना एंटी-ड्रोन प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया और संदिग्ध ड्रोन के खिलाफ जैमिंग की कार्रवाई शुरू की।